भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ओड़िशा राज्य कमेटी का मुखपत्र

जनसंग्राम

बुलेटिन:2,दिसंबर 2013, सहयोग राशि:1/-

भारत के जनयुध्द के समर्थन व एकजुटता में उठ रही अंतर्राष्ट्रीय आवाजों को 'जनसंग्राम' का लाल सलाम!

आज भारत के शोषक–शासक वर्ग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साम्राज्यवादी लुटेरे शासक वर्ग भी भारत सहित दुनिया के तमाम राष्ट्र मुक्ति, जनवादी व क्रांतिकारी आंदोलनों के दमन के लिए एकजुटता के साथ पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए भी शोसक–शासक वर्ग एड़ी–चौटी का जोर लगाए हुए हैं। आपरेशन ग्रीनहंट चला कर तमाम जन आंदोलनों का गला घोटा जा रहा है। आदिवासी इलाकों में जहां पर जनता अपनी जल–जंगल–जमीन और अस्मिता व अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है हर रोज उस पर जुलूम ढाये जा रहे हैं। वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में हजारों आदिवासी जनता सशस्त्र संघर्ष के जरिये नव जनवादी क्रांति के लिए जनयुद्ध को छेड़े हुए है। हजारों क्रांतिकारी अपना बलिदान दे चुके हैं। चल रहे जनयुद्ध के समर्थन में दुनिया भर की क्रांतिकारी, माओवादी, जनवादी व प्रगतिशील पार्टियों, ग्रुपों –

भारत के तमाम राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा करो!

25 जनवरी 2014 को एकजुटता व संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाओ!!

भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करो
जल-जंगल-जमीन के लिए संघर्ष तेज करो!
हमारी जमीन को हड़पने की साम्राज्यवादी, दलाल पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों की साजिश को ध्वस्त करो!
भूमि अधिग्रहण नहीं, असली भूमि सुधार ही समय की मांग है!

अप्रैल 2013 को केन्द्रीय कमेटी की ओर से जारी प्रैस स्टेटमेंट

जमीन हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए उत्पादन का प्रमुख जरिया है। जो इसे अपनी माता के सामान मानते हैं क्योंकि जमीन की उपज के सहारे ही किसान पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपना जीवनयापन और पालन पोषणत्र करते हैं। इसी जमीन को चालू संसद सत्र में हमसे छीन लेने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 – एक उपनिवेशिक कानून जिसके 'कानूनी' आड़ में ब्रिटिश राज के दौरान इतिहास के सबसे अमानवीय और क्रूर भूमि अधिग्रहणों में से एक को अंजाम दिया गया। आज इसका सतही परिवर्तन कर एक नया नकाब पहनाया जा रहा है। सतही परिवर्तन इस लिहाज से कि इसका मकसद पहले जैसा ही है – हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का खुला लूट – उस समय उपनिवेशिक शासकों के स्वार्थ के लिए और अब साम्राज्यवादियों के लिए। और यह 'बदलाव' पहनके आएगा 'सही मुआवजा', 'पारदर्शिता', 'पुनर्वास और पुनर्स्थापन' का नया मुखौटा और भूमि अधिग्रहण के पत्थरिला जमीन पर औपनिवेशिक समय में बाकी रह गया जो भी रूकावट हो उसे भी नेस्तनाबूद कर देना। अर्थनीति से जुड़ा देश के सभी कानून जो उपनिवेशिक काल से ही जैसे की तैसे बरकरार रखा गया या 1947 के सत्ता हस्तांरण के बाद कुछ फेरबदल के साथ लागू किया गया वह साम्राज्यवादी ताकतों व भारत के बड़े नौकरशाह पूंजीपतियों के उस दौर के अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलु जरूरतों के मुताबिक था। अभी पेश किए गए भूमि अधिग्रहण

भारत के तमाम राजनीतिक बंदियों को बिनाशर्त रिहा करो!
25 जनवरी 2014 को
एकजुटता व संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाओ!

आज भारत की जेलों में लगभग 10 हजार संदिग्ध माओवादी यातनाएं भोग रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्र मुक्ति आंदोलनों (काश्मीर, मणिपुर आदि), जनवादी आंदोलनों के हजारों बंदी भी जेलों में बंद हैं।

नेतृत्व व कैडर सहित पीएलजीए सदस्यों सहित 90 प्रतिशत के लगभग सभी ग्रामीण आदिवासी हैं, जिन्होंने जबरदस्त परित्याग के खिलाफ हथियार उठा रखे है, वे किसान हैं जिन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों, पारादेशिय निगमों के साथ हुए सरकारी एमओयू व प्राकृतिक संसाधनों की साम्राज्यवादियों द्वारा लूट के खिलाफ हैं, राष्ट्र अल्पसंख्यक संगठनों के कार्यकर्ता हैं जो हिंदू सांप्रदायिक फासीवादी आतंक के खिलाफ हैं, छात्र, बुद्धिजीवि, कलाकार हैं जो आरडीएफ व अन्य जनवादी संगठनों से संबंध रखते हैं, उनका जुर्म ये है कि वह आदिवासियों के पक्ष में खड़े होते हैं।

जेल में बंदियों को कई तरह की यातनाओं, ज्यादतियों, अमानवीय जीवन परिस्थितियों, जमान में देरी, बार–बार जेल बदली, मारपीट, महिलाओं को बलात्कार आदि का शिकार होना पड़ता है। .....

.....भारतीय जनता के मित्रों एकजुटता प्रदर्शित करने वाली ताकतों का आज फौरी कर्तव्य बन जाता है कि उनकी बिना शर्त रिहाई का व उनके मुक्तियुद्ध का समर्थन करें।...

आज भारत के शासक वर्गों ने भारत को 'जन आंदोलन के जेलखाने' के रूप में तब्दील कर दिया है।

हम सभी से आव्हान करते हैं कि बड़े पैमाने पर 25 जनवरी 2014 को राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का आयोजन करें। हर संभव तरीके से – स्ट्रीट एक्शन, प्रचार, जन गोलबंदी, उच्च आयोगों, दफ्तरों, अंतरराष्ट्रीय प्रेस व मानव अधिकार संगठनों के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करें। ऐसे अयोजन हफ्ते भर जारी रखें।

इंटरनेशनल कमेटी टू स्पोर्ट द पीपूल्सवार इन इंडिया

अधिनियम इससे अलग नहीं है। यूपीए–2 की सरकार द्वारा 'विपक्षी पार्टियों' के परोक्ष सहयोग से और कार्पोरेट मीडिया के व्यापक प्रचार के साथ लाया जा रहा बड़े 'सुधार' कार्यक्रमों का ही हिस्सा है, *भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन और उचित मुआवाजे का अधिकार विधेयक* 2012, जो पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की जगह लेने जा रहा है।

साम्राज्यवाद आज गहरी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बढ़ते हुए इस संकट से उभरने के लिए बैचेन वह भारत में उनके सबसे विश्वसनीय दलाल – प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री – के पीट पर उतावले होकर चाबुक चला रहे हैं और साथ में चिल्ला रहे हैं ''तेजी से'', ''और तेजी से''। हांफते हुए तीनों हमें ''आश्वासन दे रहे हैं कि सितम्बर 2012 में घोषित बड़े सुधारों के बाद अब और भी सुधारों को जल्दी ही लागू किया जाएगा। इसी वादे के तहत अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम को संसद नामके ढकोसले के जरिए जनता पर थोपा जा रहा है। जहां एक तरफ यह जमीन हड़पने का सबसे बढ़िया तरीका खोज निकालने के लिए शोषकों के बीच आम सहमति बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे बरसों के कोशिशों का नतीजा है, दूसरी तरफ इसपर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुहर लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश है।

जैसा कि इसका नाम ही सूचित करता है, यह विधेयक लोगों के जमीन को 'विकास' के नाम पर अधिग्रहण करने के लिए काम में लाया जाएगा। वह विकास जो भारत के शोषक वर्गों की भाषा में खदान, बड़े बांध, विशेष आर्थिक जोन, राजमार्ग, हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेल पथ, सैनिक शिविर आदि के समार्थक है। दरअसल 1947 के औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के समय से ही चल रही है (याद कीजिए नेहरू के 'आधुनिक मंदिर' यानी बड़े बांधों के द्वारा लाखों लोगों को विस्थापित किया गया था। जिन्हें आज तक कोई मुआवाजा नहीं मिला।) हालांकि 1991 के बाद पहली पीढ़ी के नई उदारवादी नीतियों को भारत में लागू करने के बाद इसके गति में और तेजी आ गई है। 1947 के बाद का इतिहास दर्शता है कि लगभग बिना मुआवाजा – उपयुक्त मुआवाजा तो दूर की बात – बिना पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता के बिना ही भारत में सरकारी और निजी पूंजी (साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के) द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण विनाश की एक लंबी श्रृखंला है। (दस करोड़ विस्थापित, जिसमें से एक आकलन के मुताबिक केवल 17 से 20 प्रतिशत को ही किसी भी तरह का पुनर्स्थापन या मुआवाजा मिला।) इस विनाश का हिस्सा है भूमि अधिग्रहण की वजह से बड़े संख्या में लोगों की मौत, विस्थापन के खिलाफ और हमारे देश के बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं (जल–जंगल–जमीन, खनिज संपदा आदि) को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करने के विरोध में हुए जन संघर्षों का दमन आदि।

देश की जनता का 'विकास' से मोहभंग हो चुका था। भारत के मानचित्र में लाल निशानों की संख्या – जो भूख हड़ताल से लेकर सशस्त्र संघर्ष तक विभिन्न रूप में तथाकथित विकास की वजह से हुए विस्थापन के खिलाफ जनता के संघर्षों को दर्शता है – देशभर में तेजी से बढ़ने और फैलने लगा। इसकी वजह से विकास के इस विध्वंसी रथ थम गया। यही परिप्रेक्ष्य है 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवाजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक 2012' का, जो अब संसद में पारित होने के लिए तैयार है।

'जन प्रयोजन' (च्नइसपब चनतचवेम) शब्द के दायरा को और व्यापक करते हुए यह विधेयक कृषि, कृषि उत्पाद के प्रोसेसिंग, कूल स्टोरेज, औद्योगिक कारिडोर, खदान, राष्ट्रीय उत्पादन नीति के द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पूंजी निवेश और उत्पादन क्षेत्र तथा कोई भी बुनियादी ढांचागत प्रकल्प जिसे सरकार संसद में पेश करने के बाद अधिसूचित करता है, इन सबके लिए इस विधेयक के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इस तरह यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए बेरोकटोक भूमि अधिग्रहण का राह प्रसस्त कर जो भी नाम मात्र का सम्प्रभुता और आत्मनिर्भरता रह गया था वह भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जमीन पर निर्भर किसानों के अलावा भी हमारे देश में करोड़ों ऐसे भूमिहीन लोग हैं जो अपने रोजी–रोटी के लिए जमीन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भरशील हैं। ऊपजाऊ जमीन के अधिग्रहण के बाद कृषि आधारित उद्योग भी प्रभावित होंगे। यह साफ है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक केवल किसान परिवारों को ही नहीं बल्कि इन उद्योगों पर निर्भर मजदूर परिवारों को भी विघटित करेगा।

निजी कम्पनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले जमीन के 80 प्रतिशत मालिकों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी वाले कम्पनियों के लिए 70 प्रतिशत मालिकों की सहमति लिए जाने का प्रावधान यह भूमि अधिग्रहण विधेयक करता है। लेकिन यह सहमति प्रावधान केवल जमीन के मालिकों तक ही सीमित है, इसमें अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले सभी परिवारों का सहमति लेने का कोई व्यवस्था नहीं है। भूमि अधिग्रहण के इतिहास का निराशाजनक और अन्यायपूर्ण रिकार्ड को देखकर यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस 'सहमति' का क्या हश्र होगा। 80–70 प्रतिशत सहमति क्यों जब यह पूरे 100 प्रतिशत होनी चाहिए? भूमि अधिग्रहणों के परिणामों के बारे में लोग कितना जानकार होंगे? लोगों को गुमराह करने या अंधेरे में रखने के लिए कितने ही दुष्प्रचार किया जाएगा? इस प्रक्रिया में

बल प्रयोग का कितना हिस्सा रहेगा और कितना रहेगा मध्यभोगियों का रिश्वत का हिस्सा? जमीन के लूट प्रतिरोध कर रहे जनता को दमन करने के लिए पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और विशेष बलों के हिंसा का व्यापकता कितना होगा? हर प्रदेश के लोग इन सवालों पर गौर किए हैं और इसके सच्चाई को उजागर किए हैं।

यह विधेयक सरकार को इस तरह के निरंकुश क्षमता देता है कि वह मनमाने ढंग से नहर और जल सिंचन सुविधायुक्त बहु फसलीय कृषि क्षेत्र को भी उस राज्य के विशेषताओं को ध्यान में रखने बहाने अधिग्रहण के लिए अधिसूचित कर सकता है। इसका व्यवहारिक मतलब यही होता है कि सरकार साम्राज्यवादियों – दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों को अपने इच्छा अनुसार ऊपजाऊ बहु फसलीय जमीन हड़पने के लिए सहयोग करेगा। पेसा कानून और वन अधिकार कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए इस विधेयक में उन्हीं ग्रामसभाओं और नगरपालिकाओं में पुनर्संस्थापन के रूपरेखा पर जन सुनवाई करने की प्रावधान है जहां से 25 प्रतिशत से ज्यादा जमीन अधिग्रहण किया जाना है, न कि हरेक प्रभावित ग्रामसभा से। यह विधेयक सरकार को पुनर्संस्थापन और पुनर्वास योजना के घोषणापत्र जारी करने में टालमटोल करने की भी क्षमता देती है।

किसानों को मिलने वाला मुआवाजा (लाखों में) और उनके जमीन को फिर से बेचकर मिलने वाला रकम (करोड़ों में) के बीच का फक्र को देखकर भी अपनी जमीन मुनाफाखोर कम्पनियों को बेचने के लिए मजबूर किसानों की दुर्दशा का अनुमान असानी से लगाया जा सकता है। करोड़पति अरबपति में बदल जाते हैं और एक समय स्वतंत्र किसान बन जाते हैं कंगाल। इस विधेयक बेहद खतरनाक प्रावधान यह है कि अधिग्रहण किया हुआ जमीन अगर पांच साल तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया तो वह जमीन के मालिक के पास वापस न जाकर प्रदेश के भूमि बैंक में जमा होगा। इस प्रावधान की वजह से भारी मात्रा में जमीन अधिग्रहण होगा जिसको बाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हस्तांतरण करने के लिए सरकार के पास पूरा मौका रहेगा।

शहरी इलाकों में गरीबों के साथ–साथ मध्य वर्ग का भी व्यापक स्तर पर विस्थापन एक नियम जैसा बन गया है। शहरी (Land ceiling) कानूनों को दरकिनार कर दिया गया। यह विधेयक लागू हो जाने से व्यापक पैमाने पर गांवों से शहर की तरफ लोगों का पलायन होगा और इसके वजह से पहले से ही विकट शहरी बेरोजगारी की समस्या और भी भयंकर रूप लेगी। यह स्थिति साम्राज्यवादी – दलाल नौकरशाह पूंजीपति गठजोड़ के लिए अनुकूल है क्योंकि वह 2007 के अंत से गहरी आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं जिससे निकलने के लिए उन्हें बेरोजगारों की एक बड़ी फौज की जरूरत है जो मजदूरी के दर को कम से कम स्तर पर कायम रखेगा। फलस्वरूप, यह विधेयक भारत के संविधान में उल्लेखित कई मौलिक अधिकारों का, जैसे रोजगार, जीवन, खाद्य, शिक्षा का अधिकार और यहां तक कि मतदान का अधिकार – जिन अधिकारों के दम भरते संसद में बैठे लुटेरे कभी नहीं थकते – उल्लंघन होने जा रहा है। जमीन पर निर्भर तमाम लोगों के खाद्य और आजिविका के सुरक्षा पर और भी यह विधेयक एक बड़ा हमला है। यह क्षेत्रीय विषमताओं को अमीर और गरीब के बीच व्यवधान को तथा शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच अंतरविरोध को तेज करेगा। यह विधेयक यहां तक कि औपचारिक संसदीय राजनीतिक ढांचा को भी नुकसान पहुंचाएगा और साथ–साथ प्रदेशों के क्षमता को सीमित कर फासीवादी केन्द्रीय सत्ता को मजबूत करेगा।

कांग्रेस पार्टी या इसके नेतृत्व में बहु दलीय गठबंधन 1947 के बाद ज्यादातर समय देश के केंद्र और राज्यों में सत्ता पर रहें हैं। जमीन की लूट का रथ का संचालन कर यही लाखों मजदूरों, किसानों और अन्य शोषित वर्गों तथा शोषित समुदाय जैसे दलित, आदिवासी, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक और पिछड़े क्षेत्रों की जनता को विस्थापित किया है। बाकी संसदीय पार्टियां भी इससे पीछे नहीं हैं। इन सभी पार्टियों को विस्थापित जनता अभियुक्त समझते हैं। साम्राज्यवादी मालिकों की सेवा में एकत्रित संसद की सभी पार्टियां इस विधेयक को पारित करने के लिए जल्द ही आम सहमति में आ गए।

विपक्षी दलों के 'आपत्तियों' का दायरा बहु फसली कृषि जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाने (समाजवादी पार्टी) से लेकर राज्य का भूमि अधिग्रहण में किसी भी तरीके के भूमिका का विरोध (त्रिणमूल कांग्रेस) शामिल है। एनजीओ आपत्ति और सुझाव आजिविका केंद्रित पुनरसंस्थापन और पुनर्वास योजना, भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभाओं की सहमति, प्रकल्प प्रभावित या विस्थापित लोगों के सौ प्रतिशत की सहमति, शहरी विस्थापितों के लिए उपयुक्त पुनर्संस्थापन की व्यवस्था आदि से संबधित है। इन विरोधों से प्रस्तावित विधेयक कुछ बुनियादी खामियां तथा इसके सीमिताएं तो रेखांकित होती है, लेकिन जब पूरी विधेयक ही जन विरोधी हो तो तब उसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करने का मतलब है उसे परोक्ष रूप से मंजूरी देना। सभी सत्ताधारी संसदीय दल जो केन्द्र या राज्य में शासन कर रहे हैं या पहले सत्ता में थे, बड़े पैमाने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन हड़पने के लिए बदनाम हैं। यह पार्टियां भू माफिया का रखरखाव और उनके द्वारा किसानों

सव्यसाची पण्डा द्वारा शासक वर्गों के सुर में सुर मिलाते हुए हमारी पार्टी के खिलाफ लगाए गए तमाम जहरीले, बेबुनियादी और झूठे आरोपों को भाकपा (माओवादी) सिरे से खारिज कर देती है! और गद्दारी के लिए उसका पार्टी से बहिष्कार करती है!

(आनंद)

पीबीएम, सीआरबी सचिव केन्द्रीय कमेटी की ओर से जारी प्रैस स्टेटमेंट

हमारी ओड़िशा सांगठनिक कमेटी (एस. ओ.सी.) के सचिव सव्यसाची पण्डा ने हमारी पार्टी के महासचिव के नाम 16 पृष्ठों वाला पत्र लिखकर 14 मई 2012 को मीडिया में जारी कर दिया। इस पत्र में उसने शासक वर्गों के सुर में सुर मिलाकर भाकपा (माओवादी) और उसकी अगुवाई में जारी क्रांतिकारी आंदोलन पर जहर उगलते हुए कोरी कल्पनाओं से कई बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए। पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की बुरी नीयत से उसने इस पत्र को जारी कर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद तथा सर्वहारा की अगुवा पार्टी से खुद को अलग कर लिया। पार्टी छोड़ने और जनयुद्ध की लाइन व क्रांतिकारी व्यवहार को त्यागने की खुलेआम घोषणा कर उसने अपने नव संशोधनवादी चेहरे को उजागर किया। उसने अत्यंत निंदनीय, नीचतापूर्ण व षड़यंत्रकारी तरीकों से पार्टी, क्रांति, शोषित जनता, खासकर ओड़िशा की शोषित जनता की मुक्ति से जुड़े महान उद्देश्यों के साथ

को, खासकर आदिवासियों और शहरी गरीबों को, बेदखल करने तथा राज्य के दमन तंत्र का इस्तेमाल कर विस्थापन के खिलाफ जनता के प्रतिरोध को रोकने के लिए भी जाने जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि इन पार्टियों में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने जमीन कब्जाकर अपना तिजोरी न भरा हो। और सभी एनजीओ का भूमिका ठीक उसी तरह है जिसके लिए उनको प्रयोग में लाया गया था – यानी समाज में एक सुरक्षा दीवार (Safety valve) का भूमिका जो जनता के समस्याओं के समाधान के नाम पर यह निश्चित करने की कोशिश करते हैं कि देश के किसानों का सबसे बुनियादी मांग – जमीन जोतने वालों का हक – यानी असली भूमि सुधार के मांग पर समाज में सम्पूर्ण चुप्पी कायम रखना।

भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय कमेटी देश की जनता से अपील करती है कि वह इस प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने पर एकत्रित होकर संघर्ष करें। साथ ही, गरीब किसान, मध्यम व धनिक किसानों से लेकर शहरी गरीब तथा मध्य वर्ग तक उन सभी तबके जो इस विधेयक से प्रभावित होंगे, जनता के इस व्यापक हिस्से को भी हम एकताबद्ध होकर जल–जंगल–जमीन पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार के लिए और भूमि अधिग्रहण तथा विस्थापन के खिलाफ संघर्ष तेज करने की गुजारिश करते हैं। हमारी पार्टी फिर से दोहराती है कि असली भूमि सुधार के बगैर 'विकास' का कोई मायने नहीं। भारत एक अर्द्धसामंती–अर्द्धउपनिवेशिक देश है जिसके 70 प्रतिशत जनसंख्या अपने परवरिश के लिए अब भी जमीन पर निर्भर है। लेकिन सही भूमि सुधार लागू करने के बजाए देश लुटेरे शासक वर्ग किसानों के जमीन को विकास के बहाने कौड़ियों के भाव हड़पकर बेशुमार मुनाफा लूट रहे हैं। लाखों के तताद में गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर दिन–ब–दिन कंगाल होते जा रहे हैं। और उनके आत्महत्या की बढ़ती संख्या इस सामग्रिक त्रास्दी का ही एक प्रमुख संकेत है।

साम्राज्यवाद, मुख्यत अमेरिकी साम्राज्यवाद को हमारे देश के सभी क्षेत्रों पर, खासकर अर्थनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र पर बढ़ रहे हस्तक्षेप के साथ–साथ विदेशी सेना का देश में प्रत्यक्ष अवतरण के बिना ही नई उपनिवेशिक शोषण की प्रक्रिया तेज हो रही है। विशेष आर्थिक जोन को देश के कानून व्यवस्था के बाहर रखने का मतलब नाम मात्र सम्प्रभुता का भी मजाक बनने का ही सूचक है। अलग–अलग रूप में बढ़ती हुई नई उपनिवेशिक हस्तक्षेप की परिप्रेक्ष्य में नई जनवादी क्रांति के तहत एक असली राष्ट्रीय क्रांति की अभी सख्त जरूरत है। बड़े जमींदारों के स्वार्थ भी साम्राज्यवादियों और दलाल बड़े पूंजीपतियों से अलग नहीं है। इसलिए हमारी केन्द्रीय कमेटी यह स्पष्ट ऐलान करना चाहती है कि नई जनवादी क्रांति के धुरी के रूप में सशस्त्र कृषि क्रांति ही जनता के इन तीनों दुश्मनों को उखाड़ फेंक कर देश में असली भूमि सुधार, असली लोकतंत्र, आत्मनिर्भरशीलता तथा सम्प्रभुता कायम कर इस विनाशकारी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगायेगी। हम देश की जनता से गोलबंद होकर गद्दारों और साम्राज्यवाद के पालतू कुत्तों – जो संसदीय लोकतंत्र के आड़ में सत्ता में काबिज होकर देश को नीलाम कर रहे हैं – के खिलाफ चल रहे दीर्घकालीन जनयुद्ध को व्यापक और विस्तारित करने की आह्वान करती है ताकि भारत की नईजनवादी क्रांति को अपने मुकाम तक पहुंचाया जा सके।

विश्वासघात कर खुद को गद्दार साबित किया।

सब्यसाची पण्डा ने पहले कुछ समय तक सीपीएम में और उसके बाद सीपीआई (मा.ले.) (लिबरेशन) में काम किया था। बाद में क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित होकर उसने दक्षिणपंथी लिबरेशन पार्टी को छोड़कर 1998 में भाकपा (मा.ले.) (पार्टी यूनिटी) में प्रवेश किया। क्रांतिकारी पार्टियों की एकता से वह भाकपा (मा.ले.) (पीपुल्सवार) और उसके बाद भाकपा (माओवादी) में बना रहा। 2003–05 के बीच ए.ओ.बी. एस. जेड.सी. सदस्य के रूप में, 2005 से ओड़िशा राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य के रूप में और 2008 से उस कमेटी के सचिव के रूप में काम करता रहा। क्रांतिकारी पार्टी में 15 साल के लम्बे अंतराल तक काम करने के बावजूद खुद को एक असली सर्वहारा क्रांतिकारी के रूप में ढालने में वह विफल रहा। उसके क्रांति–विरोधी व अवसरवादी राजनीतिक विचारों, रुझानों और व्यवहार की साथियों, कैडरों और सी.सी. कामरेडों ने कई बार आलोचना की। पिछले दिसम्बर में जब राज्य स्तर का विशेष प्लीनम आयोजित किया गया था, उसमें उसके खिलाफ कई आलोचनाएं उठी थीं। लेकिन उसने उनमें से कुछ को रस्मी तौर पर स्वीकार कर बाकी को टालमटोल कर दिया। एक सच्चे सर्वहारा क्रांतिकारी के तौर पर अपनी गलतियों को ईमानदारी से चिन्हित कर सुधार लेने की बजाए वह एक कायर की तरह क्रांतिकारी आंदोलन से भाग गया।

उसके 16 पृष्ठों वाले पत्र में झूठ, विकृतियां और सच को तोड़ने–मरोड़ने वाले कुतक्र ही थे, जबकि रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस पत्र को उसने ओड़िशा में हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर कर, छिन्न–भिन्न कर, विनाश करने की ही नीयत से लिखा था। यह किसी से छिपी नहीं है कि महान क्रांतिकारी लक्ष्य को समर्पित, असीम कुरबानियों से नहीं डरने वाली, निस्वार्थ रूप से काम करने वाली, देश की मुक्ति के लिए कटिबद्ध और शोषित जनता के लिए आशा की किरण के रूप में हमारी पार्टी को प्राप्त प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर, शासक वर्गों की सेवा में संलग्न होकर अपनी स्वार्थ राजनीति को साधने की बुरी मंशा ही पण्डा के इस पत्र के पीछे निहित थी। इतिहास में ऐसा अक्सर देखा गया है कि शासक वर्ग पण्डा जैसे लोगों को इस भ्रम के साथ सामने लाते हैं कि इससे क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ जारी अपने दुष्प्रचार को वैधता मिल जाएगी। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरूआत से देखा जाए तो दुश्मन ने पण्डा जैसे अवसरवादियों को सामने रखकर इस तरह की कोरी कल्पनाओं के सहारे कामरेड्स चारु मजुमदार, कन्नाई चटर्जी आदि हमारे कई नेताओं पर, पार्टी पर तथा क्रांतिकारी आंदोलन पर कई बार हमले किए थे।

पण्डा द्वारा लगाए गए आरोपों की तह में जाने से पहले हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी समय–समय पर बैठकें, प्लीनम और अधिवेशन चलाती रहती है ताकि अपने कार्याचरण को सुधारा जा सके तथा उसे बेहतर बनाया जा सके। अपनी गलतियों को चिन्हित कर उन्हें आलोचना–आत्मालोचना, समीक्षा और विशेष भूल सुधार अभियानों के जरिए सुधार लेती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह सब जान–समझकर भी पण्डा अपने सोलह पन्नों वाले झूठे आरोपों के साथ सामने आया है तो उसके बुरे मंसूबों को साफ समझा जा सकता है। असल बात यह है कि चूंकि वह इस तरह की प्रक्रिया में भाग लेकर खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया।

हालांकि पण्डा के सड़ांध से भरे आरोपों की फेहरिश्त काफी लम्बी है, लेकिन उनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं –

1. माओवादियों के लिए विवेकहीन हिंसा और बेकसूर लोगों को मारना आम बात बन गया। वे अपने कैडरों को तथा भोलेभाले और बेकसूर पुलिस वालों को अंधाधुंध मार डालने के आदेश देते हैं। 2. पार्टी में तेलुगु और कोया कामरेडों का दबदबा कायम है। 3. माओवादी ही आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। उनसे खाना बनवाते हैं। सामान उठवाते हैं। कार्यकर्ताओं को त्यौहारों पर भी अपने परिवारों से मिलने नहीं देते हैं। माओवादी आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। 4. गणपति आतंक और भय पर आधारित तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं।

अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली जनता पर राजसत्ता अपने पास मौजूद तमाम हथियारों से दमनचक्र चलाती है। अगर यह लड़ाई जनता की मुक्ति के लक्ष्य से, यानी उत्पीड़ित जनता की राजसत्ता को कायम करने के लिए चलती हो तो राजसत्ता उस पर तीखे दमन पर उतारू हो जाती है। उसके पुलिस, अर्द्धसैनिक व फौजी बल आगे रहकर हमला करते हैं, जबकि उसके तमाम दूसरे अंग इस हमले में सुनियोजित, तालमेल के साथ, बेहद क्रूरता व षड़यंत्रकारी तरीकों से भाग लेते हैं। इसलिए इस हिंसा का मुकाबला करने के लिए जनता को सशस्त्र संघर्ष जरूरी हो जाता है। मार्क्सवाद के बारे में एबीसीडी जानने वालों को भी क्रांतिकारी हिंसा से सम्बन्धित इस बुनियादी व प्राथमिक विषय के बारे में जरूर मालूम होगा। जब पण्डा ने दक्षिणपंथी अवसरवादी सीपीआइ (एम.एल.) लिबरेशन पार्टी को छोड़ क्रांतिकारी पार्टी की लाइन को कबूलकर पार्टी में शामिल हुआ था और एकता कांग्रेस की लाइन को मान लिया था, तब उसे इसके बारे में मालूम नहीं था ऐसा तो नहीं हो सकता। चूंकि पण्डा ने खुद को पार्टी से अलग करना चाहा, इसलिए वह

अवसरवादी तरीके से जहर उगल रहा है कि माओवादियों की हिंसा विवेकहीन है और वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इन सबका विरोध करने का दिखावा करते हुए वह यह उम्मीद कर रहा है कि भारतीय राजसत्ता उसके प्रति रहमदिली दिखा दे। जनता को कई प्रकार की हिंसा का शिकार बनाते हुए, उनके जीवन के तमाम पहलुओं को ध्वस्त करते हुए, उनकी हत्याएं करते हुए, बर्बर राजकीय दमन चलाने वाले और उसमें हिस्सा लेने वाले सरकारी सशस्त्र बल व अधिकारी तथा लक्ष्मणानंद, जगबंधु जैसे वर्ग–दुश्मन पण्डा को अब अचानक निर्दोष नजर आ रहे हैं। शासक वर्गों के चरणों पर नतमस्तक होने के लिए वह झूठे इलजाम लगाने के मामले में शत्रु–दुष्प्रचार को भी पीछे छोड़ रहा है।

'ओड़िशा में तेलुगु और कोया कामरेडों का दबदबा चल रहा है' वाला आरोप लगाकर पण्डा 'फूट डालो और राज करो' की उसी घिसी–पिटी व ओछी चाल चल रहा है जोकि दरअसल ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और उनके नक्शेकदम पर चल रहे भारतीय शासक वर्गों की है। दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन के अनुसार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रणनीतिक दृष्टि से बिखरे हुए इलाकों से देशव्यापी स्तर में तथा छोटे इलाकों से व्यापक इलाकों में विस्तार करने के लिए और खुद को छोटी ताकत से एक बड़ी ताकत के रूप में विकसित करते हुए अंततः देशव्यापी पैमाने पर राजसत्ता हासिल करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण हो रहा है। इसके लिए पार्टी रणनीतिक दृष्टि से अपनी ताकतों को शुरू से ही विभिन्न इलाकों में तैनात करके काम कर रही है। स्थानीय स्तर पर जनाधार को बढ़ाते हुए पार्टी व जनसेना को विकसित करते हुए इलाकेवार राजसत्ता की स्थापना कर रही है। इस लाइन पर चलते हुए रणनीतिक तौर पर शक्ति संतुलन में बदलाव लाकर अंततः शहरों को घेरकर देशव्यापी राजसत्ता पर कब्जा करनी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के हर सदस्य को देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने के लिए तैयार रहना होगा। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीयवादी होने के चलते कम्युनिस्टों को दुनिया के किसी भी देश में या क्षेत्र में जाकर वहां की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मुक्ति के लिए काम करने को तैयार रहना चाहिए। भारतीय क्रांति के इतिहास पर नजर डाली जाए तो हम यह समझ सकते हैं कि अपने इलाकों व राज्यों को छोड़कर दूसरे इलाकों व राज्यों में जाने वाले कामरेडों के कड़े प्रयासों के फलस्वरूप ही देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार हो पाया है। इन कामरेडों ने भाषाएं सीखीं। वहां की जनता की संस्कृति का सम्मान किया। उनके साथ एकताबद्ध हुए। नए इलाकों में निर्मित आंदोलनों को ऐसे कामरेडों के सामूहिक परिश्रम के नतीजे के रूप में देखा जा सकता है। पण्डा के संकीर्ण क्षेत्रीयवादी नजरिए के चलते दूसरे राज्यों से आए कामरेडों का ओड़िशा में आकर काम करना उसे कभी रास नहीं आया। ऐसे कामरेडों की निस्वार्थ भावना की प्रशंसा करने की बजाए उसने उनके और ओड़िया कामरेडों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए षड़यंत्रकारी तरीकों व गुटबाजी से ही लगातार काम किया। आंदोलन की जरूरत के अनुसार दूसरे राज्यों से ओड़िशा में काम करने के लिए आने वाले कामरेडों के मामले में उसने क्षेत्रीय अंधराष्ट्रवाद का प्रदर्शन करते हुए नौकरशाहीपूर्ण, गैर–जनवादी व संकीर्ण तरीके से काम किया। वास्तव में ओड़िया जनता और ओड़िया कामरेडों ने उनके लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए आंध्रप्रदेश, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ से आए हुए कामरेडों का खुशी से ही स्वागत किया। इस सच्चाई को स्वीकार किया। हम आशा करते हैं कि पण्डा के साथ कार्यरत चंद कामरेड्स जनयुद्ध की लाइन के बारे में दोबारा चिंतन–मनन कर उसके झूठों को समझ लेंगे और उसकी साजिशों को समझकर उसका पर्दाफाश कर देंगे।

क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आदिवासियों की मुक्ति का लक्ष्य त्याग देने वाले पण्डा 'माओवादियों के हाथों आदिवासियों का शोषण' के बारे में शासक वर्गीय हत्यारों की ही तर्ज पर हमारी पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हुए मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है जोकि उसके छलकपट का साफ सबूत है। पार्टी में रहते समय शारीरक श्रम में कभी भाग न लेने वाले पण्डा की आंखों पर जब शासक वर्गीय चष्मे सज गए, आदिवासी कामरेडों का स्वैच्छिक रूप से, अत्युन्नत क्रांतिकारी चेतना के साथ क्रांति के लिए अपनी सारी शारीरक शक्ति को बाहर लाकर काम करना 'माओवादियों के हाथों शोषण' के रूप में दिखाई दे रहा है। आखिर माओवादी कौन हैं? और आदिवासी कौन हैं? क्या पार्टी में काम करने वाले आदिवासी माओवादी नहीं हैं? क्रांति को छोड़कर शासक वर्गों की वकालत करने पर उतारू ठेठ अवसरवादी पण्डा को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान रोजमर्रा के जीवन में जरूरी व्यक्तिगत श्रम और सामूहिक जीवन में सैन्य, तकनीकी, उत्पादन–विकास, जन कल्याण आदि क्षेत्रों में आवश्यक श्रम, जन आंदोलन में जनता का विभिन्न प्रकार का श्रम माओवादियों द्वारा आदिवासी जनता के शोषण के रूप में दिखाई देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वहारा पार्टी में हरेक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना–अपना काम कर लेते हैं। भार उठाते हैं। बीमार, शारीरक रूप से कमजोर और विशेष कामों में लगे साथियों की मदद दूसरे लोग करते हैं। दरअसल जनसेना प्रधान रूप से युद्ध का संचालन करते हुए अपने लिए जरूरी रसोई, भार उठाना आदि काम खुद ही कर लेती है। राष्ट्रीयता, लिंग, क्षेत्र

आदि का फक्र किए बगैर हरेक को जनयुद्ध के अंतर्गत उपरोक्त काम करने ही होंगे। देश के विभिन्न गुरिल्ला जोनों में यही चलता आ रहा है। और चल रहा है। दरअसल हमारी पार्टी की संस्कृति जनवादी व समाजवादी संस्कृति है जिसमें स्त्री–पुरुषों के बीच, पढ़े–लिखे व अनपढ़ों के बीच तथा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी के प्रति आदिवासियों के आकर्षित होने का यह एक अहम कारण है। हमारी पार्टी इसी संस्कृति को बड़े पैमाने पर, लाखों लोगों के बीच ले जा रही है।

राजसत्ता यह आरोप बार–बार लगा रही है कि माओवादी अपनी पार्टी में शामिल महिलाओं/आदिवासी महिलाओं को अत्याचाार व यौन प्रताड़ना का शिकार बनाते हैं। गद्दार बन चुके पण्डा ने भी माओवादियों पर शासक वर्गों की तरह बेहद नीचतापूर्ण तरीके से हमला किया है तो इसमें अश्चर्य क्या है? अतीत में हमारी पार्टी ने हर बार जो जवाब दिया आज भी इस पर हमारा वही जवाब है। हालांकि इस आरोप का अत्युत्तम जवाब दे रही हैं वे सैकड़ों महिलाएं जो हमारी पार्टी में भर्ती हो रही हैं, वे हजारों–लाखों महिलाएं जो क्रांतिकारी महिला संगठनों में सदस्यता ले रही हैं, वे महिलाएं जो आंदोलन के इलाकों में मौजूद हैं और वे सैकड़ों महिला साथी जो नक्सलबाड़ी के दिनों से लेकर पिछले 45 सालों से शोषित जनता की मुक्ति के लिए अपने प्राणों को कुरबान कर चुकी हैं।

1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद, आंदोलन के अब तक के 90 से ज्यादा सालों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 25 बरसों में जनता, जन संस्कृति और जन जीवन के तमाम पहलुओं के साथ जितना ज्यादा एकताबद्ध हुई, उतना पहले कभी नहीं हुई थी। न सिर्फ एकताबद्ध हुई, बल्कि वह जन जीवन के राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलुओं में से तमाम प्रगतिशील अंशों को ऊंचा उठाकर, उन्हें अपने अंदर समाहित कर, उनका और ज्यादा क्रांतिकरण कर रही है। पण्डा के इस आरोप को कि त्यौहारों पर घर देखने को इच्छुक कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाता है, क्रांतिकारी जनता कतई विश्वास नहीं करेगी। जिन लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन के साथ ज्यादा परिचय नहीं है, ऐसे लोगों को उस पर घृणा की भावना पैदा करने की नीयत से ही वह इस प्रकार अवसरवादी तरीके से हमला कर रहा है।

यह आरोप कि गणपति आतंक और भय पर आधारित तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, इतना हास्यास्पद है कि दरअसल इसके लिए स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है। भाकपा (माओवादी) किसी बुर्जुआई पार्टी जैसी कतई नहीं है। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मौजूदा अर्द्ध सामंती व अर्द्ध औपनिवेशिक राजसत्ता को क्रांतिकारी हिंसा के जरिए ध्वस्त कर, नई जनवादी क्रांतिकारी सत्ता, यानी सर्वहारा की अगुवाई में मजदूर–किसान एकता की बुनियाद पर आधारित चार वर्गों – मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्गों की जनवादी तानाशाही की स्थापना हमारा फौरी लक्ष्य है, जबकि बाद में समाजवाद और साम्यवाद लाना अंतिम लक्ष्य है। ऐसा भी नहीं है कि यह सब पण्डा को मालूम नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की आड़ में देश में मनमानी तरीके से तानाशाही चलाने वाली दलाल नौकरशाही बुर्जुआ व सामंती वर्गों की निरंकुश व्यवस्था से, जिसकी साम्राज्यवादियों से सांठगांठ है, समझौता करके उसमें अपनी जगह पक्की करने के इरादे से ही पण्डा कामरेड गणपति और हमारी पार्टी पर गलत आरोप लगा रहा है।

दरअसल पण्डा खुद ही ओड़िशा में अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। राज्य की विशेष प्लीनम में की गई समीक्षाओं और फैसलों को देखने के बाद उसने समझ लिया था कि पार्टी के कैडर उससे दबकर रहने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने उसके नौकरशाहाना व्यवहार और अन्य राज्यों के साथियों के प्रति गैर–जनवादी व संकीर्णतावादी रवैये की आलोचना की। यह पहचानते हुए कि नौकरशाहाना व्यवहार को जारी रखना संभव नहीं है, इस अवसरवादी ने पार्टी छोड़ने का फैसला लेकर तबसे अपनी पूर्व तैयारियों में तेजी लाई।

दरअसल, राज्य स्तरीय प्लीनम के आयोजन के बाद से उसने ओड़िशा राज्य प्रभारी सी.सी. कामरेड से संपर्क करना ही छोड़ दिया। तबसे, करीब छह महीनों तक वह अपने बयानों और साक्षात्कारों में लगातार पार्टी पर जहर उगलता रहा। इससे पार्टी में राजनीतिक व सांगठनिक समस्याएं उत्पन्न हुईं जिससे ओड़िशा के आंदोलन को तीव्र नुकसान पहुंचा। क्योंकि बहुत से मामलों में उसका रवैया विशेष प्लीनम के फैसलों, पार्टी लाइन और नीतियों के खिलाफ रहा। उसकी अगुवाई में जब इटली के सैलानियों को बंदी बनाया गया था, तब वह निहायत अवसरवादी तरीकों पर उतर आया। उसने समूचे ओड़िशा राज्य में एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा की। ओड़िशा और उसके सीमावर्ती इलाकों के उल्लेखनीय हिस्से में जब दो–दो सीमावर्ती कमेटियां काम कर रही हों, तब उसका इस तरह घोषणा करना अनुचित था। इस तरह बाकी दो कमेटियों को आदेश देने का उसे कोई अधिकार भी नहीं था। उसके द्वारा एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा के बाद जब एओबी के साथियों ने एक विधायक को बंदी बनाया और एक एसआई को गोली मार दी, तब उसने न सिर्फ एओबी के साथियों की खुलेआम आलोचना की, बल्कि यह तक कह दिया कि उनके लिए मारना फैशन बन गया।

ओड़िशा एसओसी के दायरे में समूची पार्टी द्वारा की गई समीक्षाओं को ताक पर रखकर पण्डा ने यह घोषणा की कि लक्ष्मणानंद, जगबंधु जैसे वर्ग–दुश्मनों का सफाया गलत था। दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर उसने कामरेड निखिल के नाम से बयान जारी करते हुए अलग–अलग समुदायों व अलग–अलग राज्यों से आए हुए कामरेडों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिशें करते हुए एक जहरीली मुहिम शुरू कर दी। जब मीडिया में लगातार खबरें आने लगी थीं कि पण्डा पार्टी छोड़ने वाला है और एक नया ग्रुप बनाने वाला है, लगातार मीडिया के संपर्क में रहते हुए भी पण्डा की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आना महज इत्तेफाक नहीं था। साफ जाहिर है कि विशेष प्लीनम के बाद ही उसने पार्टी छोड़ने की योजना बनाकर खुलेआम अवसरवादी तरीकों और विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। अपने पतन की पराकाष्ठा के रूप में उसने आखिरकार पार्टी छोड़ दिया।

ओड़िशा आंदोलन के दौरान सामने आई राजनीतिक समस्याओं पर दक्षिणपंथी अवसरवादी रुख अपनाते रहे पण्डा का पतन आखिर में संशोधनवाद के स्तर पर हुआ जो दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन को ठुकरा देता है। उसके अंदर मौजूद संकीर्णतावादी, अतिजनवादी, अनुशासनहीन, गुटीय, गैर–सांगठनिक, पदलोलुपतावादी, नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागने आदि रुझानों ने ओड़िशा में पार्टी और आंदोलन को बेहद नुकसान पहुंचाया। वह हमेशा सुखी जीवन की तलाश में रहता था। उसके अंदर मेहनती स्वभाव का बिल्कुल अभाव था। संगठित होने के क्रम से गुजर रही ओड़िशा राज्य पार्टी को हुए गंभीर नुकसान की स्थिति और सी.सी. पर दुश्मन का हमला केन्द्रित होने से जो गंभीर नुकसान पहुंचा था उसका इस अवसरवादी ने फायदा उठाया ताकि राज्य में विघटनकारी गतिविधियां जारी रखी जा सकें। इन सबकी जड़ उसके अंदर गहराई से मौजूद व्यक्तिवाद में है जो व्यक्ति को केन्द्र में रखता है। इसके अलावा, क्रांतिकारी आंदोलन पर साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सम्पूर्ण सहयोग से भारत के शासक वर्गों द्वारा जारी प्रति–क्रांतिकारी युद्ध में 2009 के मध्य से आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से खासा बदलाव आ गया। तबसे हमारे आंदोलन के खिलाफ जारी देशव्यापी व चौतरफा भारी सैनिक हमले की पृष्ठभूमि में ही पण्डा के पतन व विश्वासघात को देखना होगा। इस हमले में पार्टी को देश भर में तीखे नुकसान हुए हैं। हालांकि ओड़िशा में आंदोलन अभी भी कमजोर ही है, लेकिन वह भी इस हमले का बुरी तरह शिकार हो रहा है। खासकर 2010 के आखिर से उसे गंभीर नुकसान झेलने पड़े। यह हमला और भी तीखा होने वाला है। भारत जैसे पिछड़े देशों की प्राकृतिक सम्पदाओं और संसाधनों को लूटने के रास्ते में बाधा बनने वाले संगठनों और लोगों को कुचलने के पीछे अहम कारण बहुराष्ट्रीय व देश की दलाल कार्पोरेट कम्पनियों के हित ही है। विश्व अर्थव्यवस्था को घेरने वाला वित्तीय संकट और जितना तीखा होगा, क्रांतिकारी पार्टी, उसके नेतृत्व, आंदोलन व शोषित जनता पर वे अपना हमला उतना ही तेज करेंगे ताकि वे खुद को उससे उबार सके। इस पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी पार्टी के नेताओं के लिए आंदोलन को चलाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। पार्टी के सच्चे नेता देश और दुनिया में छाई हुई बेहतरीन क्रांतिकारी परिस्थिति का फायदा उठाकर जनता को राजनीतिक रूप से तैयार करते हुए, जनयुद्ध को विकसित करने व क्रांति के पक्ष में बदलने की ही कोशिश करेंगे। इसके लिए क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता, दृढ़ इरादे, साहस के साथ फैसले लेना, पार्टी, जनसेना व जनता को एक सूत्र में बांधकर चलाना, बलिदानी भावना आदि जरूरी होते हैं। क्रांति की जरूरतों और कार्यभारों के मुताबिक खुद को और पार्टी को ढालने के लिए फौलादी संकल्प जरूरी हो जाता है। ऐसे लक्षणों के अभाव में कोई भी नेता क्रांति का नेतृत्व करने में या तो विफल हो जाएगा या फिर अक्षम हो जाएगा। ऐसे लोगों में से कुछ जंगे मैदान को छोड़कर कायरों की तरह भाग खड़े हो जाएंगे या फिर दुश्मन की शरण में चले जाएंगे। इस सच्चाई को छुपाते हुए ऐसे अवसरवादी और क्रांति–द्रोही शासक वर्गों का बचाव करते हुए पार्टी और पार्टी–नेतृत्व पर अनाप–शनाप आरोप लगाते रहते हैं। अतीत में न सिर्फ हमारी पार्टी के इतिहास में, बल्कि विभिन्न देशों की क्रांतियों में भी ऐसे गद्दार रहे थे। ऐसे लोगों में पण्डा आखिरी व्यक्ति भी नहीं होगा।

उपरोक्त सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारी केन्द्रीय कमेटी ने पण्डा पर आए तमाम आरोपों को उसके सामने राजनीतिक रूप से पेश कर, उसे गलतियों से बाहर आने का मौका देते हुए, सुधारने की विशेष कोशिश शुरू की। लेकिन राज्य की विशेष प्लीनम के बाद से उसने सम्बन्धित सी.सी. कामरेड से पूरी तरह सम्बन्ध तोड़ लिया और पार्टी, आंदोलन व नेतृत्व पर लगातार खुला हमला करता रहा। इन सबकी पराकाष्ठा के रूप में मीडिया को यह जहरीला पत्र जारी करके खुद को गद्दारों में शामिल कर लिया। इसलिए हमारी केन्द्रीय कमेटी सब्यसाची पण्डा को पार्टी से बहिष्कार करती है। और हम इसकी सूचना ओड़िशा में मौजूद हमारी पार्टी के तमाम साथियों, समूची क्रांतिकारी जनता और देश के तमाम क्रांतिकारी खेमे को देते हैं।

ओड़िशा के साथियों, जन संगठनों और क्रांतिकारी व जनवादी जनता से हम अपील करते हैं कि वे हमारी पार्टी, आंदोलन और नेतृत्व के प्रति पण्डा द्वारा अपनाए गए शत्रुतापूर्ण व अवसरवादी रुख तथा शासक वर्ग–अनुकूल व

पुव्वार फासीवादी हत्याकांड का खंडन करो!
आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व ओड़िशा के पुलिस, विशेष कमांडो/ग्रेहाउंड्स व केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों द्वारा सेंट्रल रीजियन में चलाए जा रहे हत्याकांडों और विध्वंस के खिलाफ
२७ अप्रैल को सेंट्रल रीजियन बंद सफल बनाओ!

प्रताप
प्रवक्ता सेंट्रल रीजनल ब्यूरो द्वारा 19 अप्रैल 2013 को जारी प्रेस विज्ञप्ति

16 अप्रैल 2013 को आंध्रप्रदेश की सीमा पर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला, कोंटा ब्लॉक के पुव्वार गांव में एपी ग्रेहाउण्ड्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपी–कोबरा बलों द्वारा खम्मम एसपी रंगनाथ और कोत्तागूडेम ओ नेतृत्व मे, मुखबिरां से मिली पक्की सू साथ हमला कर उत्तर तेलगाना के पांच मि हला कामरेडों समेत नौ कामरेडों की हत्या कर दी। इस हमले में कामरेड्स मर्री रवि उर्फ सुधाकर (उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य), गुगलोत

जनविरोधी रुख का खण्डन करें। उसे, उसकी सड़ी–गली नव संशोधनवादी राजनीति और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को ठुकरा दें। इतिहास ने कई बार साबित किया है कि जो खुद ही खुद को बेजोड़ क्रांतिकारी नायक के रूप में दिखाते हैं या फिर शासक वर्गों द्वारा इस तरह फोकस किए जाते हैं, ऐसे गद्दार आखिरकार इतिहास के कूड़ेदान में ही फेंक दिए जाएंगे जबकि सच्ची क्रांतिकारी पार्टी, उसके नेता और उसकी अगुवाई में क्रांतिकारी जनता अनुपम साहस के साथ, भारी तूफानों से होकर अंतिम जीत की ओर अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे। जनता ही इतिहास का निर्माता है, पण्डा जैसे नकली क्रांतिकारी नहीं। हमारी पार्टी को सम्पूर्ण विश्वास है कि ओड़िशा का सिक्का चलाते हुए शासक वर्गों की चरण–सेवा में जी–जान से जुट जाने वाले पण्डा जैसे गद्दारों को ओड़िशा की क्रांतिकारी जनता जरूर ठुकरा देगी तथा ओड़िशा के साथी व व्यापक उत्पीड़ित जनता भाकपा (माओवादी) की अगुवाई में क्रांति के पथ पर अग्रसर होंगे।

लक्ष्मी उर्फ पुष्पा (केकेडब्ल्यू डीवीसीएम), वेट्टि नरसक्का उर्फ सबिता (एटूरनागारम एसी सचिव), दुर्गम राजू (एसीएम), रीना (एसीएम), वेट्टि रामक्का उर्फ ऊर्मिला (एसीएम), मद्दि सीता उर्फ नवता (डीवीसीएम की गार्ड), मड़काम भीमा उर्फ अजय (डीवीसीएम का गार्ड) और अरलि वेंकटि उर्फ गौतम (एसजेडसीएम का गार्ड) शहीद हो गए। सेंट्रल रीजनल ब्यूरो इन तमाम शहीदों को लाल–लाल जोहार पेश करते हुए उनके सपनों को साकार करने की शपथ लेता है। एपी ग्रेहाउण्ड्स पिछले कुछ सालों से दण्डकारण्य में घुसकर इस तरह के हत्याकाण्डों और तबाही को अंजाम देते आ रहे हैं। 2008 में हुए कंचाल हत्याकाण्ड के बाद यह और एक भारी हत्याकाण्ड है। हमारी पार्टी इस हत्याकाण्ड की कड़ी निंदा व खण्डन करते हुए जनता और पीएलजीए का आह्वान करती है कि पुलिस, ग्रेहाउण्ड्स आर अर्द्धसैनिक बलों के हमलों का प्रतिरोध किया जाए।

पिछले चार महीनों से दण्डकारण्य, आंध्र–ओड़िशा सीमांत जोन, उत्तर तेलंगाना व गोंदिया (महाराष्ट्र) के इलाके पुलिस, ग्रेहाउण्ड्स और अर्द्धसैनिक बलों के लौह पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। हर दिन, हर कोने से सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाए जा रहे हत्याकाण्डों, फर्जी मुठभेड़ों, विध्वंस और आतंक से जुड़ी खबरें आ रही हैं। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने वाले भारत के शोषक शासक वर्ग सदियों से अत्यंत क्रूरतापूर्ण शोषण, उत्पीड़न, दमन, अन्याय, भेदभाव और उपेक्षा की शिकार जनता पर, खासकर आदिवासियों पर अभूतपूर्व पाशविकता बरत रहे हैं। दण्डकारण्य में पिछले दस दिनों के दरमियान कम से कम 20 क्रांतिकारियों और आम जनता को फर्जी मुठभेड़ों में कत्ल कर दिया गया। खासकर आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में विभिन्न राज्यों के पुलिस व कमाण्डो बल और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल संयुक्त आपरेशन चलाकर मनमानी मुठभेड़ों, हत्याकाण्डों और विध्वंसकाण्ड को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढके सुकमा में और आंध्रप्रदेश के करीमनगर जिले के काटारम में चार राज्यों के पुलिस के आला अधिकारियों ने विशैठकें कर इन ताजा हमलो की साजिश रची। वायु से हेलिकाप्टरां और मानवरहित विमानों के प्रयोग को बढ़ाने के अलावा वायुसेना के जरिए हवाई हमले करने की योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सेना के प्रशिक्षण के बहाने माड़ क्षेत्र पर कब्जा कर क्रमगत रूप से जनता के खिलाफ जारी युद्ध में सेना की तैनाती करने की योजना भी उनके एजेंडे में है। इन हमलों के जरिए जनता द्वारा निर्मित हो रही नई राजसत्ता को, उसकी गुरिल्ला सेना को और उसकी पार्टी को जड़ से खत्म करने पर जोर लगा रहे हैं। हाल में हुई कुछ अन्य घटनाएं इस बात का सबूत हैं।

➢ 12 अप्रैल को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला, धनोरा तहसील के सिंदेसूर गांव में जनता जब गुरिल्ला सैनिकों को भोजन की व्यवस्था कर रही थी तब पुलिस ने अचानक हमला किया जिसमें कामरेड कैलास उर्फ पंकज (एसीएम) और कामरेड चम्पा नुरोटी (कम्पनी–4 की सदस्या) के अलावा गांव की दो निहत्थी महिलाएं वसंती कोवासी और संगीता आत्रम को गोली मार दी गई।

➢ 4 अप्रैल को इसी जिले के भामरागढ़ तहसील, भटपार गांव में जनता के साथ बैठक करने वाले गुरिल्ला दस्ते पर सी–60 कमाण्डों ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें कामरेड लक्ष्मण (एसीएम), मिलिशिया सदस्य कामरेड प्रकाश और सुधाकर के अलावा अलावा गांव की अम्मी और सुनिता नामक दो किशोरियों की हत्या की गई।

➢ 2 अप्रैल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला, माड़ क्षेत्र ग्राम कोंगे में हमला कर जगल में शिकार पर गए छह भालेभाले आदिवासियों को पकड़कर ले जाया गया और उन्हें 'इनामी नक्सली' के रूप में पेश किया गया। इसके पहले गांव के अंदर घुसकर डकैतों की तरह लूटपाट और तबाही मचाई।

➢ 14 मार्च को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला, खोब्रामेण्डा गांव के जंगलों में पार्टी नेतृत्व का सफाया करने के लक्ष्य से भारी हमला किया गया।

➢ 9 मार्च को बीजापुर जिला, कंचाल गांव के पास एपी ग्रेहाउण्ड्स द्वारा की गई गोलीबारी में कुंजाम देवे नामक ग्रामीण महिला की मौत हुई और एक अन्य महिला घायल हुई। देवे की लाश और घायल महिला को हेलिकाप्टर में ले जाकर वर्दी पहनाकर उन्हें नक्सलवादी घोषित किया गया।

➢ 1 मार्च को नारायणपुर जिले के मांदोड़ा गांव में मिलिशिया सदस्यों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर कामरेड गुधराम नेंडी की हत्या की।

➢ 24 फरवरी को बीजापुर जिला, कोरसेली गांव में अर्द्धसैनिक बलों, छत्तीसगढ़ पुलिस व एसटीएफ ने हमला कर गों साधारण जीवन बिताने वाले कामरेड सलीम (सम्मिरेडी) को पकड़कर अगले दिन आवनार के पास ले जाकर गोली मार दी।

➢ 5–8 फरवरी के मध्य माड़ डिवीजन (नारायणपुर जिला) के गट्टाकल गांव पर छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के पुलिस बलों और सीआरपीएफ ने सैकड़ों की संख्या में हमला कर तबाही और लूटपाट मचाई। गांव में क्रांतिकारी जनताना सरकार द्वारा संचालित आश्रम पाठशाला को जला डाला।

➢ 4 फरवरी को सिंगम और रेंगम गांवों पर हमले कर गांव की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया।

➢ 12–13 जनवरी को बीजापुर जिले के गंगलूर के निकट पिड़िया गांव पर पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने भारी विध्वंसकाण्ड मचाया। घरों में घुसकर

मनमानी लूटपाट की और उसके बाद 20 घरों में आग लगा दी। डोडी तुमनार में जनता द्वारा क्रांतिकारी जनताना सरकार के नेतृत्व में संचालित आश्रम पाठशाला को जलाकर राख कर दिया।

- 19 जनवरी को गढ़चिरोली जिला, अहेरी तहसील के गोविंदगांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर जा रहे गुरिल्लों पर पहले से मिली खबर के आधार पर पुलिस ने घात लगाकर हमला किया जिसमें कामरेड्स शंकर लकड़ा (डीवीसीएम), विनोद कोड़ोपी (अहेरी दल कमाण्डर), गीता कुमोटी (प्लाटून–14 की उप कमाण्डर), मोहन कोवासी (डिप्यूटी कमाण्डर) के अलावा सदस्य कामरेड्स लेब्बे गावड़े और जूरू मट्टामी शहीद हो गए।
- 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला, भुरभुसी गांव में स्नान करते समय गुरिल्लों पर बीएसएफ ने गोलीबारी की जिसमें दो महिलाएं कामरेड्स सनोति और सुमित्रा शहीद हो गईं।
- जनवरी के दूसरे सप्ताह में एपी–छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ग्राम निम्मलागूड़ेम में हमला कर दो ग्रामीण महिलाओं को ले जाकर वर्दी पहनाकर मार डालने की कोशिश की। बाद में अदालत में पेश किया।
- चरला व दुम्मुगूडेम के इलाकों में तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांवों में एपी पुलिस ने गांवों पर लगातार हमले कर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजदिया। आंध्रप्रदेश–छत्तीसगढ़ की सीमा पर हाट बाजारों को बंद किया जा रहा है।

उपरोक्त घटनाएं चंद उदाहरण भर हैं। और भी असंख्य घटनाएं आए दिन घट रही हैं। आदिवासी किसानों को गिरफ्तार कर उन्हें इनामी नक्सली घोषित कर फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। झूठी गवाही से कठिन कारावास की सजाएं दी जा रही हैं।

शोषक शासक वर्ग अपने दमनात्मक हमलों के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध को भी संचालित कर रहे हैं। मीडिया के जरिए यह प्रचारित करवा रहे हैं कि माओवादी नेता बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। यह झूठा प्रचार करवा रहे हैं कि माओवादी नेता पैसा लेकर भाग रहे हैं। समर्पण कर चुके लोगों के जरिए यह दुष्प्रचार करवा रहे हैं कि पार्टी में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और जबरन नसबंदी करवाई जा रही है। दूसरी ओर सरंडर पालिसी का बार–बार प्रचार करते हुए सिर पर कीमत लगा रहे हैं। हथियार लेकर भागकर आने वालों को लाखों रुपए का इनाम देने की घोषणाओं के साथ बड़े पैमाने पर पोस्टर लगवा रहे हैं। इधर पुलिस व अर्द्धसैनिक बल सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम से गांवों में लोगों को तरह–तरह का सामान बांट रहे हैं। लुटेरी सरकारें अपने एलआईसी हमले के तहत सैनिक दमन के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध और ढोंगी सुधार कार्यक्रमों को तेज कर रही हैं।

देश भर में क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करना, देश के विभिन्न क्रांतिकारी संघर्ष के इलाकों में विकसित हो रही जन राजसत्ता को खत्म करना, इसके द्वारा देश की अनमोल प्राकृतिक संपदाओं को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की कार्पोरेट कम्पनियों के द्वारा लुटवाने की राह में आ रही बाधाओं को दूर कर लेना ही इस हमले का मकसद है। इस हमले की अगुवाई सोनिया–मनमोहन–चिदम्बरम–शिंदे–जयराम रमेश शासक गिरोह कर रहा है,जबकि विभिन्न राज्य सरकारें इसमें तालमेल के साथ भाग ले रही हैं। टाटा, मित्तल, जिंदल, एस्सार, अल खैमा, नेको जयस्वाल्स आदि दलाल व विदेशी कार्पोरेट कम्पनियों के साथ किए गए लाखों रुपए के एमओयू को इसलिए कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि देश भर में जनता प्रतिरोध कर रही है और कई इलाकों में इस प्रतिरोध का नेतृत्व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कर रही है। इसीलिए आज माओवादी आंदोलन देश के लुटेरे शासक वर्गों की नजर में 'बहुत बड़ा खतरा' बन गया। इसीलिए साम्राज्यवादी, दलाल नौकरशाह पूंजीपति और सामंती वर्ग इसका अंत करने पर आमदा हैं।

जनता से हमारा आह्वान है कि वह अपनी रक्षा के लिए, अपने एकजुट प्रयासों के बल पर अपना भविष्य खुद ही तय करने के लिए और अपनी जनवादी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साम्राज्यवादियों और उनके पालतू कुत्ते भारत के शोषक शासक वर्गों की तमाम आर्थिक, राजनीतिक व दमनात्मक नीतियों का मजबूती सविरोध करें तथा उनके भाड़े के पुलिस, अर्द्धसैनिक व सैन्य बलों का दृढ़तापूर्वक सामना करें। हम देश के मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, जनवादियों और तमाम देशभक्तों से अपील करते हैं कि वे इस हमले का खण्डन करें और इसे रोकने की मांग करें। क्रांतिकारी संघर्ष के क्षेत्रों में डेरा जमाए हुए तमाम अर्द्धसैनिक बलों को वापस लेने तथा सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करने की मांग करें। हमारा सेंट्रल रीजनल ब्यूरो समूची जनता का यह आह्वान करता है कि इस हमले के खिलाफ आगामी 27 अप्रैल को सेंट्रल रीजियन के क्षेत्र में (उत्तर तेलंगाना, आंध्र–ओड़िशा सीमांत क्षेत्र, दण्डकारण्य, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली व गोंदिया जिलों तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में) बंद रखा जाए। शिक्षण संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, रेल व परिवहन आदि सभी गतिविधियों को बंद रखकर लुटेरी सरकारों को यह बताया जाए कि हम इस हमले का खण्डन करते हैं।

(हालांकि छात्रों की परीक्षाओं और चिकित्सा आदि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा जाएगा।)

आम जनता को विश्व बैंक के हवाले कर देश का आठवां आम बजट पेश किया वित्तमंत्री चिदम्बरम ने !

दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था भारत का 2013-14 का आम बजट फरवरी में साम्रज्यवादियों के विश्वासनीय व वफादार दलाल चिदम्बरम ने आठवीं बार पेश किया। बजट की कुल राशि 16 लाख 65 हजार 257 करोड़ रूपये है। इसमें योजनाबध्द व्यय 5,55,332 करोड़ रुपये यानि लगभग 32 प्रतिशत बाकी 68 प्रतिशत गैर योजनाबध्द खर्च के साथ आम बजट को सांसद में पेश किया।

बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार की उपलब्धियों को बढ़ाचढ़ा कर पेश किया. उन्होनें दावा किया कि माओवादी आन्दोलन पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है। लेकिन अभी भी यह आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देश की अतरीक-बाहरी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनिकों और हथियारों से लैस करने की जरुरत पर भी जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम ने संसद में तीन घंटे के अपने बजट भाषण में कई बॉटल बिसलेरी पानी पीकर जनता को कड़वी घूंट पिलाने की कोशिश की। पिछले दस सालों से सत्ता चला रही कांग्रेस नेतृत्व वाली युपीए सरकार को हर साल कोई एक नयी योजना की घोषणा करने और उस योजना में घोटाले करने का मनमोहन सिंह सरकार का रिवाज बन गया है. ये सारे घोटाले एलपीजी नीतियों की उपज है जिसने इस शासन व प्रशासन को भ्रष्ट बना दिया है। इसीलिए ही अब देश में 2 जी स्पेक्ट्रम और कोलगेट जैसे एक के बाद एक एवं एक से बढ़कर एक लाखों करोड़ो के बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं। दलाल शासक शोसक वर्ग की नीति ही साम्राज्यवादियों को लूट के लिए खुली छूट देकर और खुद भी मौका देखकर झोला भर लेने की है। इस साल के आम बजट को पेश करना तो मात्र एक औपचारिकता थी। क्योंकि इस यूपीए-२ का आखरी बजट है। अगले साल आम चुनाव होने वाला है। सहज ही सत्ता खोने के डर से वह जन विरोधी नीतियों को आगे लाने के लिए हिचकिचा रही है। इसलिए इस बार एक नया तरीका अपनाकर बजट से पहले ही कई नीतिगत एवं महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गये, जिनमें शामिल है खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश, विनिवेश, विमानन क्षेत्र का निजीकरण करना, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की मात्रा में बढ़ोतरी आदि।

उपरोक्त साम्राज्यवादी परस्त एलपीजी नीतियों के अलावा जनता को जो कड़वी घूंट पिलानी थी उसे भी घुमाफिरा कर पिलाया गया है। बुर्जआ शासन में आम जनता के लिए बजट तो आंकड़ों का खेल मात्र है। वित्तमंत्री आंकड़ों का बाजीगर होता है। हाथी के दांत खाने के एक और दिखने के और होते है। इसी तरह सदन के पटल पर रखा जाने वाले बजट और सरकारी खर्च के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है।

2013-14 के बजट को उदारवादी अर्थनीतियों को और तेजी से लागू करने की महज एक जरिये के अलावा और कुछ नहीं है। यह बजट खुद के पैरों पर खड़ा होकर तैयार किया हुआ नहीं है, बल्कि साम्राज्यवादियों पर निर्भर होकर इसे तैयार किया गया है। बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा कर्ज लाने, 20 प्रतिशत आय कर और 21 प्रतिशत नियमित कर पर आधारित है। और खर्च देखें तो 18 प्रतिशत ब्याज चुकाने के लिए, 21 प्रतिशत केन्द्रीय योजनाओं के लिए, 10% सभी प्रकार की सब्सीडियों पर और 10 प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसमें खतरे का विषय यह है कि सरकारी बजट घाटा में चल रहा है। 2009 में 225 अरब डालर रहा घाटा 2012 तक 375 अरब डालर हो चुका था, इस साल यानि 2013 मार्च में वह बढ़कर 418 अरब डालर को पार कर गया है। खतरे की घंटी यह है की हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और ऋण का अनुपात लगातार बिगड रहा है। यानि दिन ब दिन कर्ज बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद आय में राजकोशीय घाटा 2013-14 में 5.2% हो गया है। देश की विकास दर भी लगातार गिर कर 5 प्रतिशत से कम पर आ गया है। डालर के मुकाबले रुपये की कीमत लगातार घाट रही है। फिर भी शासक देश का तेजी से विकास होने का दावा करते आ रहे हैं।

विकास को गति देनेवाले बजट का दावा करने वाले वित्तमंत्री का आर्थिक आवंटन देखने से पता चलेगा कि यह दावा कितना खोखला है। पटल पर रखे गये आंकड़ों को ही मान लिया जाये तो भी विकास में अहम भूमिका निभाने वाले कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रों में आवंटन ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत याद दिलाता है। देश का असली और टिकाऊ विकास उत्पादन से जुडा होते है। सेवा क्षेत्र से होने वाला विकास अस्थाई एवं गुब्बारों जैसा होता है। इस सरल विषय को छुपाकर दलाला मानसिकता वाले शासक जानबूझकर हमें गुमराह कर रहे है। इस बजट उत्पादन क्षेत्र को अनदेखा कर आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, उल्टा विदेशी और रिलायंस, जैसे बड़े दलाल घरानों को मनचाहे ढंग से दाम बढ़ाने की छूट दी गयी है। रक्षा क्षेत्र छोड बाकि क्षेत्रों में बढ़ोतरी नाम मात्रा ही है, इसमें कटौती नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसबार भी कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गयी है।

कृषि क्षेत्र :

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है लेकिन इस क्षेत्र के प्रति शासक वर्गों का रवैया सौतेला ही रहा है। इस के चलते अब तक देश भर में लगभग ढाई लाख किसानों ने खुदकूशी की है। इस साल के आम बजट में कृषि क्षेत्र के ऋण के लिए दो सौ करोड़ अधिक उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया है। समय पर ऋण अदा करने वालों को ब्याज में माफी

देकर 4% सूद लगाया जाएगा. कृषि अनुसंधान, तकनीक, सिंचाई के लिए आवंटित बजट में भी वृद्धि की गयी है। इन आंकड़ों को देखने, सुनने से खुशी होती है। मगर अमल का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकी पिछले बजट में जो पांच हजार करोड़ यानि कृषिक्षेत्र की जरूरत के लिए मात्र 20 प्रतिशत ऋणों का आवंटन किया गया था। इस में भी किसानों को 250 करोड़ ही दिया गये। वह भी किसे मिला कुछ कहा नहीं जा सकता। बुनियादी सच्चाई तो यह है कि बैंकों से ऋण सामन्ती, धनी किसान और कुछ उच्च मध्यम किसानों तक ही पहुंच पाता है। 60% गरीब किसान महाजनों व सूदखोरों से कर्ज लेते है। बजट के ऋण आबंटन से इन किसानों को कोई फयदा नहीं होगा. न ही सूद माफी की सरकारी योजना में इन किसानों को कोई फायादा होने वाला है. क्योंकि उन्हें बैंकों से कर्ज मिलता ही नहीं.

कार्पोरेट कृषि नीति को बढ़ावा देनेवाली सरकारी नीति से बीज, खाद और किटनाशक दवाईयों पर साम्रज्यवादियों का कब्जा होता जा रहा है। इससे मध्यम और छोटे किसानों की कृषि में साल दर साल बीज, किटनाशक दवाई, खाद की महंगाई स कृषि लागत में वृद्धी आई है। नाममात्र रह गए सब्सिडी और उत्पादन लागत में वृद्धी की तुलना में सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही कम बढ़ा है। यह न्यूनतम मूल्य भी किसानों को न मिलने की स्तिथी में है, क्योकि खुद सरकारी संस्थायें जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और सीसीआय ही किसानो से मंडियो में न्युनतम समर्थन मूल्य पर फसल नहीं खरीद रहे हैं। इससे 11 करोड़ किसान परिवारों की जिंदगी मुश्किल में पड़गई है। धीरे-धीरे मध्यम किसान गरीब किसान में और गरीब किसान मजदूर में बदलता जा रहा है। कृषि मजदूर अच्छे जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे है। इससे शहरों में बेरोजगार सेना बढ़ रही है। जहां बुआई और कटाई से लेकर उनकी बोरियों की पैंकिग करने वाले कामगार पलायन कर रहे हैं। इस साल कृषि विकास दर 4 प्रतिशत निर्धरित किया गया, लेकिन इस हालात में तो 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। मगर सेज, रोड़, गृह निर्माण (टाऊनशिप) और उद्योग के लिए अंधादुंध जमीन अधिग्रहण करने से उपजाऊ जमीन भी कम हो रही है। इस से धिरे-धिरे देश खाद्य असुरक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास पर इनदिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। मगर ग्रामीण विकास के नाम पर सड़क और संचार व्यवस्था पर ही 75% खर्च कर रहे हैं। नये चकाचक रोड़ों को साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाहों द्वारा अपने देश की संपदाओं को राजाओं जैसे बेरोकटोक लूटकर ले जाने के लिए, माओवादी आन्दोलन को कुचलने के लिए और सुदूर इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तुरंत रवाना करने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा।

औद्योगिक क्षेत्र

जबसे विश्व बैंक की एल.पी.जी शर्तों के आगे देश के शसक वर्गों ने सिर झुकाया है तब से देश के सार्वजनिक उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करना जारी है और घरेलू उद्योगों की भूमिका बड़ी कंपनियों से अनुबंधित होकर और कल-पर्जे तैयार करके सप्लाई करने की बन गयी है। लघू और मध्यम स्तर के उद्योग बंद होने के कगार पर हैं, या खुद के उत्पादन की जागह मजबूरन सब कांट्रेक्ट पर काम करने को तैयार होने की स्थिति में आ गये हैं। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 360 लाख सुक्ष्म, लघू और मध्यम कारखाने हैं। जिनमें 810 लाख लोग काम कर रहे हैं। इन कम्पनियों में काम के अवसर दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। यानि कारखानें बंद हो रहे हैं। इसका कारण आर्थिक मंदी नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियां ही इसका असली कारण है। इन उद्योगों को दिये गये बैंक ऋण पर अधिक ब्याज, बिजली सप्लई में कटोतियां और अधिक टेरिफ लगाने से लेकर पहले से मिल रही सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सब्सिडियां कम करने या बंद करने की सरकारी नीतियों की वजह से मार्केट में इन कम्पनियों का टिक पाना मुश्किल हो गया है। बड़ी कम्पनियों के हाथों में बिक जाने या अनुबंधित हो जाने का ही इनका भविष्य हो गया है। उदहरण के लिए हम छत्तीसगढ़ को ही देखें, यहां लौहा आयस्क पर आधारित कई छोटे-मोटे कारखाने हैं जो आज ज्यादातर बंद होने के कगार पर हैं क्योकि इन कंपनियों को लोह आयस्क समय पर नहीं मिलता। बैलाडिला के एनएमडीसी से लोह आयस्क जापान को समय पर और कौड़ियों के दामों पर बेचा जाता है तो यहां के स्थानीय उद्योगों को कई गुना ज्यादा भाव लगाये जाते हैं। देशभर की यही कहानी है। इससे देश में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। छोटे, मझोले कारखानों में ही श्रम शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल होता है। बड़े कारखानों में मशीन को ज्यादा लगाते है जिस से इनमें श्रम शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता।

संकट में फसे औद्योगिक क्षेत्र को उबार कर रोजगार वृद्धि के लिए बजट में कोई सकरात्मक उपाय और ठोस कदम नहीं उठाये गये। उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने के अलावा खुदरा व्यापार में एफडीआई को अनुमोदन देने के बाद पांच करोड़ छोटे व्यापारियों को भी अपनी रोजी रोटी के लिए माल स्टोरों में कामगार बनना पड़ेगा। वहीं साम्रज्यवादियों और दलाल नैकरशाही पूंजिपतियों के लिए जमीन, पानी, बिजली, सब कुछ मुफ्त में देने के अलावा नौ सालों तक करों में राहत और कई तरह के पैकेज दिये जा रहे हैं पिछले तीन सालों से हर साल 5000 करोड़ रुपये का पैकेज दे रहे हैं।

रक्षा बजट

देश के रक्षा बजट में हर साल भारी बढ़ोतरी हो रही है और आवंटित बजट से भी ज्यादा खर्च किया जा रहा है। 2009-10 के आम बजट में सुरक्षा के लिए 33,809 करोड़ आवंटन किया गया था। इन चार सालों में चार गुना ही नहीं लगभग 7.5 गुना बढ़ा कर इसे अब 2,03,672 करोड़ आवंटन किया गया है। खर्च इससे ज्यादा नहीं होगा इसकी कोई

गारंटी नहीं है क्योंकि अगर 2001-10 का ही उदाहरण देखे तो हमें पता चलेगा की आवंटित राशि से भी 30 प्रतिशत ज्यादा रकम खर्च की गयी। वहीं कृषि जैसे क्षेत्रों की बजट राशि कभी पूरी खर्च नहीं की जाती। रक्षा बजट कृषि और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों की राशि को शासव–शोषक निगल रहे हैं। इस विषय में कोई पार्टी भूलकर भी चर्चा नहीं करती। गलती से भी अगर कोई सवाल किया तो उसे शक के नजरिये से देखा जाता है। देश को तरक्की करना और आगे बढ़ना है तो कृषि और उद्योग जैसे उत्पादन क्षेत्रों और शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से खतरे का हवाला देकर सभी का मुह बंद कर रहे हैं। लेकिन रक्षा बजट इस तरह बढ़ाने का असली मक्सद साम्राज्यवादियों से चम्चागिरि, तो पडोसियों पर दादागिरि और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संकट से राहत दिलाना है।

देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए माओवादा का खतरा और बाहर से चीन का खतरा नाम से कई रक्षा सौदे किया जा रहे हैं। माओवादियों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियारों और आधुनिक टेकनलाजी से अर्द्ध सैनिक बलों को लैस कर रहे हैं। माओवादी इलाकों में काम करने वालों को भारी प्रोत्साहन के तौर पर उपहार दिया जा रहे हैं और कई नयी अर्द्ध सैनिक बटालियानों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ-साथ स्पेशल ऑपरेशनों के लिए पैसा पानी जैसा बहाया जा रहा है ।

देश गम्भीर आर्थिक संकट झेल रहा है यह खुद प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री भाषण में कहने के बाद गैर उत्पादक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने का मतलब क्या है? क्या देश की सुरक्षा सचमुच खतरे में पड़ा है? असल में सुरक्षा के नाम से शासक वर्ग कुछ और ही हासिल करना चाहते हैं। आर्थिक संकट में फसे साम्राज्यवादी देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बचाने के लिए हजारों करोडों का सौदा कर दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपय हड़प रहे है। हाल ही में कई बड़े देशों से रक्षा संबंधी करार हुए हैं। इन्ही में से एक रुस से दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान सुखोई के पांचवें संस्करण का 126 विमानों को 50 हजार करोड़ में खरीदने का निर्णय हुआ है। और अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए 3600 करोड़ से हेलिकप्टरों की खरीददारी हो रही है। इसके लिए 17 करोड़ रुपये एडवान्स भी दे दिया गये हैं।

इस भरी वृध्दि का राजनीतिक पहलू यह है कि साम्राज्यवादियों के इशारे पर चलने वाले सामन्ती और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों ने साम्राज्यवादियों की लूट खसोट में आड़े आ रहे माओवादियों का किसी भी कीमत पर सफाया करना है। दूसरा, बुरी तरह संकट में फसे साम्राज्यवादी देशों के कई रक्षा उत्पाद कारखानें बंद के कगार पर हैं। अमेरिका सहित सभी साम्राज्यवदी देशों ने बेलअउट पेकेज (दिवालिया कंपनियों को बचने के लिये दी जाने वाली आर्थिक मदत) दिये हैं फिर भी वे कंपनियां घाटे से उभर नहीं पाई। उन कंपनियों की ओर से साम्रज्यवादी देश विकासशील व पिछड़े देशों पर रक्षा सामाग्री खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस दबाव के आगे झुक चुके शासक वर्ग देश की सुरक्षा का हवाला देकर उन देशों से रक्षा सामग्री खरीद रहे हैं। तीसरा कारण अपने देश के शासक वर्गों की एक विशेषता यह है कि साम्राज्यवादियों की छत्रछाया में ही अपनी विस्तारवादी आकांक्षा को पाल रहे हैं। पड़ोसी देशों पर अपना दबदबा बनाये रखने के लिए भी भारी सैनिक खर्च कर रहे हैं।

नई योजनाएं और हकीकत

इस बजट में कुछ नई योजनाएं घोषित की गई हैं। उनमें प्रमुख है खाद्य सुरक्षा, महिला बैंक, निर्भया निधी, युवाओं के कौशल विकास की योजनायें। खाद्य सुरक्षा के तहत गरीब तबके के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सब्सिडी से तीन रुपये किलो चावल,दो रुपये किलो गेहुं हर व्यक्ति को पांच किलो अनाज बांटने की योजना बनायी गयी हैं। पिछले चार सालों से ठंडे बस्ता में डाल कर रखी इस योजना को अगले चुनावों को नजर में रखकर अब आखरी समय में अनन-फनन में लाए हैं और पुरी दुनिया में ही अनोखी है योजना के नाम से प्रचार कर रहे हैं। इस योजना के दायरे में शहर के 55 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत परिवार आते हैं का प्रचार किया जा रहा है। साथ ही गरीब परिवारों का भूखे पेट सोना और कुपोषण भी दूर होगा का भी पूरे जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। यही सरकार खुद अपनी बयान में कह रही है कि देश में गरीबी रेखा के नीचे अब मात्र 30 प्रतिशत लोग रह गये हैं। फिर अचानक इतनी आबादि इस योजना में कहां से आ गयी? यह दोहरी बातें राजनीतिक अवसरवाद और चुनावी स्टंट है। अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों को वितरण के नाम पर नीचे से लेकर ऊपर तक बंदर बांट हो रही है। इस धांधली को रोकने और जरुरतमंद लोगों को ठीक से पहुंचाने के लिए ही नगदी बदली योजना लाने का इतने दिनों से प्रचार किया गया। अब इस योजना को किस प्रणाली से क्रियान्वित किया जाएगा अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। लेकिन इसके लिए बजट में मात्र दस हजार करोड़ रुपये दिये गए हैं जबकि इस प्रणाली को सालभर अमल करना है तो कम से कम सव्वा लाख करोड़ रुपये चाहिए। यह गरीबों से खिलवाड़ा के सिवाय कुछ नहीं है। इससे पता चलता है कि इस योजना को लेकर सरकार कितना गम्भीर और संवेदनशील है। सरकार का मकसद गरीब जनता को अनाज देना नहीं बल्कि गरीबों के वोटों को हासिल करके फिर से सत्ता में आना है।

महिला बैंक, और निर्भया कोष की घोषणा - देश में साम्राज्यवादी संस्कृती का अंधानुकरण करते हुए महिलाओं को एक भोग की वस्तु या मार्केट में बिकाऊ चीज और सेक्स सिबंल के नजरिये से देखने की नकारात्मक सोच बढ़ गयी है। इससे देश के हर कोने में हर दिन बुजुर्ग महिलाओं से लेकर नाबालिग लडकियों तक पर आये दिन अत्याचार एक आम बात हो गई है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में पारा

मेडिकल छात्रा पर हुए अत्याचार के बाद देशभर में सरकार के विरोध में उमड़े जनाक्रोश ने महीने भर दिल्ली को हिला कर रख दिया था। इन प्रदर्शनों में खासकर महिलाओं और युवाओ ने भाग लिया। इस जनाक्रोश को देखकर सरकार घबरा गयी थी। आनेवाले चुनावों में यह गुस्सा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाने के खतरा को कम करने के लिए महिला एवं युवाओं को लुभाने के लिए ही यह योजना है। विशेष महिला बैंक की स्थापना उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ कुछ हद तक मध्यम वर्ग महिलाओं के लिए काम आएगी। इससे गरीब तबके की महिलाओं को कुछ भी फायदा नहीं होनेवाला है। सरकार यह भूल रही है की गरीब ही नहीं उच्च मध्यम वर्ग तक की महिलाएं आकाश को चूमते दामों का मुकाबला कर परिवार चलाने में पुरुषों से ज्यादा मुश्किलें उठा रही हैं। यह मुश्किलें कौनसा मोड़ लेंगी सरकार को आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा।

रेल बजट

केन्द्र में 18 सालों के बाद फिर एक बार रेल मंत्रलय की लगाम कांग्रेस पार्टी के हाथों में आयी है। पिछले आठ सालों में सिधे तौर पर यात्रा किराया नहीं बढ़ा, लेकिन दूसरे तरीकों इसे बढ़ाया जाता रहा है। इस साल के बजट के समय कभी अमल में न आनेवाले कई सुविधाओं की घोषणा करने के साथ ही एक अहम निर्णय की घोषणा की गयी जो आगे जाकर यात्रियों की जेब काटेगी। वह यह है कि साल में दो बार इंधन कर बढ़ाये जाने का रेल मंत्री पवन बंसल ने ऐलान किया है। इसका मतलब है किराया बढ़ाने के लिए न रेल बजट और न ही संसद की मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा, रेल यात्रियों को जब चाहे तब लूट लेने का अधिकार सरकार को इससे मिल गया है।

बढ़ती महंगाई और घटता जीवन स्तर

बढ़ती महंगाई आम जनता के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। महंगाई किसी भी देश की आर्थिक मजबूती की सूचक भी है। जहां जितनी महगांई वहां उतना ही आर्थिक संकट का संकेत देता है। मंहगाई कम करना जनता के अक्रोश को कम करने के लिए ही नहीं पटरी से उतरनेवाली आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भी जरुरी होता है। इतनी गम्भीर समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। बल्कि वह महंगाई को बढ़ावा देने की भूमिका ही निभा रही है।

युपीए 2 सरकार विकास का नारा लेकर अगले चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है। बजट में विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है यह औद्योगिक संगठनों ने कहा और उसका कार्पोरेट मीडिया ने बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार किया। अगर विकास पर जोर लगाना है तो पहले महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। स्विस बैंकों में जमा देश के काले धन की वापसी और उसको निकलावने के साथ जमाखोरी पर पाबंदी लगाना चाहिए। मगर सरकार में उतनी इच्छाशक्ति नहीं है। महगांई बढ़ाने में एक अहम भूमिका डिजल, पेट्रोल, गैस आदि इंधन के भावों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल, डिजल, गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी 90 हजार करोड़ से 62 हजार करोड़ तक घटायी गयी. अब धीरे-धीरे इसे पूरी तरह हटाने के लिए वैश्विक मुल्य के अनुरुप रखने के नाम से हर पंद्रह दिन में एक बार मूल्यांकन का नाटक कर रहे हैं। रिलायंस और दूसरी विदेशी उर्जा कंपनियों को मनचाहे दाम तय करने के लिए पूरी छूट देने की योजना जनवरी में रंगराजन समिति ने बना दी थी।

अत: इस बजट का मतलब - देश की अर्थ व्यवस्था में सेंध लगाने वाले एफडीआई के लिए खोल देना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के नाम से कई प्रोत्सहनों की घोषणा, घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रति नकारात्मक रवैय्या, सुरक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में सौंपना, उत्पादन क्षेत्र को नजरंदाज करना, कुछ आकर्षक योजनाओं को आरम्भ करना है। औद्योगिक घरानों से कभी भी पूरी कर वसूल नहीं करने वाली सरकार - राजस्व घाटा को कम करने के नाम पर कटौती की तलवार पहले ग्रामीण विकास, कृषि, अल्पसंख्याकों, एससी, एसटी और शिक्षा आदि के लिऐ निर्धारित की गये बजट पर ही चलाती है। देश में राष्ट्र मंडल खेलों के आयोजन के लिए एससी, एसटी और ग्रामीण विकास बजट में की गयी कटौती इसका जीता-जागता सबूत है। यह इतिहास फिर नहीं दोहराया जायेगा इसका का कोई सबूत नहीं है।

पीएलजीए में पार्टी का बोल्शेवीकरण करते हुए जन आधार को बढ़ाओ!
जनता के खिलाफ युध्द आपरेशन ग्रीनहंट को हराने के लक्ष्य से हमेशा पहलकदमी बरकरार रखते हुए गुरिल्ला युध्द को तेज करो!

पीएलजीए की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर सीएमसी का संदेश

पाठकों से अपील

'जनसंग्राम' आपकी पत्रिका है, तमाम पाठक साथियों से अपील है कि पत्रिका के लिए आपके इलाके में जनता पर होने वाले दमन, प्रतिरोध, पीएलजीए के दुश्मनों पर हमलों, लुटेरी सरकारी नीतियों व विस्थापन के खिलाफ, जल-जंगल-जमीन के लिए उठने वाले आंदोलनों पर नियमित रिपोर्टस भेजें. पत्रिका पर अपनी सलाह, सुझाव व आलोचना भेजें!

संपादक मंडल - 'जनसंग्राम'

मैनपुर डिवीजन में बढ़ता पुलिस दमन

पिछले साल मई महीने में जोलाराव गांव के निकट जंगल में मुखबिर की सूचना के आधार पर दस्ते पर हुए हमले में जनता की प्यारी सुपुत्रियां और हमारी प्रिय कामरेड्स समीरा, अरुणा और अमीला की शहदत के बाद डिवीजनल कमेटी के नेतृत्व में मुखबिर नेटवर्क को कुछ हद तक ध्वस्त कर किया गया. कुछ का सफाया करने के बाद कुछ मुखबिर गांव छोड़ कर शहर भाग गये हैं।

दुश्मन इनफर्मर नेटवर्क को निरंतर फैलाने की कोशिश जारी रखे हुए है। एलआईसी नीति के तहत दुश्मन एक तरफ खुद के खूफिया विभाग को मजबूत कर रहा है हुए दूसरी तरफ पार्टी और आंदोलन के खिलाफ कुप्रचार चला रहा है। और पक्का समाचार मिलने परे हमला भी कर रहा है। गस्ती में तेजी लाकर अपनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्रामों के जरिये आम जनता में से कुछ लोगों को अपने ओर मोड़ लेते हुए आत्मसमर्पणों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

गस्ती का तरीका :

उदंती इलाके में एक ही समय जुंगाढ़, इंदगांव, बीरगाटी, रायगर, शोभा से पुलिस बल उदंती के जंगल में चारों ओर से कुम्बिंग कर रहे हैं। इसी तरह सीतानदी इलाके में बोराई, सीतानदी, बिर्नासिलि, मेंचिका, शोभा से पुलिस बल जीपीएस सिस्टम की मद्द से रास्तों को छोड़कर पूराने डेरों को कवर करते हुए पहाड़ों, जंगल को घेरकर छानबिन करते हुए घूम रहे हैं। नया डेरा दिखने से अगली बार जरूर तलाश कर रहे हैं। एक दिन से लेकर तीन-चार दिन तक घूम रहे हैं। जनता से बचते हुए आधी रात को जंगल में घुस रहे हैं। एक-एक बैच में 30 से 50 की संख्या में आते हैं। कभी-कभी 200 की संख्या में एक ही बैच के रूप में आते हैं। खासकर शोभा से ओड़िशा जानेवाले रोड पर भूतबेडा से लेकर गरिभा को सबेरा पैदल ही जाकर फिर शाम को 6 बजे वापस आते हैं। इसी समय कुछ बैच हमारी ओर से आंबुश के खतरे वाली जगहों की जांच करने या सिविल में दुपहिया वाहनों पर सवार टीमों के साथ जांच कर करते हैं।

हमारे दस्तों का समाचार मिल ने पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल जमा होकर हमला के लिए आते हैं। गाजी मुंडा के पास डेरा पर हुए हमले के लिए लगभग 250 की तादाद में आये थे। इस में सीआरपीएफ, एसटीएफ व जिला पुलिस बल सबेरे दो बसों और 25-30 दुपहिया वाहनों पर सवार होकर आये थे। इस बार सीधा हमला करने की बजाय फायरिंग से रिट्रीट होते समय दस्ता को फसाकर सफाया करने की रणनीति बनाये थे। इसी के तहत घटना स्थल को घेरकर कई स्टाफ पार्टियों को तैनात कर रखा थे। इसी तरह बाटापानी जंगल में डेरा पर हुये हमले में भी इसी तरह की रणनीति को अपनाया गया था। इन दोनों घटनाओं के अलावा 2012 में जोलाराव की घटना में भी एक विशेष तरह की गैस से बने ग्रेनेडों का इस्तेमाल किया गया. इस विषैली गैस में सांस लेने से उल्टियां होना, चक्कर आना के अलावा, बेहोश सा हो जाना, दो–तीन दिन तक खाना खाने की इच्छा नहीं होना आदि से इंसान बहुत ही कमजोर बना जाता है। कुम्बिंगों में हो या पट्रोलिंगों के समय हामरे हमलों से बचने की सभी सतर्कताएं दुश्मन बरत रह हैं।

सिविक एक्शन प्रोग्राम :

आम जनता के मन से अपनी क्रुरता छवी को मिटा कर एक छोटे गुट को अपनी ओर मोढ़ कर मुखबिर एसपीओ व्यवस्था बनाकर आम जनता के खिलाफ खडा करना और कुछ दलालों को तैयार करने के लिए ही यह योजना चला रहे हैं। आम तौर पर स्थानीय प्रशासन के बिना ही एस.पी, सी.आर.पी.एफ अधिकारियों के नेतृत्व में इसे चला रहे हैं। हाल ही में ओड़िशा के कांडेतरई में हुए प्रोग्राम में एसपी शामिल होकर हमारे विरोध भाषण देकर बताया की नक्सली विकास विरोधी हैं इसी लिए इस इलाके में रोड़ निर्माण नहीं होने देते-रोड़ नहीं होने से इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं । और कई प्रकार के मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं। सरकार के पक्ष में रहकर पुलिस की मदत करने का अनुरोध किया और सरकार के साथ रहने से कई फायदा हैं यह बोलकर लालच दिखाया। सीतानदी इलाका के सालेभाट,उंदती इलाका के कर्लाझर,सहाबिनकछार,और भुतबेड़ा,गोना में सी.आर.पी.एफ के कमांडेंट के नेतृत्व में चलाया गया प्रोग्रामों में पुलिसों ने घर-घर जाकर जनता को जबरन जमाकर मीटिंग करके स्टीलड्रम,सोलर लेंप,बच्चों को नोटबुक किसानों को कृषि औझार वगैरा वितरण किया!

दुश्प्रचार :

पार्टी एवं नेतृत्व के खिलाफ पर्चों के माध्यम से सरकार बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। जैसे - नेतृत्व बाहर से आकर स्थानीय युवाओं को बहला-फुसला कर जबरन पार्टी में शामिल करके अपराधों में फसा रहे हैं, अत्याचार करवा रहे हैं , गुरुजीयों को हत्या कर के बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं, ठेकेदारों को डरा-धमका कर जबरन पैसा वसुलकर नेता अय्याशी कर रहे हैं । रोहीदाश, जगबन्धु मांझी जैसे जनता द्वारा चुने गये जन प्रतिनिधियों का हत्या कर जन समस्या निराकरण में बाधा पहुंचा रहे हैं, बाहर से आये नक्सली यहां आतंक पैदा कर रहे हैं, इसलिए उनके संगठनों में कोई नहीं शामिल होना पार्टी में भर्ती नहीं होना, दस्तों में काम कर रहे लोग भी वापस आकर सरेंडर करो - आदि

दुष्प्रचार कर रहे हैं। साथ ही आत्मसमर्पण करने वालों से घरों को लेटर लिखवा रहे हैं जिसमें धमकी देर हैं कि वापस आआ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा ।

एसपीओ-मुखबिरी नेटवर्क ध्वस्त :

डिवीजन में 2012 के आखरी में एक मुहिम के तहत मुखबिरों पर कार्रवाई किये जाने के बाद कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं। इसे पुलिस ने निर्दोष लोगों को मुखबिर करार देकर जान से मार डाल कर गाँवों से पच्चीस परिवारों को भगाया का झूठा प्रचार किया। पार्टी की ओर से पर्चा निकालकर हमने किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया। जनता के अनुमोदन से एवं-मांग से जिनका गुनाह और जनविरोधी गतिविधियां साबित होने के बाद ही कारवाई की गयी है। हम किसी परिवार को गाँव बहार नहीं किये। अगर निर्दोष हो तो वापस गांव में आओ, जाने अंजाने में कुछ गलत किया तो भी जनता से माफी मांगकर रह सकते हो का भी हमने प्रचार किया है. जिससे आम जनता में अनुकूल प्रभाव पड़ा। मगर इनमें से कोई परिवार वापस गांव में नहीं आया। उल्टा नगरी-सिहावा जैसे शहर जनेवाली आम जनता, जनसंगठनों के कार्यकर्ताओं, पार्टी हमदर्दों का पता लगाकर तुरंत पुलिस को फोन में बताकर अरेस्ट करवा रहे हैं या फिर तरह-तरह के प्रश्न पूछकर मानसिक यातनाएं दे रहे हैं। एक इनफार्मर को कोवर्ट बनाकर दस्ता में भर्ती करवाने की कोशिश भी की गयी है। इस साल की तीनों मुठभेड़ों के पीछे भी मुखबिरी सूचना ही असली कारण रहा। योजनाबध्द तरिके से जनसंगठनों , पार्टी सेलों में रहे सदस्यों, दस्तों में काम करके व्यक्तिगत कारणों से आम जिन्दगी जीने की आशा से घर वापस गये सदस्यों को जबरन एसपीओ बनाना, और योजनाबध्द तरिके से हमारे समर्थकों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यातनाएं देकर दस्ता, डंपों के बारे में समाचार लेकर, इसी के आधार पर कुछ डंपों को नष्ट भी किये है।

गांवों और जनता पर दमन :

गांवों और कुछ परिवारों पर हमे मदत देने का आरोप लगाकर बार-बार हमला करके मारपीट कर रहे हैं। ग्राम बोनास पर कई बार हमला करके जनता को पिटाई किये और जबरन घरों में घुसकर धान को नष्ट करने के अलावा हजारों नगदी लुट कर ले गये। ग्राम आछला में भी इसी तरह का बर्ताव किया गया। बार-बार के हमलों से डरकर कुछ गांव वाले गांव छोड़ कर जाने पर मजबूर हैं या फिर पुलिस स्टेशन जाने से दबाव में आकर मुखबिर बन रहे हैं। पुलिस प्रशासन यह इसलिए कर रहा ताकि जनता और गांव पर दबाव डालकर पार्टी को जनता से अलग-थलग किया जा सके। हर पुलिस थाना और कैम्प के सामने नाका लगाकर सामान की तलाशी ले रहे हैं। सरपंच, सचिवों व शिक्षित लोग भी अगर गांव में दैनिक पेपर लाते हैं तो यह नक्सलियों के लिए है कहकर जप्त कर रहे हैं। पार्टी को समाचार से वंचित करना ही इसका असली मक्सद है। पुलिस बेकसुर लोगों को गिरफ्तार करके इनामी नक्सली करार देकर बड़ा सफलता के तौर पर दर्शा रहे हैं इस बीच सीतानदी इलाके में गातिबहरा गांव से एक व्यक्ति को और अंजूर गांव से दशरथ नामक आसामी को अपने-अपने घरों से अरेस्ट करके गस्ती के दौरान जंगल में इनामी नक्सलियों का गिरफ्तार के नाम से अखबरों में रिर्पोट छपाया। मगर इन लोगों से पार्टी का कोई संबन्ध नहीं है। पुलिस और सरकार की जनजीवन पर कड़ी निगरानी व दबाव के बावजूद जनता के मन में पार्टी के प्रति प्रेम भावना ज्यों कि त्यों है।

गरियाबंद एसपी का पुलिस को मोटिवेट करना :

इस बीच गरियाबन्द पुलिस अधिक्षक ने जिला में तैनात सभी तरह के बलों को मोटिवेट करने के लिए-फील्ड समस्याओं के निदान के नाम से सभी तरह के बलों को एकत्र करके खिलाना-पिलाना, पुलिस परिवारों से कौन्सिलिंग के नाम पर मुलाकात करके पारिवारिक समस्या समाधान के नाम से नाटक चलाकर कुछ छोटा-मोटा उपहार दे रहा है. कुम्बिगं, सार्चिगं अभियानों में एसपी, कमांडेंट स्तर के अधिकारी प्रत्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं। दमन में तेजी के साथ क्रूरता भी लाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी राम गोपाल गर्ग कोशिश कर रहा है।

नुआपाड़ा डिवीजन - दमन और प्रतिरोध

बूबिट्राप हेंडबैग से एएसपी सहित दो पुलिस घायल

बढ़ते पुलिस दमन के खिलाफ डिवीजनल कमेटी ने 6 जनवरी 2013 को जनता से एक दिन बंद का अह्वान किया था। इसी सिलसिले में अममोरा एरिया में मैनपुर-देवबोग रोड पर दवलपुर के पास रोड को अवरुद करने के लिए कुछ पेड़ काटकर डाले गये साथ ही वहां कुछ पोस्टर, बेनर, और कुछ रोजमर्रा की चीजों के साथ एक हेंड बैग छोड़ कर आए थे। इसकी सूचना मिलते ही गरियाबंद जिला पुलिस उप अधिक्षक के नेतृत्व में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी तड़के चार बजे घटना स्थल पर पहुंच कर जंगल के ओर दो-चार कारतूस फैर कर कुछ ही दूर पर पड़े हुआ सामान को जप्त कर जैसा ही हेंड बैग की चेन खोली तो तुरंत विस्पोट हुआ इस घटना में एएसपी राज कुमार मिंज के अलावा दो और जवान घायल हुए।

मूड़ी पानी गांव में बम निरोधक दस्ता के दो पुलिस वाले घायल

सुनाबेड़ा एसी इलाका में छग और ओड़िशा पुलिस हमेशा संयुक्त अभियान चलाते हुए जनता को मारपीट करना गालि-गलोज करके, अरेस्ट करके जनता में दहशत का महोल पैदा कर रहे हैं। जनवरी 17 को संतोश पारा जंगल में हुए मुठबेड़ के बाद हमेा दस्ता का

सफया करने के घमंड से घूम रहे दुश्मन को सबक सीखाने के लिए फरवरी 4 की रात को रसेला - पिपरछड़ी रोड पर मूड़ी पाानी गांव के चोराह में चारा के रूप में बेनर, पोस्टर लगाकर एक माईन बिछाकर उपर डम्मी बम लगाया गया था। बम निरोधक दस्ता के साथ घटना स्थल पहुंची पुलिस टुकड़ी बम को निष्क्रिय करते समय एक जवान घायल हुआ। इसके अगले दिन फिर जांच के लिए आए बम निरोधाक दस्ता के आतंकियों में से एक अतंकी पुलिस वाला दूसरे ट्राप की चपेट में आकर घायल हुआ। इस से पुलिस में घबराहट पैदा हुआ तो जनता में खुश का लहर फैली। गरिया बंद एसपी रमगोपाल गर्ग ने पत्रकारों से कहा माओवादियों ने जगह-जगह बम बिछाके रखने की खबर मिली है इसलिए बमनिरोधक दस्ता छानबीन करेगा तब तक कुछ दिन कुाम्बिंग बंद रहेगी।

दमन के खिलाफ नुआपाड़ा डिवीजन बंद सफल!

डिवीजन में अर्ध-सैनिक बलों से बार-बार कुम्बिंग चलाते हुए जनता के साथ मारपीट कर गाली-गलोज करना, गांव को घेराव करके पार्टी समर्थकों, जन संगठन कार्यकर्ताओं को गिफ्तार कर यातनाए देना, जेल में कैद करना, जमानत न देकर महिनों-महिने जेल में ही बंद रखना आदि दमन जारी है। इस तरह 2011 से अब तक लगभग एक सौ लोगों को गिफ्तार कर शारीरिक व मानसिक यातनाएं देकर 20 जन को जेल में कैद किया! पुलिस वाले आदिम जनजाति **चौकट भूंजियों** के रीति-रिवाजों की हंसी उड़ाते हुए पवित्रता के प्रतीक माने-जाने वाला **लाल बंगला** (रसोईघर जिसमें परिवार सदस्यों के अलावा-दूसरों का प्रवेश निषेध होता है) में जूते-चप्पलों साहित घुस रहे हैं। इस फासीवादी दमन-घेराव के खिलाफ 2013 जनवरी 6 को डिवीसी ने जनता से डिवीजन (नुआपाड़ा-गरियाबन्द) बंद को सफल बनाने का आव्हान दिया था।

बंद की सफलता के लिए पोस्टर, बेनर, पर्चों से जनता में प्रचार किया गया। जनवरी 5 की आधी रात के बाद मैनपुर-धवलपुर रोड़ पर मिलीशिया की मदद से पीएलजीए ने अवरोध खड़े करके रोड़ के बगल में बूबि ट्रापवाला हेंड बेग छोड दिया. गरियाबन्द पुलिस उप अधिक्षक राजकुमार मिंज के साथ सीआरपीएफ के दो पुलिस घायल हुए। इसके बाद रोड़ पर कई घंटो तक ट्राफिक जाम रहा। बाजार, वहान, पेट्रोलपंप आदि बंद रहे.

दुष्प्रचार के खिलाफ क्रांतिकारी प्रचार

दुश्मन ने आंदोलन और पार्टी का सफाया करने के लिए एक तरफ ग्रीन हंट सैनिक अभियान तो दूसरा तरफ आर्थिक सुधार - जनता में फूट डालों राज करो नीति के अनुसार सिविक प्रोग्राम जारी हैं, जिसका मकसद मुखबिर बनाकर दमन को तेज करना है। इस नीति के तहत ही डिवीजन में समय-समय पर जंनादोलन को बदनाम करने के लिए कभी खुद पुलिस प्रशासन के नाम से तो कभी फर्जी नामों से दुष्प्रचार दुश्मन चला रहे हैं।

इस बीच पुलिस ने अर्ध सैनिक बलों में भर्ती होने के लिए बेरोजगार युवा खासकर छात्र-छात्राओं को प्रेरित करते हुए शारीरिक दृढ़ता और शिक्षा मापदंडों में छूट का भरोसा दिलाया जा रहा है। देश-राज्य की सेवा के नाम से पूंजीपतियों की लूट जारी रखने के लिए किराये के टट्टू बनाये जा रहे हैं। पुलिस की और से आदिवासी संघर्ष समीति के नाम से गांव छोड़कर भाग गये मुखबिरों के समर्थन में एक पर्चा निकाला गया। डिवीजनल कमेटी ने भी एक पर्चा निकाला - पुलिस, एसपीओ, मुखबिर क्यों नहीं बनना चाहिए, जनांदोलन पर आदिवासियों के नाम से पुलिस के दुष्प्रचार विरोध करें। जनता के बीच फूट डालने के प्रयास को विफल करें।

इसी तरह डीवीसी का ओर से शहीद भगत सिहं के शहदत दिवस पर डिवीजन के युवाओं से अपील - देश को साम्राज्यवादीयों, दलाल शासक वर्गो के शोषण से मुक्ति के लिए शहिद भगत सिहं के वारिस बनो! पुलिस, एसपीओ, मुखबिर नहीं! देश को गुलामी मानसिकता, शोषण व कर्ज की दलदल से मुक्ति के लिए पीएलजीए में शामिल हो! गरीब और बेरोजगार युवाओं को एसपीओ, पुलिस में भर्ती करके अपने ही भाई बहनों की हत्या करवाने की शासक वर्ग का साजिश को ठुकरा दो! नाम से और फिलिपिन्स जनयुध्द पर अमेरिकी साम्राज्यवाद की मदद से वहां के शासक वर्गों द्वारा चलाये जा रहे दमनकारी ऑपरेशन ओपलान बेनियहान सैनिक हमले के विरोध में अप्रैल माह में सप्ताह भर भाईचारा समर्थन में प्रचार किया गया। इसी तरह वनोंपज संग्रहण के भाव बढ़ाने की डिमांड से भी पर्चा निकाल कर प्रचार किया गया।

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का संदर्शन प्रोग्राम हुआ फेल

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सारण्डा पैकेज जैसे पैकेज को लेकर फरवरी 15 को नुआपाड़ा के सुनाबेड़ा में आने की योजना प्रशासन के साथ बनाया था। सुरक्षा का हवाला देकर इसे पहले सुनाबेड़ा से बुरकोट, बाद में नुआपाड़ा को ही सीमित कर दिया गया। इस यात्रा के खिलाफ सुनाबेड़ा एसी इलाका में पोस्टर, बेनर पर्चो से विस्तृत प्रचार किया गया जैसे संदर्शन से पहला - सेंचुरी हटाओ! रोड नहीं - घर और पीने का पानी चाहिए, मोबाईल टावर नहीं - अस्पताल में दवाई व डांक्टर चाहिए, मुफ्त में सामान नहीं- हमें मूलभूत अधिकार चाहिए, पहारियों को जनजाति में शामिल करो। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार चाहिए आदि डिमांडों पर जनता में पर्चा, पोस्टर, बेनरों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रनिक मीडिया व्दारा विस्तृत प्रयास किया गया। इस से मंत्री की आम सभा को कोई नहीं गया।

सरकारी झूठे विकास की पोल खोली सुनाबेड़ा जन जागरण मीटिंग ने

सुनाबेड़ा सेंचुरी में माओवादियों के प्रभाव से पिछले कुछ सालों से विकास कार्यो ठप पड़ा हुए हैं का राग पटनायक सरकार ने अलापना चालू किया. योजनाओं को लागू करने के लिए केन्द्र की मदद के लिए ओड़िशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुहर लगायी तो तुरंत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नुआपाड़ा आकर दो बटालियन अर्ध सैनिक बल और 110 करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा कर दी.

असलियत तो कुछ अलग ही है। पिछले दो सालों से सुनाबेड़-सोसेंग पंचायत की जनता कई बार रोजमर्रा की समस्याओं और कुछ बुनियादी सुविधाओं जैसा कि - सिंचाई पानी, दवाखाना को दवाईयों की सप्लाई, डॉक्टर की नियुक्ति, एंबुलेस की रिपेरिगं, तेंदुपत्ता फड़ी खोलने की समस्या के समाधान के लिए अपने जन प्रतिनिधियों को कलेक्टर के पास भेजा था। अभी तक इनमें से कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। सरकार के इस जनविरोधी रवैये के खिलाफ दोनों पंचायतों की जनता ने मार्च 8 को सुनाबेड़ा में जन जागरण मीटिंग आयोजन करके विरोध जताया। इस मीटिंग में लगभग 1500 जनता हजिर हुई। इसमें 700 महिलाओं ने भी भाग लिया व 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया.

निर्दोष बाबेघाट आदिवासी जनता पर पुलिस ने की गोलीबारी : दो जन घायल

नुआपाड़ा डिवीजन में पुलिस जुलुम-अत्याचारों के खिलाफ डिवीजनल कमेटी ने बंद का आव्हान दिया था. इसे विफल करने के लक्ष्य से दोनों राज्यों के पुलिस बलों, सीआरपीएफ व एसओजी ने संयुक्त अभियान मैदानी और जंगली इलाके में तीन दिन पहला से ही शुरू कर दिया था. बंद सफलता पूर्वक होने के एक दिन बाद 7-1-2013 को तरबोड़ पंचायत के बाबेघाट गांव की जनता हमेशा की तरह तालाब में मछली पकड़ने गयी हुई थी. सरकारी आतंकी पुलिस बलों ने जनता को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की. इसमें दो आदिवासी गंम्भीर रूप से घायल हो गए. इनमें से एक के हाथ में गोली लगी जिस कारण उसका हाथ टूट गया तो दूसरे व्यक्ति को एक गोली पांव में तो दूसरी पेट में लगी. आम ग्रामीणों पर गोली चलाकर बाद में मीडिया में प्रचार किया गया कि माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बीच में फंसकर दो ग्रामीण घायल हुए हैं.

इस झूठी मुठभेड़ का खंडन करते हुए डीवीसी ने अपील जारी ी कि जनता में दहशत फहलाने के लिए जानबूजकर फायरिंग की गयी है, वहां कोई मुठभेड़ नहीं हुई, सभी को चाहिए कि वह इस झूठी मुठभेड़ का विरोध करें, घायलों को मदद दें व घायलों के उचित उपचार के अलावा समुचित मुआवजा देने के लिए भी डिमांड करे. दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा दें।

जिला के कुछ वकीलों, बुध्दिजीवियों और आदिवासी संगठनों ने मिलकर एक जांच कमेटी गठित कर - जाँच पड़ताल के बाद तरबोड़ पुलिस थाना में केस दर्ज किया। मीडिया के जरिये सरकार से डिमांड किया कि घायल आदिवासियों को उचित और सही उपचार दिलाए जाए और पांच लाख मुआवजा दिया जाए। उनका कहना था कि आम जनता पर माओवादियों के नाम पर फायरिंग करना गलत ही नहीं अपराध ही है। यहा सरासर कानून का उलंघन हैं। इस घटना को न्यायीक जांच करके दोषी पुलिस कर्मियों पर कारवाई की जानी चाहिए।

झूठी मुठभेड़ों में हत्याओं के खिलाफ सीआरबी बंद का आह्वान नुआपाड़ा में भी हुआ सफल

बस्तर के सुकमा जिला के पूवर्ति गांव में ग्रेहाउंडस बलों साहित छत्तीसगढ में तैनात अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों व कोया कमांडो के साथ मिलकर एक बडा संयुक्त अभियान चलाया गयाा २६ अप्रैल को मुखबिरों की सुचना पर हमला किया गया जिसमें एक राज्य कमेटी सदस्य साहित नौ कारमेड शहीद हुए. इसी तरह से जनवरी से लेकर अप्रैल तक महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में भी कई साजिशपूर्ण झूठी मुठभेडें सी-६० कमांडो व सीआरपीएफ अधिकारियों व्दारा रची गयी जिनमें १७ कामरेड शहीद हुए. इन झूठी मुठभेडों में हत्याओं के खिलाफ मध्य रीजनल ब्यूरों ने आंध्र, छग, ओड़िशा, महाराष्ट्र में अप्रैल 25-26 को दो दिन बंद का आव्हान दिया था। इस बंद को सफल बनाने के लिए डिवीजनल कमेटी अपनी जनता को आव्हान दी। धौवलपुर-मैनपुर मार्ग पर फारेस्ट डिपार्टमेंट के नाका को बंद करके एक नकली (डम्मी) बूबि ट्राप लगाया था। इससे 26 को दुपहर 12 बजे तक रोड़ पर वहानों का आवागमन बंद रहा और आंदोलन के इलाका में छोटा व्यवसाई, पेट्रोलपंप, स्कूल आदि बंद में शामिल रहे, कुल मिलाकर बंद सफल रहा।

दमन

डिवीजन में पिछले छ: महिनों से लगातार कुम्बिंग चालू है। पाहड़ के निचले मैदानी इलाका के गांवों में तो और भी ज्यदा चल रही है। कुम्बिंग के लिए नजदीकी कैम्प से कम से कम एक कंपनी की संख्या में वाहनों में अनुकूल जगह तक आकर वहां से आपस में 20-30 जन एक ग्रुप बनकर पैदल ही जंगल के अंदर घुस कर सर्चिंग कर रहे हें। कुंबिंग सर्चिंग, गस्ती हो या जंगल में घुसे हों, अगर जनता मिल जाती है तो उसे बंदी की तरह अपने पास रखते हैं. रातों रात आना जाना कर रहे है। दस्ता आने -जाने की संभावित जगहों पर एम्बुश बैठना, जंगल का रास्ता छोडकर नदी-नाला, जंगल-पाहड़ में ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की मद्द से घूम रहे हैं ।

सुनाबेडा में कैम्प लगाकर मार्च 28 से लेकर अप्रैल 8 के बीच इलाका में कुम्बिंग चलाये। इस कुंबिंग में 150 के लगभग बल हिस्सा लिये। गांव के चारो ओर सेंट्री

लगाकर दिन-रात सर्चिंग करना, रात के समय जगह-जगह पर एंबुश बैठे। आखरी दिन सिविक प्रोग्राम चलाये। अगले ही दिन दस्ता गांव में आया समाचार मुखबिरों से मिलते ही फिर 12 को आकर दो दिन कुम्बिंग चलाये।

धर्मबंदा इलका में छत्तीसगढ़, ओड़िशा रज्य के पुलिस अप्रैल 11 से 17 के बीच संयुक्त अभियान चलाये। कंपनी संख्या में आई पुलिस आपस में कई बैच बनकर एक बैच पहाड़ पर तो दूसरी निचले हिस्से को कवर किये. अगर एक बैच एम्बुश में फसे तो दूसरा बैच तुरंत मदद में पहुंचने की दूरी में रह रहे हैं। अगर दस्ता का पता चला तो हमला करने, उसे घेरने का प्रयास कर रहें है।

डिवीजन के तीनों इलाकों में अप्रैल माह में दो बार दोनों राज्यों के पुलिस बल संयुक्त अभियान चलाये हैं। इस दैरान जगह-जगह जनता को मारपीट किया हैं। बुरकोट में 2013 मई महीने के 25 से जून 10 के बीच लगभग 150 सीआरपीएफ बलों से कैम्प लगाकर सर्चिंग, कुम्बिंग चलाई गयी। बुरकोट होते हुए सुनाबेड़ा, सोसेंगा पंचायत के गांव के आने वाली जनता को बार-बार चेकिंग करके जनता में भय पैदा करने की कोशिश जारी हैं। पाहड के निचले हिस्से में अविराम अभियान चला रहे हैं कभी वेन में तो कभी मोटर साईकिलों पर सवार हो कर आ रहे हैं। दस्ता के समाचार मिलते ही बड़ी संख्यां में कई बैचों में आकर जंगल में पानी की जगह, पुराने डेरों की तलाश कर रहे हैं। इस तरह कुंबिंगो में तेजी लाकर पार्टी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो भी जनता ने संघर्ष की राह में आगे ही बढ़ रही है।

सिविक एक्शन प्रोग्राम :

इस डिवीजन की जनता कई सालों से सेंचुरी और अन्य समस्यओं के खिलाफ लड़ रही है। जनतको गुमराह करने के लिए आर्थिक लालच दिखाके मुठ्ठी भर लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए दोनों रज्यों की सरकारें इस साल सिविक प्रोग्राम चलाने पर ज्यादा जोर लगा रही हैं। मार्च और अप्रेल माह में तीनों एसी इलाको में खासकर सुनाबेड़ा और धर्मबांदा और उसके आसपास के गांवों में थोड़-थोड़ा अंतराल के बाद चलाया। इस दैरान छात्र-छात्राओं और युवाओं पर केंद्रित करके अपना ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास किये। इनकी खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाकर इनाम बांटे गए। आम जनता को कपड़ा, बर्तन, सिलाई मशीन, किसानों को कृषि औजर दिये। कुछ जगह मेडिकल केंप लगाकर दवाई दिए हैं। शिविर चलाने से दो दिन पहला से ही पूरे इलाका में कुम्बिंग चलाकर जनता पर दबाव डालकर भय पैदा करते हैं. इस मोके को इनफर्मर नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जनता को जमा करके मीटिंग चलाकर पार्टी के खिलाफ दुश्प्रचार कर रहे हैं।

तेंदुपत्ता संघर्ष

डिवीजन के इलाका में सुनाबेड़ा-सोसेंग पंचायत इलाका सेंचुरी में आने बाद से तेंदुपत्ता फड़ी खोलना बंद किया कर दिया गया है. पिछले कुछ सालों से सेंचुरी के खिलाफ जनता संघर्ष कर रही है। फड़ियों को फिर से खोलने के लिए लगभग 500 जनता नुआपाड़ा जाकर कलेक्टर से गुहार लगायी कि सीजन में तुरंत तेंदुपत्ता फड़ी खोले - आश्वासन तो मिला मगर फड़ी नहीं खोली गयी। भैंसादानी पंचायत के पाटदरहा गांव पहाड़ पर स्थित है। तो यहां भी कोई न कोई बहाना बनाकर नहीं खोली जा रही. जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस इलाका में तुरंत फड़ी खोलने के लिए बोड़ेन ब्लाक में तहसिलदार को डिमांड पत्र सोपां गया। साथ ही बढ़ती मंहागाई के हिसाब से तेंदुपत्ता संग्रहण मजदूरी बढ़ाने का भी डिमांड किया। इस साल गड्डी सेंकड़ा 130 रु. और संग्रहण के दौरान घायल होने से उचित इलाज 2 लाख और मर जाने से पांच लाख की भी डिमांड किया गया है। धर्मबंदा इलाका की जनता भी मार्च महिनों में मांगपत्र कलेक्टर को देकर मजदूरी भाव बढ़ाने की डिमांड की. गरियाबंद इलाका में सेंकड़ा 160 रु डिमांड किया गया। पुरा डिवीजन में हजारों पर्चा, पोस्टरों से प्रचार किया गया। और कुछ जगहों में संघर्ष फड़ी स्तर पर संगठित किया गया। इस साल ओड़िशा में 100 से 120 तक बढ़ा है। छग में 140 हुआ।

मुखबिर - जन अदालतों के कटघरे में

दुश्मन ने पार्टी और जनांदोलन से जुडे समाचार जुटाने के लिए हर गांव में मुखबिरों की तंत्र तैयार कर रहा है। गांव-गांव में गुण्डों, आवारा तत्वों और बेरोजगार युवाओं को नैकरी का झांसा देकर मुखबिरी के लिए तैयार कर रहे हैं। कोलिभीतर एरिया में भैसाधानी पंचायत के कुछ गांवो में शिक्षित युवाओं को पुलिस में भर्ती होने के लिये दस्ता का समाचार देने के लिए तैयार किया है। आममोरा पंचायत में अभियान के दैरान कुछ लोगों को फोन नं देकर और एक व्यक्ती को कुछ लालच दिखा कर दस्ता का समाचर देने से आर्थिक और सरकार से कुछ मददत चाहिए तो फोन करो करके नम्बर दिया। धर्मबंदा इलाका में मुढ़ीपानी पंचायत में भी एक व्यक्ति को इसी तरह तैयार किया गया है। इन सभी के व्यवहार में इस बीच आये बदलाव को जनता ने पहचान कर पर्टी को सूचित किया कि इन लोगों से गांव को खतरा है, तो सभी को बुलाकर जनता के सामने पूछताछ किया तो सभी ने अपनी-अपनी गलती को मानकर गांववालों से माफी मांग कर आगे से जनता के साथ मिलकर रहने का आश्वासन दिया. परिवार वालों ने भी भरोसा दिया तो जनता ने चेतावनी देकर सबको बरी कर दिया।

झुठे सुधार कार्यक्रमों का विरोध करो - संघर्ष का रास्ता चुनो

बलांगीर-बरगढ़-महासमुंद डिवीजन में पुलिस दमन

डिवीजन में बढ़ते जन संघर्ष को रोकने के लिए पुलिस दमन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओड़िशा के डीजीपी प्रकाश मिश्रा बार-बार कह रहा है कि 8 जिलाओं में माओवादिओं का सफाया हो गया है। इन 8 जिलों में स्थित फोर्स को आवश्यकता अनुसार तैनात किया जाएगा। इस योजना के तहत बड़े पैमने पर फोर्स की तैनाती की जा रही है। 19 अप्रैल 2013 को बरगढ़ जिला के बर्तोंडा गांव में सिर्फ गांव के जमीनदार की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल के 100 से ज्यादा जवान तैनात किये गए। इसी जिले में जगदलपुर पुलिस थाना में 50, केर्मीली के विजय रंजन सिंह बरिया मंत्री स्थानिक विधायक के गांव में 50, बलंगीर जिला के लाटुर में 100 केन्द्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुराने थानों, पुलिस कैम्पों में 20-30 संख्या से 50 से 100 तक बढ़ा दिया है । इसी तरह पदमपुर और पईकमाल में भी 100 से ज्यादा सीआरपीएफ बल तैनात किया गया है। और भी कुछ जगहों में कैम्प लगाने की चर्चा हो रही है। ग्रीनहण्ट अभियान और एलआईसी पॉलिसी के तहत डिवीजन में सिविक एक्शन प्रोग्राम, पुलिस, होमगार्ड-एसपीओ में भर्ती और झूठे विकास सुधार योजनों लागू करने की भरसक कोशिश जारी हैं।

सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जगह-जगह प्रोग्रामों के आयोजन कर रहे है। प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण खेल कूद आयोजन नहीं करते बल्कि अभी पुलिस अधिकारी ग्रामीण और छात्रों के खेलकूद टुर्नामेंन्ट आयोजित करवा रहे हैं। इस के लिए आवश्यक खर्च पुरस्कार पुलिस अधिकारी ही दे रहे है। इन खेलकूदों से युवाओं को पुलिस होमगार्ड, एसपीओ, मुखबिर काम के लिए चुना जाता है। स्थानीय लोगों पर ही इस के लिए ध्यान केन्द्रीत किया जा रहा है. यह प्रक्रिय लगातार जारी है. हर गांव से 3 से 5 युवाओं को एसपीओ मुखबिर बना कर प्रति माह वेतन दे रहे हैं। और फ्री में मोबाईल भी दे रहे हैं। इस तरह के युवाओ को योजनाबद्ध तरीके से नौकरी में भर्ती करवा रहे हैं ताकि उस कवर में रह कर काम कर सकें। उदाहरण के लिए ग्राम पाटपेन में नुआपाड़ा एसपी उमाशंकर दास के नेतृत्व में 4 युवाओं को एसपीओ के रुप में तैयार किया गया। ये लोग सीधे एसपी के संपर्क में रहते थे। इन 4 युवाओं में एक चेतन 12वीं तक पढ़ाई किया था. चेतन को पुलिस अधिकारी ने ही शिक्षक पद पर नियुक्त करवाया था। इन एसपीओं को एक बार चेतावनी भी दी गयी और एक बार जन आदलत में पीटा भी गया था। इसके बावजूद भी एसपीओ का काम करते रहे इस कारण हमारी पीएलजीए को चेतन का सफाया करना पड़ा। अभी प्रचार यह हो रहा है कि माओवादीओं ने एक शिक्षक की हत्या कर दी। लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षक की आड़ में चेतन एसपीओ का काम कर रहा था।

पुलिस की गस्ती में भी बदलाव देख सकते हैं. कभी तीन दिन या सप्ताह 10 दिन का गैप देकर लगातार गस्ती जारी हैं। एक बैच दूसरे को सपोर्ट देते हुए तीन से पांच बैच आ रहे हैं। कभी-कभी 2-3 जिला या दो राज्य बल भी समन्वय से गस्त कर रहे हैं। लोगों को जगंल में न जाने की धमकियां दी जाती हैं। जंगल में मिलने से जनता की पिटाई करते हैं। जंगलों से जनता को वनोपज संग्रह करना छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। अब नये एसडीपीओ, डीएसपी अधिकारियों की नियुक्ति के बाद गस्ती में और तेजी आई. इसके साथ जंगल के अंदर दूर तक भी गस्त कर कर रहे हैं। जीपीएस के माध्यम से दिशा निर्धारित कर सीधा पहाड़ों में भी आना जाना कर रहे हैं। बीच जंगल में रह कर खाना पकाकर खाते हुए कुंबिंग कर रहे है। और जंगल में भी 2-3 दिन रह रहे हैं। हमारी पार्टी और पीएलजीए को नुकसान पहुचांने के लिए रात कोलि चुप-चाप आकर गांवों के किनारे, रास्तों में, स्कूल बिल्डिंगों के ऊपर चढ़कर रहना, एम्बुश बैठना आदि भी जारी है। 10-15 मोटर साईकिल, बोलेरो, बसों का भी गस्त में उपयोग किया जाता है।

पिछले साल सितम्बर महीने में बलंगीर, बरगढ़ जिलों में शुरू हुई गिरफ्तारियों में कुल 35 निर्दोष ग्रामीणों को माओवादी के नाम से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनमें से 21 लोगों को छोड़ दिया गया। बाकि 14 लोग अभी भी पुलिस हिरासत में ही हैं। फर्जी केसों में फसाकर सजाए देने की सरकार का साजीश चल रही है।

मार्च महीने के पहले सप्ताह में बरगढ़ जिला में पैकमाल ब्लाक के नजदिक स्थित ग्राम सत्राहबेरा में एक गूंगे युवक को गस्त में आए सीआरपीएफ वाले पकड़ कर ले गये। ग्रामवासियों के यह कहने के बावजूद कि यह युवक गूंगा है और हमारे ही गांव का है, माओवादी के नाम पर ले गया बुरी तरह यातनाएं देकर युवक को मार डाला. इस हत्या के विरोध में हजारों लोग एकित्रत होकर पैकमाल से पदमपुर जाने वाले रोड़ पर चक्का जाम किये, पुलिस वालों के हस्तेक्षप करने पर उनकी भी जमकर पिटाई किये।

कोई भी मरणासन्न वर्ग आसानी से सत्ता नहीं छोड़ता,सत्ता का जन्म हमेशा बंदूक की नली से होकर गुजरता है!
जनता ही इतिहास की असली निर्माता है!!
यदि जनता के पास जनसेना नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं!!

ओड़िशा के कंधमाल, गजपति, गंजाम, रायगढ़ जिलों में क्रूरता के साथ जारी है ऑपरेशन ग्रीनहंट का हमला !

नियमिगरी बाक्साइट खनिज को वेदांता को सौंपने के लिए सारंडा के आपरेशन अनकोंडा की तर्ज पर जारी सैनिक हमले का विरोध करो !

सब्यसाची पंडा ने दक्षिण पंथी, सुधारवादी रवैया अपना के पार्टी, जनता और जनांदोलन को धोका देकर-ओड़िशा माओवादी पार्टी खड़ा करने के बाद से खुले आम हमारा पार्टी का आलोचना करना, बेबुनियाद (निराधार) मनगढ़ंत कहानियों से कल्पनाओं से भरा बयानों को नियमित रूप से प्रेस को जारी करना आदि कुटील प्रचार चला रहा हैं। इस तरह वह दुश्मन का दुष्प्रचार को अपना गला देकर सुधारवादी पंडा शासक वर्ग और पुलिस के हाथों में एक औजार बना हुआ है।

इस मौके का फायदा उठा कर हाल ही में पदभार संभाले डी.जी.पी प्रकाश मिश्रा ने पंडा के ओर से अलग गुट बनाने को सराहा/ इस से ओड़िशा राज्य में जन मुक्ति छापामार सेना का हमलाओं में कमी आयेगी और पंडा के प्रति नरम रवैया अपनाने और माओवादी पार्टी और उसका आला नेतृत्व के प्रति सख्ती रवैया अपनाने और आपरेशन ग्रीन हन्ट में तेजी लाने के तहत ही ''आपरेशन सब्यसाची'' को चलाया जा रहा है करके भी जाहिर किया। मगर ध्यान देने वाली बात यी है की इस चार जिलाओं में पहले से ''आपरेशन माओइस्ट'' चला रहे हैं।

इस चार जिलाओं में हमेशा एरिया डामिनेशन चलाते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का सिर पर रिवार्ड (इनाम) एलान करके दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के तरह आत्मसर्म्पन, पुनरावास, हर माह वेतन का पॉलसी का भी राज्य सरकार द्वारा घोषिणा किया गया है।

नियमगिरि विस्थापन विरोधी जनांदोलन को कुचलने के लिए (केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने) एक तरफ इस आंदोलन का नेतृत्व दे रही पार्टी का सफाया करने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा कई बार एरिया डामिनेशन आपरेशनों और नियमगिरि (लांजीगढ़) इलाका में तेज किया गया है। दूसरी ओर जयराम रमेश द्वारा सरांडा जैसे यहां भी सैनिक अभियान के साथ-साथ अधिक सुधारों के लिए 300 करोड़ का पेकेज का घोषणा किया है।

हाल ही में अपना एक बयान में डी.जी.पी ने कहा ओड़िशा राज्य में माओवादियों का प्रभाव 18 जिलाओं से 12 जिलाओं में घटकर रह गया है। एस. ओ.सी (राज्य संगठनिक कमेटी) इलाका के कंधमाल, रायगढ़ा में सक्रिय है। इन दो जिलाओं से माओवादियों को खदेड़ने का योजना बनाने का भी एलान करते हुए नियमगिरि काशीपुर इलाका में आन्ध्रा-छत्तीसगढ़ से आये लोग काम कर रहे हैं। इनको कुचलने के लिए आन्ध्रा-ओड़िशा के ग्रेहाउंड्स, एस.ओ.जी बलों के संयुक्त अभियानों के लिए एक कार्य योजना बनी है। और नारायण पटना से लेकर नियमगिरि तक कार्पेट सेक्युरिटी को मजबूत करते हुए दरसाल में नियमगिरि, त्रिलोचनपुर, कोटा मावी, कुरली कमवेशा में सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय सुरक्षा बलों का कैम्प तैनात कर विस्थापन विरोधी आंदोलन को कुचलने का ही प्रकाश मिश्रा का असली कार्य योजना है।

कंधमाल, गंजाम, गजपति व रायगढ़ जिले में पुलिस दमन व जनप्रतिरोध

इन जिलाओं से माओवादी पार्टी का सफाया करने के लिए अर्द्ध सैनिक बलों के कई कैम्प तैनात ाकर सैकडों के तादाद में पुलिस अर्द्ध सैनिक बलों ने गांव पर हमला करना कूम्बिंग चलाना आम सा हो गया है। इसी सिलसिले में कूम्बिंग के लिए आए बलों पर जन मुक्ति छापामार सेना (पी.एल. जी.ए) द्वारा जनवरी 2012 को किए गए एक हमला में तीन पुलिस मारे गए और तीन घायल हुए। इस घटना से संबंध होने का आरोप लगाकर जिला परिषद सदस्या दाड़ींग बाड़ी निवासी जुनुस प्रधान, सोनपुर बी.जे.डी सरपंच मनमोहन प्रधान और मुरकू गांव के सुनेश्वर मांझी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। क्योंकि इन तीनों ने ही जनता का साथ देकर दमन के खिलाफ खड़ा हुए थे। इस तरह केरूबड़ी गांव के व्यापारी नीरा कांत प्रधान को अरेस्ट करके हिरासत में यातना देकर बाद में जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद वह जेल में ही दम तोड़ दिया। माओवादी के समर्थन के नाम से गंजाम जिला में बड़गड़ में एक तुमिड़ीबंद में एक छात्र को, रायगढ़ जिला से डेम्बगुड़ा से एक श्रीरामपुर से एक 55 साल का एक व्यापारी, रोमनबड़ा सेठ को गिरफ्तार किया है। अंदरूनी गांवों से सात जन को, मुरगुड़ी से एक श्रांभी गांव से तीन जन, गुकूमा से एक, पहाड़ी पंगा गांव से एक, लंचावल्ली से तीन जन, मज्जीगुड़ा से एक जन को गिरफ्तार किया। इस कूम्बिंग के दौरान घरों को तोड़ फोड़ कर महिलाओं के साथ दुरव्यवहार करना, बलात्कारी भी किया। सोना, नगदी पैसा का लूटपाट, महिलाओं से छेड़छाड़ भी किये। जनता को श्रीरामपुर कैम्प लेजाकर दस्ता का डेरा दिखाने के नाम से पिटाई

भी किया। दूसरी ओर एल.आई.सी पॉलसी के तहत जनता को लुभाने की मन से तो कभी जन सम्पर्क के नाम से तो कभी कौसीलिंग नाम से सिविक प्रोग्राम आयोजन करके जनता को मुफ्त में कपड़ा, छत्ता, कम्बल जैसे सामान, बांटन, बेरोजगार युवाओं को आकर्षित कर मुखबीरी के लिए तैयार करने की कोशिश करना, कहीं-कहीं जनता सामान लेने से इन्कार कर रही है। कुछ जनता को आर्थिक फायदा पहुंचाकर अपने तरफ मोड़लेने को एक छोटा सा सेक्शन को शासक वर्ग का सामाजिक आधार बनान के लिए ही यह प्रयास है। छलकपट मानसिक युद्ध के तहत पिछले एक साल से गांव से सटे जंगल में डेराओं पर हमला का नाटक चलाकर माओवादी भाग गया, डेरा से क्लेमोर, साहित्या और रोजमर्रा का सामान जप्त किया गया करके प्रचार बार-बार किया जा रहा है। गजपति, गंजाम जिला को माओवादियों से मुक्त किया गया करके प्रचार किया जा रहा है। अरेस्ट किये गये जनता को हमारे पार्टी से गद्दारी कर भागे हुए सब्यसाची पंडा के पार्टी में शामिल होकर माओवादी पार्टी का विरोध करो कहकर धमका रहे हैं। मजे की बात यह है कि खुद पुलिस ओड़िशा माओवादी पार्टी के नाम से माओवादी जहां पंडा ग्रुप का नामोनिशन नहीं है वहां पर्चा, पोस्टर लगाकर दुष्प्रचार कर रहा है। कुछ लोगों को माओवादियों का समर्थन बंद करो नहीं तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो करके धमका रहे हैं।

जनता में दहाशत फैलाने के लिए 6 नवम्बर 2012 को गजपति जिला के बनिया गुड़ा से दो किलोमीटर दूरी पर जंगल में पांच जन ग्राम वासियों को ओड़िशा माओवादी पार्टी का सदस्य बताकर झूठी मुठभेड़ में हत्या किया। मार गए सभी कंधमाल जिला ग्राम दाड़िंगबाड़ी और ब्रम्हणी गांव ब्लाक के है। मारे गये सदस्य का नाम इस प्रकार है।

1. सिकरामसिंह (32) मद्दिवंक गांव निवासी
2. श्यामसन कुर्ज्जी (58) बिरिंग गुड़ा निवासी
3. एवीचन्द्र
4. लक्ष्मीकांत नायक (30) लुजरी मुंडा गांव वासी
5. सन्नोत मल्लिक (30) गयोज गांव वासी है।

इन में से दो जन ग्राम पंचायत सदस्य है। इस झूठी मुठभेड़ को ओड़िशा सर्वोदय संगठन बर्त्सना करके सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कमेटी गठन किया। इस कमेटी ने गांव में जाकर छानबीन किया। बात में खुलासा में कहां की सभी को अपने-अपने गांव से एक दिन पहले ही हिरासत में लेकर यातना देने के बाद हाथ, पांव, बांध कर निहत्थे लोगों का मुठभेड़ के नाम से हत्या किया गया। इस झूठी मुठभेड़ के खिलाफ कई जन संगठनों ने मिलकर नवम्बर आखिर में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया और भुवनेश्वर में एक सभा आयोजित किया। बाद में मुख्य मंत्री से मुकदमा दर्ज करने और मृतक परिवारों को मुआवजा देने के लिए मांग किया।

इस झूठी मुठभेड़ के खिलाफ भा.क.पा (माओवादी) पार्टी नवम्बर 25 को कंधमाल, गंजाम, गजपति और रायगढ़ जिला में बंद का आह्वान किया जो अंशिक रूप से सफल रहा।

नियमगिरी, काशीपुर में आपरेशन ग्रीनहंट

ओड़िशा के रायगढ़ा , कलहंडी और कोरापूट तीन जिलाओं का सरहद अंचल का विशाल इलाका ही नियमगिरि काशीपुर यह सात पहाड़ों से सजे इलाका है। यह घने जंगल, समतल इलाका है। यहां पर खासकर कुई (कुव्वी) नामक आदिवासी समुदाय रहता है। साथ ही सौंरा, जोड़िया के अलावा दलित और ओडिया के अलग-अलग जाती के जनता भी रहते हैं। सात पर्वत मालाओं का नाम है सी.जी माली, कुटूमाली, केड़माली, डोंगमाली, कोंडव माली, संगु माली, सासे माली यह माली पहाड़ों में बाक्साइट खनिज भरी है। इसीलिए इस पर कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसे वेदांत, उत्कल, हिन्डाल्को गिद्धनजर पड़ी है। साम्राज्यवादियों के इशारा पर चलने वाली केन्द्र, राज्य सरकारें इन कम्पनियों के अलावा कई कम्पनियों से करार किया है। यहां की जनता खासकर आदिवासी इस करार के खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रहे है। इन कम्पनियों को पानी, आपूर्ति के लिए निर्माणधीन बांधों के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे है। कुछ इलाका में माओवादियों का नेतृत्व में भी जनता लड़ाई कर रही है।

यह पर्वत श्रृंखला बाक्साइट के अलावा और कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। नियमगिरि पहाड़ श्रृंखला लांजीगढ़ भीशमकचक कल्याणसिंहपुर इलाका से सटा हुआ है। लगभग 112 गांव में 7,000 कुव्वी (डोंगरिया कुचिया) आदिवासी दलित जनता रहते है। एक अध्ययन के अनुसार इस पर्वत श्रृंखला में 80 हजार मिलियान टन बाक्साइट मौजूद है। इसके अलावा आंध्र-ओड़िशा के जनता को सिंचाई व पीने का पानी के अलावा कई बड़े औद्योगिक इकाइयों को पानी का आपूर्ति यही से होती है। वंशदारा, नागवली नदियों का उद्गम यही से होता है। जहां से जंगलों में कई औषधिय गुण वाले पेड़- पौधे व फल-फूल एवं अनेक किस्म के जंतू का आश्रय स्थल है। अनेक प्रकार के धान उत्पादन करने वाला सहज आर्थिक व्यवस्था, पुरातन आदिवासी संस्कृति रीतिरिवाज परंपरा अविरत है।

इस बाक्साइट पहाड़ श्रृंखला पर वेदांत के मांग को केन्द्र, राज्य सरकारें जी हुजूरी करके मान लिए। मगर जनता उस के लिए तैयार नहीं है। खुद को नियमगिरि समिती के रूप में संगठित कर संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को देश विदेश के कई पर्यावरण विधोने भी अपना समर्थन जता कर सरकारी नीतियों पर सवाल खड़ा किया। परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार ने सक्सेना कमेटी का गठन किया। जो वेदांत परियोजना को अनुचित करार दिया जिसके इसके खिलाफ में

वेदांत और राज्य सरकार मिलकर सर्वोच्च न्यायलाय में खनन जारी रखने के लिए पिटीशन दाखिल किया जो सर्वोच्च न्यायलाय ने 17 अप्रैल 2013 को ग्राम सभाओं का अनुमोदन के बाद ही करना है करके आदेश दिया। यह आदेश सीधे तौर पर नहीं बल्कि गुमराह कर जनता को धोका देने वाली है। इस निर्णय के खिलाफ जागरूख नियमगिरि सुरक्षा समिती, माओवादी पार्टी और कई जन संगठन मिलकर संघर्ष कर रहे है। नियमगिरि से लेकर काशीपुर तक की जनता बाक्साइट उत्खनन के खिलाफ ही नही जल-जंगल-जमीन पर अधिकार के साथ-साथ रोजमर्रा के समस्याओं पर जनता माओवादी नेतृत्व में लामबंद होकर लड़ रहे हैं। इसी लिए शासक वर्ग माओवादी पार्टी को विकास के लिए सबसे बड़ी खतरा के रूप में दुष्प्रचार कर रहे हैं और पार्टी का सफाया करने आंध्र-ओड़िशा आंदोलन के बीच समन्वय को तोड़ ने के लिए बड़े-बड़े आपरेशन चला रहे हैं।

अब तक इस इलाका में 5 बार बड़ा आपरेशन चलाया गया। पहली बार 2012 फरवरी 20 से मार्च 10 तक, दूसरी बार नवम्बर 14 से दिसम्बर 10 ते, फिर दिसम्बर 18 से 27 तक 27 दिसम्बर के दिन पी.एल.जी.ए द्वारा एक पुलिस की टुकड़ी पर किया गया हमला के बाद बीच में ही सारे बलों को वापस बुला लिया। 2013 मार्च अप्रैल के बीच 20 दिन का एक आपरेशन चलाया गया। कूम्बिंग के दौरान पिछले एक साल से नियमगिरि इलाका में निगरानी बढ़ाया गया। मुन्नीगुड़ा, लांजीगढ़ और कल्याणसिंहपुर सेंटर के रोड़ पर तलाशी के नाम से आने-जाने वाले जनता को परेशान करना शक होने पर माओवादी का सामान ले जा रहे हैं कह कर धमकियां देना पार्टी के हमदर्दी होने के नाम से इलाका से बहिष्कार (तड़ीपार) कर रहे हैं।

आंदोलनरत इलाका में सप्ताहिक बाजार जाने वाले जनता को पकड़ कर कुछ को मुखबीर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। दवाई और सामान खरीदने वाले को अरेस्ट करके पूछ-ताछ के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं।

नियमगिरि को घेरने का आपरेशन में हजार से पंद्रह सौ तक सी.आर.पी.एफ और एस.ओ.जी भाग लेते हैं। यह आपरेशन रायगढ़, कलहंडी पुलिस अधिक्षकों के संयुक्त मार्ग दर्शन में चलाया गया। आपरेशन को रायगढ़ा को अड्डा बनाकर संचालन नियंत्रण किया गया। रायगढ़ा से पुलिस बल को रातों रात वाहनों से मुन्निगुड़ा त्रिलोचनपुर, कल्याणसिंहपुर रोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं। सभी टीम समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं। हर टुकड़ी कम्पनी फारमेंशन में आते हैं। कुछ बैच माली, पहाड़ों पर रह कर निगरानी किया करते हैं। कुछ बैच गांव के अगल-बगल में चेकिंग करना और कुछ बैच रास्ता पर एम्बुश बैठना करते हैं। पूरा बल तीन दिन कि लिए अपना खान पान साथ में लाते हैं। कम्पनी हो या प्लाटून फारमेंशन में आने से भी 3,4 पुलिस एक छोटा टीम रहते हैं। जो अपने लिए चाय, नास्ता बनाते हैं खाना में ज्यादातर फास्ट फुड लाते हैं। ताकि जल्दी तैयार करने में आसान हो। पुराने बैच जनता का ध्यान भटकाने के लिए खुलेआम नीचे उतरते हैं तो नया बैच गुप्तरूप से जंगल के अंदर घुस जाता है। नियमगिरि और त्रिलाचनपुर सेंटर से अंदर घुसा बल कुन्नाकड़, लक्कापोदर, लम्बागुम्मा, पारसेंली गांव पर हमला किया तो राजुल गुड़ा से प्रवेश किया बल सिरकेपाड़, जरपा, लक्कापोदर रास्ता के गांव पर हमला कर तलाशी के नाम से घर में घुसकर तोड़ फोड़ किया। तो तीसरा बैच चट्टी कोना की ओर से आया पुलिस सनडेंगली, लम्बागुम्मा, पारसेली गांव में हमला कर जनता को अरेस्ट करके लम्बा और गुम्मा जनता का राशन कार्ड जप्त किया और परंपरागत हथियार को जप्त करके ले गया।

2013 मार्च, अप्रैल के बीच में कैम्प लगा कर अगल-बगल गांव पर हमला करके गांव के जनता को अरेस्ट करके मारपीट किया। महिलाओं के साथ बद सलूकी किया। जन सम्पर्क नाम से शिविर लगाकर कपड़ा, कम्बल, छत्ता, आदि वितरण किया। जिसे कई जनता ने विरोध किया और कैम्प हटाने का मांग किया। 20 दिन के बाद कैम्प को हटा लिया गया। नारायणपटना क्षेत्र में एरिया डामनेशन अभियान चलाते समय रेलगाड़ी में सवार होकर जहां कही भी उतर कर कूम्बिंग चलाते है। यह काशीपुर तक विस्तार कर रहे है। पिकजिल और बासम माली शहीद दिवस (कॉ. रवि और नौ कामरेड्स का शहादत दिन) पर कई गांव में कूम्बिंग चलाया।

नियमगिरि में एरिया डामनेशन के समय पुलिस पी.एल.जी.ए का सफाया के लिए गांव को होकर जनता को बंधक बनाना एक साथ कई जगहों में एम्बुश बैठा तो भी जनता दुश्मन के आंख चुराकर पी.एल.जी.ए को दुश्मन के घेराव से बाहर निकाला जनता आगे रह कर दुश्मन के नपाक इरादों पर पानी फेर दिया। 2012 नवम्बर 17 को त्रिलोचनपुर नुवागुड़ा गांव पर पुलिस हमला किया रामदास और गजेंदर को अरेस्ट किया। ग्राम वासियों के विरोध करने पर गजेंदर को वही छोड़ दिया और रामदास को साथ में ले गया। दो दिन के बाद लगभग 500 करीब जनता लांजीगढ़ पुलिस थाना के सामने धरना दिया, बाद में पुलिस ने रामदास को रिहा किया।

बार-बार गांव से हमला करके जनता में दहाशत फैलाने वाले पुलिस को सबक सिकाने के लिए पी.एल.जी.ए ने डेंगिनेली जाने वाले रोड़ दिनांक 27 दिसम्बर 2012 को एम्बुश किया इस घटना में तीन पुलिस घायल हुए इसके बाद में सुब्बाराव और गड्डा नामक दो ग्रामीण को गिरफ्तार करके ले गया। अगले दिन लगभग 10 गांव के जनता कल्याणसिंहपुर रोड़ पर धरना दिया बाद में पुलिस थाना को घेराव किया तब दोनों को रिहा किया। इसी तरह कुरली, कम्बेशी में कैम्प लगाकर पारसेलीगांव के सरपंच गुड्डा और बादल नाम के युवा को अरेस्ट किया। तब मुन्नी गुड़ा गांव के जनता पुलिस स्टेशन में जाकर प्रदर्शन किया और अपनों को छुड़ा लिया।

महिलाओं के साथ छेड़खानी व गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रदर्शन

अपने धान का खेत में काम कर रहे अक्कारी गांव (पंचकुड़ी के बगल) पति पत्नी को पकड़ कर गांव ले जाकर ग्राम वासियों को घेरके सभी को निमर्म पिटाई किया कुछ महिलाओं के साथ बदसुलूकी की कुछ को अरेस्ट करके बिसम कटक स्टेशन ले गया। इस गिरफ्तार के खिलाफ पंचकुड़ी सहित आसपास के गांव के 70 के करीब महिलाएं थाना को घेरके गिरफ्तार साथियों को रिहा करवा लिया। लक्का पधार में 2012 दिसम्बर 11 को हमला करके तलाशी के नाम पर घर में घुस कर संभू नामक नवजवान को पकड़ कर पिटाई करना चालू किया। इससे गुस्साएं जनता ने कुल्हाड़ी लेकर पुलिस को घेरना शुरू किया जिससे पुलिस उल्टा पांव भाग खड़ा हुआ। अप्रैल 2013 में दूसरे बार एस.ओ.जी, सी.आर.पी.एफ मिलकर गांव को घेरकर दस्ता का समाचार के लिए पूछ ताछ किया उसी समय शिकार जंगल या ग्राम वासी वापस लौटकर आया जिन्हें पकड़ कर उनके पास से भरमार बंदूक छीन लिया तो जनता ने विरोध किया। जब पुलिस नहीं माने तो सभी ने कुल्हाड़ी लेकर घेरने से घबराई पुलिस ने जनता से माफी मांग कर वापस दे दिया।

जन संगठन के नेताओं की बार-बार गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रदर्शन

काशीपुर ब्लाक बारीगांव जन संगठन के नेता को 2013 फरवरी आखिर में कूम्बिंग के दौरान अरेस्ट करके अवैध रूप से हिरासत में रखा। जिसके खिलाफ जनता काशीपुर ब्लाक सेंटर जाकर पुलिस थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया बाद में सुरेंदर को अगला दिन कोर्ट में पेश किया।

एरिया डामिनेशन दमन के बीच सभा संपन्न

नियमगिरि, काशीपुर जनता बाक्साइट उत्खनन खिलाफ साथ ही साथ अनेक समस्या जैसे पुलिस दमन अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ, जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने के लिए और वन उपज का न्यूनतम मूल्य और कास्तकारी जंगल-जमीन पर पट्टा का हक मांगते हुए 2,000 करीब जनता लांजीगढ़ में 22 नवम्बर को और मुन्नीगुड़ा में 26 नवम्बर को आम सभा किया।

सर्वोच्य न्यायलय के फैसले के दिन लांजीगढ में जनता का प्रदर्शन

नियमगिरि पहाड़ की खदानों से बाक्साइट खनन के हक के लिए वेदांता कंपनी सुप्रिम कोर्ट गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम फैसला के लिए 10 दिसम्बर के दिन को निर्धारित किया गया था। ठीक उसी दिन इस इलाका के दलित आदिवासी जन संगठन ने मिलकर एक रैली और आम सभा आयोजित की। इस रैली जनता ने वेदांता को बाक्साइट देने का विरोध किया। और नियमगिरि पहाड़ आदिवासियों का है और रहेगा इसे किसी को देने का सवाल नहीं है का ऐलान किया। केन्द्र राज्य सरकारों से मांग कि वेदांता को यहां से हटाओ। इस सभा में 3,000 के आसपास जनता शामिल हुए।

नियमगिरी राजा पर्व धूमधाम से मनाया नियमगिरी की जनता ने

नियमगिरि पर्वत पर आसीन नियमगिरि राजा (देवता) ही डोंगरिया कुव्वी जन समुदाय का रक्षा कर रही है। करके यहां की जनता का विश्वास है। देवता का आशिर्वाद के लिए हर साल जनवरी फरवरी मह में तीन दिन का पर्व मनाते है। पिछले तीन सालों से इस पर्व को विस्थापन विरोधी दिन के रूप में मनाते आ रहे है। इस विरोधी दिन में राज्य और देश के कई विस्थापन विरोधी संगठन शामिल हो रहे हैं। विभिन्न संगठनों के बीच बढ़ती घनिष्ठ ता को देख कर घबराए सरकार इस बार इसे रोकने के लिए हर तरह प्रयास किया और इस पूरा क्षेत्र में कूम्बिंग को भी धिक्कारते हुए फरवरी आखिर में राजा का पर्व धूम-धाम से मनाया गया। इस पर्व में नियमगिरि आंदोलन को अपना समर्थन जताने लगभग 3,000 प्रतिनिधियो शामिल हुए थे।

इस दमन-घेराव का बीच ही नियमगिरि में अंग्रेज साम्राज्यवादियों के विरूद्ध लड़कर शहीद हुए आदिवासी नेता रेंडोंमाझी शहादत के दिन स्मृति सभा और बासंग माली शहीदों का संस्मरण सभा, मार्च 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभाओं में सैकड़ों जनता शामिल हुए है।

बासंग माली हत्याकांड में शहीद हुए नौ कामरेडों में चार महिला कामरेड्स है। इन महिला शहीदों का स्वस्थल बारी गांव स्मृति दिवस मनाते है। पिछले साल (2012 में) इस स्मारक को पुलिस ने तोड़ दिया। इस साल जनवरी माह में पुलिस कूम्बिंग के बीच ही एक गुप्त स्थान पर जनता जमा हो कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके शहीदों के राह पर चलने का संकल्प लिए है।

नियमगिरी की जनता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं!

नियमगिरी जन आंदोलन पर दमन के खिलाफ आवाज उठाओ!!

26 मई 2013 फासीवादी सलवा जुडूम के सरगना महेन्द्र कर्मा का सफाया – बस्तरिया आदिवासी जनता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों, नृशंस हत्याकाण्डों और बेअंत आतंक की जायज प्रतिक्रिया!

बड़े कांग्रेसी नेताओं पर हमला – यूपीए सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाए जा रहे फासीवादी आपरेशन ग्रीनहंट का अनिवार्य प्रतिशोध!

डीके एसजेडसी प्रवक्ता गुड्सा उसेंडी द्वारा जारी प्रैस स्टेटमेंट

26 मई 2013 को जन मुक्ति गुरिल्ला सेना की एक टुकड़ी ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के 20 गाड़ियों के काफिले पर भारी हमला कर बस्तर की उत्पीड़ित जनता का जानी दुश्मन महेन्द्र कर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकमार पटेल समेत कुल कम से कम 27 काग्रेंसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस बलों का सफाया कर दिया। यह हमला उस समय किया गया था जब आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के दिग्गज नेता 'परिवर्तन यात्रा' चला रहे थे। इस कार्रवाई में भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री व वरिश्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल समेत कम से कम 30 लोग घायल हो गए। इस ऐतिहासिक हमले में उत्पीड़क, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा और भ्रश्टाचारी के रूप में बदनाम महेन्द्र कर्मा के कुत्ते की मौत मारे जाने से समूचे बस्तर क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। पूर्व में गृहमंत्री के रूप में काम करने वाला नंदकुमार पटेल जनता पर दमनचक्र चलाने में आगे ही रहा था। उसके समय में ही बस्तर क्षेत्र में पहली बार अर्द्धसैनिक बलों (सीआरपीएफ) की तैनाती की गई थी। यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं कि लम्बे समय तक केन्द्रीय मंत्रीमंडल में रहकर गृह विभाग समेत विभिन्न अहम मंत्रालयों को संभालने वाला वी.सी. शुक्ल भी जनता का दुश्मन है जिसने साम्राज्यवादियों, दलाल पूंजीपतियों और जमींदारों के वफादार प्रतिनिधि के रूप में शोशणकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में सक्रिय भागीदारी ली। इस हमले का लक्ष्य मुख्य रूप से महेन्द्र कर्मा तथा कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी कांग्रेस नेताओं का खात्मा करना था। हालांकि इस भारी हमले में जब हमारे गुरिल्ला बलों और सशस्त्र पुलिस बलों के बीच लगभग दो घण्टों तक भीशण गोलीबारी हुई थी उसमें फंसकर कुछ निर्दोश लोगों और निचले स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जो हमारे दुश्मन नहीं थे, की जानें भी गईं। इनकी मृत्यु पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी खेद प्रकट करती है और उनके शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इस हमले की पूर्ण जिम्मेदारी लेती है। इस बहादुराना हमले का नेतृत्व करने वाले पीएलजीए के कमाण्डरों, हमले को सफल बनाने वाले वीरयोद्धाओं, इसे सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग देने वाली जनता और समूची बस्तरिया क्रांतिकारी जनता का दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इस मौके पर क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। इस वीरतापूर्ण हमले से यह सच्चाई फिर एक बार साबित हो गई कि जनता पर अमानवीय हिंसा, जुल्म और कत्लेआम करने वाले फासीवादियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वे कितने बड़े तीसमारखां भी क्यों न हो आखिर जनता के हाथों सजा भुगतनी ही होगी।

आदिवासी नेता कहलाने वाले महेन्द्र कर्मा का ताल्लुक दरअसल एक सामंती मांझी परिवार से रहा। इसका दादा मासा कर्मा था और बाप बोड्डा मांझी था जो अपने समय में जनता के उत्पीड़क और विदेशी शासकों के गुर्गे रहे थे। इसके दादा के जमाने में नवब्याहाता लड़कियों को उसके घर पर भेजने का रिवाज रहा। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका खानदान कितना कुख्यात था। इनका परिवार पूरा बड़े भूस्वामी होने के साथ–साथ आदिवासियों का अमानवीय शोषक व उत्पीड़क रहा। महेन्द्र कर्मा की राजनीतिक जिंदगी की शुरूआत 1975 में एआईएसएफ के सदस्य के रूप में हुई थी जब वह वकालत की पढ़ाई कर रहा था। 1978 में पहली बार भाकपा की तरफ से विधायक बना था। बाद में 1981 में जब उसे भाकपा की टिकट नहीं मिली थी तो कांग्रेस में चला गया। बीच में जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो वह माधवराव सिंधिया द्वारा बनाई गई पार्टी में शामिल होकर 1996 में लोकसभा सदस्य बना था। बाद में फिर कांग्रेस में आ गया। 1996 में बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करने की मों एक बड़ेलन चला था। हालाकि उस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से भाकपा ने किया था, उस समय की हमारी पार्टी भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) ने भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद किया था। लेकिन महेन्द्र कर्मा ने बाहर के इलाकों से आकर बस्तर में डेरा जमाकर करोड़पति बने स्वार्थी शहरी व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उस आंदोलन का पुरजोर विरोध किया था। इस तरह उसी समय उसके

आदिवासी विरोधी व दलाल चरित्र को जनता ने साफ पहचाना था। 1980 के दशक से ही बस्तर के बड़े व्यापारी व पूंजीपति वर्गों से उसके सम्बन्ध मजबूत हुए थे। उसके बाद 1999 में 'मालिक मकबूजा' के नाम से चर्चित एक घोटाले में कर्मा का नाम आया था। 1992–96 के बीच उसने लगभग 56 गांवों में फर्जीवाड़े आदिवासियों की जमीनों को सस्ते में खरीदकर, राजस्व व वन अधिकारियों से सांठगांठ कर उन जमीनों के अंदर मौजूद बेशकीमती पेड़ों को कटवाया था। चोर व्यापारियों को लकड़ी बेचकर महेन्द्र कर्मा ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे, इस बात का खुलासा लोकायुक्त की रिपोर्ट से हुआ था। हालांकि इस पर सीबीआई जांच का आदेश भी हुआ था लेकिन सहज ही दोशियों को सजा नहीं हुई। दलाल पूंजीपतियों और बस्तर के बड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस की ओर से चुनाव जीतने के बाद महेन्द्र कर्मा को अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में जेल मंत्री और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उद्योग मंत्री बनाया गया था। उस समय सरकार ने नगरनार में रोमेल्ट/एनएमडीसी द्वारा प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए जबरिया जमीन अधिग्रहण किया था। स्थानीय जनता ने अपनी जमीनें देने से इनकार करते हुए आंदोलन छेड़ दिया जबकि महेन्द्र कर्मा ने जन विरोधी रवैया अपनाया था। तीखे दमन का प्रयोग कर, जनता के साथ मारपीटकर, फर्जी केसों में जेलों में कैद कर आखिर में जमीनें बलपूर्वक छीन ली गईं जिसमें कर्मा की मुख्य भूमिका रही। नगरनार में जमीनें गंवाने वाली जनता को आज तक न तो मुआवजा मिला, न ही रोजगार मिला जैसे कि सरकार ने वादा किया था। वो सब तितर–बितर हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति महेन्द्र कर्मा शुरू से ही कट्टर दुश्मन रहा। ठेठ सामंती परिवार में पैदा होना और बड़े व्यापारी/पूंजीपति वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में 'बड़ा' होना ही इसका कारण है। क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ 1990–91 में पहला जन जागरण अभियान चलाया गया था। इसमें संशोधनवादी भाकपा ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस प्रति–क्रांतिकारी व जन विरोधी अभियान में कर्मा और उसके कई रिश्तेदारों ने, जो भूस्वामी थे, सक्रिय भाग लिया था। 1997–98 के दूसरे जन जागरण अभियान की महेन्द्र कर्मा ने खुद अगुवाई की थी। उसके गृहग्राम फरसपाल और उसके आसपास के गांवों में शुरू हुआ यह अभियान भैरमगढ़ और कुटरू इलाकों में भी पहुंच चुका था। सैकड़ों लोगों को पकड़कर, मारपीट करके जेल भेज दिया गया था। लूटपाट और घरों में आग लगाने की घटनाएं हुईं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। हालांकि हमारी पार्टी और जन संगठनों के नेतृत्व में जनता ने एकजुट होकर इस हमले का जोरदार मुकाबला किया। इससे कम समय के अंदर ही वह अभियान परास्त हो गया था।

उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन और ज्यादा संगठित हो गया। कई इलाकों में सामंतवाद–विरोधी संघर्श तेज हो गए। इसके तहत हुए जन प्रतिरोध में महेन्द्र कर्मा के सगे भाई जमींदार पोदिया पटेल समेत कुछ नजदीकी रिष्तेदार मारे गए थे। गांव–गांव में सामंती ताकतों व दुश्ट मुखियाओं की सत्ता को उखाड़ फेंककर क्रांतिकारी जन राजसत्ता के अंगों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। गांवों में जन विरोधी व सामंती तत्वों से जमीनें छीनकर जनता में बंटवारा करना, अतीत में जारी कबीले के मुखियाओं द्वारा नाजायज जुर्माने वसूले जाने की पद्धति को बंद कर जनता का जनवादी शासन को शुरू करना कट्टर सामंती अहंकार से सराबोर महेन्द्र कर्मा को बिल्कुल रास नहीं आया। महिलाओं की जबरिया शादियां करवाने पर रोक, बहुपत्नीत्व आदि रिवाजों को हतोत्सहित करना आदि प्रगतिशील बदलाव भी सामंती ताकतों के गले नहीं उतरे। उसी समय बस्तर क्षेत्र में भारी परियोजनाएं शुरू कर यहां की जनता को बड़े पैमाने पर विस्थापित कर यहां की प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन करने की मंशा से उतरे टाटा, एस्सार जैसे कार्पोरेट घरानों के लिए भी यहां का विकासशील क्रांतिकारी आंदोलन आंखों की किरकिरी बना था। इसलिए उन्होंने सहज ही महेन्द्र कर्मा जैसी प्रतिक्रांतिकारी ताकतों से सांठगांठ कर ली। उन्हें करोड़ों रुपए की दलाली खिला दी ताकि अपनी मनमानी लूटखसोट के लिए माकूल माहौल बनाया जा सके। दूसरी ओर, देश भर में सच्चे क्रांतिकारी संगठनों के बीच हुए विलय के बाद एक संगठित पार्टी के रूप में भाकपा (माओवादी) के आविर्भाव की पृश्ठभूमि में उसे कुचल देने के लिए शोषक शासक वर्गों ने अपने साम्राज्यवादी आकाओं के इशारों पर प्रतिक्रांतिकारी हमला तेज कर दिया। अपनी एलआईसी नीति के तहत महेन्द्र कर्मा जैसी कट्टर प्रतिक्रांतिकारी ताकतों को आगे करते हुए एक फासीवादी हमले की साजिश रचाई। इस तरह, कांग्रेस और भाजपा की सांठगांठ से एक बर्बरतापूर्ण हमला शुरू कर दिया गया जिसे 'सलवा जुडुम' नाम दिया गया। रमन सिंह और महेन्द्र कर्मा के बीच कितना बढ़िया तालमेल रहा इसे समझने के लिए एक तथ्य काफी है कि मीडिया में कर्मा को रमन मंत्रीमण्डल का 'सोलहवां मंत्री' कहा जाने लगा था। सोयम मूका, रामभुवन कुशवाहा, अजयसिंह, विक्रम मण्डावी, गन्नू पटेल, मधुकरराव, गोटा चिन्ना, आदि महेन्द्र कर्मा के करीबी और रिश्तेदार सलवा जुडूम के अहम नेता बनकर उभरे थे। साथ ही, उसके

बेटे और अन्य करीबी रिश्तेदार ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायत तक के सभी स्थानीय पदों पर कब्जा करके गुण्डागर्दी वाली राजनीति करते हुए, सरकारी पैसों का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए कार्पोरेट कम्पनियों और बड़े व्यापारियों का हित पोशण कर रहे हैं।

और सलवा जुडूम ने बस्तर के जन जीवन में जो तबाही मचाई और जो क्रूरता बरती उसकी तुलना में इतिहास में बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। कुल एक हजार से ज्यादा लोगों की हत्या कर, 640 गांवों को कब्रगाह में तब्दील कर, हजारों घरों को लूट कर, मुर्गों, बकरों, सुअरों आदि को खाकर और लूटकर, दो लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर, 50 हजार से ज्यादा लोगों को बलपूर्वक 'राहत' शिविरों में घसीटकर सलवा जुडूम जनता के लिए अभिशाप बना था। सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कई महिलाओं की बलाात्कार के बाद हत्या कर दी गई। कई जगहों पर सामूहिक हत्याकाण्ड किए गए। हत्या के 500, बलात्कार के 99 और घर जलाने के 103 मामले सर्वोच्च अदालत में दर्ज हैं तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन अपराधों की वास्तविक संख्या कितनी ज्यादा होगी। सलवा जुडूम के गुण्डा गिरोहों, खासकर पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों, नगा और मिज़ो बटालियनों ने जनता पर जो कहर बरपाया और जो जुल्म किए उसकी कोई सीमा नहीं रही। ऐसी कई घटनाएं हुईं जिसमें लोगों को निर्ममता के साथ टुकड़ों–टुकड़ों में काटकर नदियों में फेंक दिया गया। चेरली, कोत्रापाल, मनकेली, कर्रेमरका, मोसला, मुण्डेर, पदेड़ा, परालनार, पूंबाड़, गगनपल्लीकृ ऐसे कई गांवों में लोगों की सामूहिक रूप से हत्याएं की गईं। सैकड़ों आदिवासी युवकों को एसपीओ बनाकर उन्हें कट्टर अपराधियों में तब्दील कर दिया गया। महेन्द्र कर्मा ने खुद कई गांवों में सभाओं और पदयात्राओं के नाम से हमलों की अगुवाई की। कई महिलाओं पर अपने पशु बलों को उकसाकर बलात्कार करवाने की दरिंदगी भरे उसके इतिहास को कोई भुला नहीं सकता। जो गांव समर्पण नहीं करता उसे जलाकर राख कर देने, जो पकड़ में आता है उसे अमानवीय यातनाएं देने और हत्या करने की कई घटनाओं में कर्मा ने खुद भाग लिया था। इस तरह महेन्द्र कर्मा बस्तर की जनता के दिलोदिमाग में एक अमानुश हत्यारा, बलात्कारी, डकैत और बड़े पूंजीपतियों के वफादार दलाल के रूप में अंकित हुआ था। पूरे बस्तर में जनता कई सालों से हमारी पार्टी और पीएलजीए से मांग करती रही कि उसे दण्डित किया जाए। कई लोग उसका सफाया करने में सक्रिय सहयोग देने के लिए स्वैच्छिक रूप से आगे आए थे। कुछ कोशिशें हुई भी थीं लेकिन छोटी–छोटी गलतियों और अन्य कारणों से वह बचता रहा। आखिरकार, कल, जनता के सक्रिय सहयोग से किए गए इस बहादुराना हमले में हमारी पीएलजीए ने महेन्द्र कर्मा का सफाया कर बस्तर की जनता को बेहद राहत पहुंचाई।

इस कार्रवाई के जरिए हमने उन एक हजार से ज्यादा आदिवासियों की ओर से बदला ले लिया जिनकी सलवा जुडूम के गुण्डों और सरकारी सशस्त्र बलों के हाथों हत्या हुई थी। हम उन सैकड़ों मां–बहनों की ओर से बदला ले लिया जो बेहद अमावीय हिंसा, अपमान और अत्याचारों का शिकार हुई थीं। हम उन हजारों बस्तरवासियों की ओर से बदला ले लिया जो अपने घरों, मवेशियों, मुर्गों–बकरों, गंजी–बर्तनों, कपड़ों, अनाज, फसलोंकृ सब कुछ गंवाकर ठहरने की छांव तक छिन जाने से घोर बदहाली झेलने पर मजबूर कर दिए गए थे। घरबार गंवाकर, टिककर रहने तक की जगह के अभाव में, इस अनभिज्ञता से कि अपने प्रियजनों में कौन जिंदा बचा है और कौन खत्म हो गया, बदहवास तितर–बितर हुए तमाम लोगों के गुस्से और आवेश को एक न्यायोचित और आवश्यक अभिव्यक्ति देते हुए हमने महेन्द्र कर्मा का सफाया कर दिया।

इस हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंग सहित सभी ने इसे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथसिंह इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह आह्वान किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको मिलजुलकर नक्सलवाद और आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। हम पूछते हैं कि क्या शोषक वर्गों के इन पालतू कुत्तों को लोकतंत्र का नाम तक लेने की नैतिक योग्यता है। अभी–अभी, 17 मई को बीजापुर जिले के एड़समेट्टा गांव में तीन मासूमों समेत आठ लोगों की जब पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने हत्या की तब क्या इनको 'लोकतंत्र' की याद नहीं आई? जिस काण्ड को खुद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी मजबूरन 'नरसंहार' बताना पड़ा था, उस पर इन नेंताओं के मुंह पर ताले क्यालग गए थे? 1 मई को नारायणपुर जिले के मड़ोहनार गांव के फूलसिंह और जयसिंह नामक दो आदिवासी भाइयों को पुलिस थाना बुलाकर हरी वद्रियां पहनाकर गोली मारकर जब 'मुठभेड़' की घोशणा की गई थी तब क्या इनका 'लोकतंत्र' खुश था? 20–23 जनवरी के बीच बीजापुर जिले के पिड़िया और दोड्डि तुमनार गांवों पर हमले कर 20 घरों में आग लगाकर, जनता द्वारा संचालित स्कूल तक को जला देने पर क्या इनका 'लोकतंत्र' फलता–फूलता रहा? 6–9 फरवरी के बीच अबूझमाड़े कहलाने वाले बहद पिछड़े आदिवासी इलाके के गरीब माड़िया लोगों का गांव गट्टाकाल पर जब सरकारी सशस्त्र

बलों ने हमला कर, घरों को लूटकर, जनता के साथ मारपीट कर, गांव में क्रांतिकारी जनताना सरकार द्वारा संचालित स्कूल को जलाकर राख कर दिया था तब इनका 'लोकतंत्र' क्या कर रहा था? आज से ठीक 11 महीने पहले 28 जून 2012 की रात में सारकिनगुड़ा में 17 आदिवासियों के खून की होली खेलना और 13 युवतियों के साथ बलात्कार करना क्या 'लोकतंत्रिक मूल्यों' का हिस्सा था? क्या यह लोकतंत्र महेन्द्र कर्मा जैसे हत्यारों और नंदकुमार पटेल जैसे शोषक शासक वर्गों के गुर्गों पर ही लागू होता है? बस्तर के गरीब आदिवासियों, बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं पर लागू नहीं होता? उनका चाहे कितनी बड़ी संख्या में, चाहे कितनी ही बार कत्लेआम करना क्या 'लोकतंत्र' का हिस्सा ही था? क्या इन सवालों का जवाब उन लोगों के पास है जो इस हमले पर हाय तौबा मचा रहे हैं?

2005 से 2007 तक चला सलवा जुडूम जनता के प्रतिरोध से पराजित हो गया। उसके बाद 2009 में कांग्रेस–नीत यूपीए–2 सरकार ने देशव्यापी हमले के रूप में आपरेशन ग्रीनहंट की शुरूआत की। इसके लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी न सिर्फ मार्गदर्शन और मदद व सहयोग दे रहे हैं, बल्कि अपने स्पेशल फोर्स को तैनात करके काउण्टर इंसर्जेन्सी आपरेशन्स का संचालन करवा रहे हैं। खासकर माओवादी नेतृत्व की हत्या करने पर उनका जोर है। आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से 'जनता पर जारी युद्ध' के अंतर्गत कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने अभी तक 50 हजार से ज्यादा अर्द्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ में भेज दिए। इसके फलस्वरूप नरसंहारों और तबाही में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई। अब तक 400 से ज्यादा आदिवासियों को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए सशस्त्र पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने मार डाला। 2011 के मध्य से यहां पर प्रशिक्षण के नाम से सैन्य बलों की तैनाती शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के अलावा पहले चिदम्बरम और शिंदे दोनों ही रमनसिंह द्वारा चलाए जा रहे हमले से खुश होकर लगातार वादे पर वादे कर रहे हैं कि मुंहमांगी सहायता दी जाएगी। रमनसिंह भी केन्द्र से मिल रही मदद पर तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन के दमन की नीतियों के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ जनता के दबाव में और साथ ही, चुनावी फायदों के मद्देनजर कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने सारकिनगुड़ा, एड़समेट्टा जैसे नरसंहारों का खण्डन करने का दिखावा किया। जबकि उसमें ईमानदारी बिल्कुल अभाव है। राज्य में रमनसिंह द्वारा लागू जन विरोधी और कार्पोरेट अनुकूल नीतियों के प्रति और दमनात्मक नीतियों के प्रति कांग्रेस को कोई विरोध नहीं है। वह विरोध का महज दिखावा कर रही है जो अवसरवाद के अलावा कुछ नहीं है। दमन की नीतियों को लागू करने में इन दोनों पार्टियों की समान भागीदारी है। इतना ही नहीं, आंध्रप्रदेश से ग्रेहाउण्ड्स बलों का बार–बार छत्तीसगढ की सीमा के अंदर घुसना और पहले कंचाल (2008) और अभी–अभी पुव्वर्ति (16 मई 2013) में भारी हत्याकाण्डों को अंजाम देना भी कांग्रेस द्वारा लागू दमनात्मक नीतियों का ही हिस्सा है। इसीलिए हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया।

आज दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ खड़े हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, गृहमंत्री ननकीराम कंवर, मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, विक्रम उसेण्डी, राज्यपाल शेखर दत्त, महाराश्ट्र गृहमंत्री आर.आर. पाटिल आदि; डीजीपी रामनिवास, एडीजी मुकेश गुप्ता जैसे पुलिस के आला अधिकारी इस गफलत में हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महेन्द्र कर्मा ने भी इस भ्रम को पाल रखा था कि जड प्लस सेक्यूरिटी और बुलेटप्रूफ गाड़ियां उसे हमेशा बचाएंगी। दुनिया के इतिहास में हिटलर और मुस्सोलिनी भी इसी घमण्ड में थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। हमारे देश के समकालीन इतिहास में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे फासीवादी भी इसी गलतफहमी के शिकार थे। लेकिन जनता अपराजेय है। जनता ही इतिहास का निर्माता है। मुठ्ठी भर लुटेरे और उनके चंद पालतू कुत्ते आखिरकार इतिहास के कूड़ादान में ही फेंक दिए जाएंगे।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मजदूरों, किसानों, छात्र–बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों, मीडियाकर्मियों, तमाम जनवादियों से अपील करती है कि वे सरकारों से मांग करें कि आपरेशन ग्रीनहंट को तत्काल बंद कर दिया जाए; दण्डकारण्य में तैनात सभी किस्म के अर्द्धसैनिक बलों को वापस लिया जाए; प्रशिक्षण के नाम से भारत की सेना को बस्तर में तैनात करने की साजिशों को बंद किया जाए; वायुसेना के हस्तक्षेप को रोक दिया जाए; जेलों में कैद क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और आम आदिवासियों को फौरन व बिना शर्त रिहा किया जाए; यूएपीए, छत्तीसगढ़ विशेश जन सुरक्षा कानून, मकोका, अफस्पा जैसे क्रूर कानूनों को रद्द किया जाए; तथा प्राकृतिक संपदाओं के दोहन की मंशा से विभिन्न कार्पोरेट कम्पनियों के साथ किए गए एमओयू को रद्द किया जाए।

आदर्श कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी अध्यापिका और वीरांगना कामरेड महिता (लक्ष्मी) को जनसंग्राम का लाल सलाम!

29 अप्रैल 2013 के दिन

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने अपनी एक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ महिला नेता को खो दिया। उस दिन कामरेड गड्डम लक्ष्मी ने जानलेवा मलेरिया से ग्रस्त होकर अपने प्राण गंवाए। वह पिछले 32 सालों से देश की मुक्ति के लिए समर्पित होकर दृढ़ता से काम कर रही थीं। उनका ठीक से इलाज कर उन्हें बचाने के लिए साथियों और नेतृत्व की ओर से की गई तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। सबको शोक में डुबोते हुए उन्होंने जनता के बीच ही अंतिम सांस ली। पार्टी कतारों में 'महिता' के नाम से सुपरिचत गड्डम लक्ष्मी अपनी शहादत के समय पार्टी में राज्य स्तरीय नेतृत्वकारी कैडर के रूप में तथा सेंट्रल रीजियन मार्क्सवादी राजनीतिक पाठशाला की अध्यापिका के रूप में दण्डकारण्य, उत्तर तेलंगाना और आंध्र–ओड़िशा बार्डर जोन के क्रांतिकारी संघर्ष में अपना अनमोल योगदान दे रही थीं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी उन्हें पूरी विनम्रता से श्रद्धांजलि पेश करती है। उनके उच्च आदर्शों और अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने की शपथ लेती है। और उनकी मौत की खबर से शोकसंतप्त हुए उनके परिवारजनों, दोस्तों और साथियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है।

महान तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष का मजबूत गढ़ रहा नलगोण्डा जिला, कोदाडा मण्डल के गांव कंदिबण्डा में कामरेड लक्ष्मी का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा–दीक्षा क्रांति का क़िला माने जाने वाले वरंगल जिला में हुआ था। उस समय के आदर्शपूर्ण क्रांतिकारी नेता कामरेड् पुलि अंजन्ना, गोपगानि आइलैया जैसे महान कामरेडों के मार्गदर्शन में उन्होंने रैडिकल छात्र संगठन में काम किया था। उसी क्रम में वह पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में उभरी थीं। कई बार वह पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी की गई थीं। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें उतार–चढ़ावों का सामना करना पड़ा। कई मुश्किलों और नुकसानों के बीच एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लम्बे समय तक उत्तर तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और आंध्र–ओड़िशा बार्डर जोन में कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर खासा अनुभव हासिल किया। छात्र आंदोलन की कार्यकर्ता से शुरू कर विभिन्न तकनीकी और सांगठनिक कार्यों में भाग लेने वाली कामरेड महिता ने पार्टी के विकास में अपने हिस्से का योगदान दिया। 'क्रांति के बिना महिला मुक्ति संभव नहीं और महिला के बिना क्रांति की जीत संभव नहीं' कहकर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में महिला मोर्चे के विकास के लिए विशेष योगदान किया। पार्टी द्वारा जारी महिला परिप्रेक्ष्य को उन्होंने कैडरों को पढ़ाया, बल्कि उसे समृद्ध बनाने में भी उनका योगदान रहा।

2008 के आखिर से कामरेड महिता का जीवन दण्डकारण्य संघर्ष से जुड़ गया। पार्टी को सैद्धांतिक व राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के महान लक्ष्य के अंतर्गत उन्होंने मार्क्सवादी शिक्षण देने वाली अध्यापिका के रूप में दण्डकारण्य में कदम रखा। हालांकि जिम्मेदारियों के अनुसार वह विभिन्न राज्यों का दौरा करती रहीं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उस समय से दण्डकारण्य ही उनका प्रधान कार्यक्षेत्र था। यहां आने के बाद कुछ ही समय में उन्होंने आदिवासी जनता की स्थानीय भाषाओं को सीख लिया। यहां के कार्यकर्ताओं को उन्हीं की भाषा में शिक्षण देती थीं। आम पार्टी सदस्यों को, एरिया कमेटी से लेकर राज्य स्तर के कार्यकर्तों को उन्होंने कई बार राजनीतिक कक्षाओं में शिक्षण दिया। राजनीतिक अर्थशास्त्र, पार्टी इतिहास, भारत की नई जनवादी क्रांति, महिला परिप्रेक्ष्य आदि कई विषयो सुंचारू रूप से वह क्लास लेती थी। कई कार्यकर्ताओं को राजनीतिक व सैद्धांतिक शिक्षण देने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर उन्होंने दण्डकारण्य के क्रांतिकारी संघर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षण के सत्रों के बीच मिलने वाले खाली समय में कामरेड महिता ने दण्डकारण्य के संघर्ष का, खासकर यहां पर विकसित हो रही जन राजसत्ता का नजदीक से अध्ययन करने तथा जमीनी अनुभवों से सीखने का प्रयास किया। सकारात्मक पहलुओं के अलावा, उनकी नजर में आई खामियों और कमजोरियों से भी वह समय–समय पर पार्टी कमेटियों को अवगत करवाती थीं। उन्होंने कई अनमोल सुझाव और निर्माणात्मक विमर्श पेश किए ताकि पार्टी, जनसेना और आंदोलन को मजबूत किया जा सके। अक्टूबर 2011 में आयोजित दण्डकारण्य स्पेशल जोन के प्लीनम में उन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया जिसमें उन्होंने दण्डकारण्य संघर्ष के विकास हेतु अनमोल सुझाव दिए। उन्होंने अपने संदेश में अपनी दिली आकांक्षा व्यक्त की कि दण्डकारण्य का आधार इलाके के रूप में विकास

हो।

महिता एक पढ़ाकू कामरेड थीं। गुरिल्ला जीवन में उपलब्ध कम समय का सदुपयोग करते हुए वह अपनी शिक्षण–क्षमता, विषयों पर पकड़ और समझदारी की व्यापकता को बढ़ाने की कोशिश करती थीं। सभी से घुलमिल जाते हुए सभी का स्नेह जीतने वाली उत्तम कम्युनिस्ट थीं वह। दुबली–पतली और नाजुक स्वास्थ्य का मुकाबला करते हुए ही उन्होंने पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को पूरा करने का दृढ़तापूर्वक प्रयास किया। आज शोषक शासक वर्ग और उनके सेवक पुलिस व खुफिया अधिकारी मीडिया के जरिए यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि 'तमाम माओवादी नेता बीमारियो से ग्रस्त होकर पंगू बन चुके हैं कहकर माओवादी आंदोलन के भविष्य पर जनता के अंदर भ्रम पैदा करके क्रांति की जीत पर अविश्वास फैलाया जाए। लेकिन बढ़ती उम्र और हमेशा पीछा करने वाली अस्वस्थता की परवाह किए बिना, जनता के बीच और जनता के सुरक्षा कवच में रहते हुए आखिरी सांस तक जनता के हितों को ही सर्वोपरि मानते हुए काम कर चुकी महिता जैसी वीरांगनाओं और वीरयोद्धाओं के आदर्शों और उच्च मूल्यों से सशस्त्र हुई पार्टी जन दुश्मनों के सपनों को चकनाचूर करके ही रहेगी। उनके मनोवैज्ञानिक युद्ध को विफल करके रहेगी।

देश की आबादी के 95 प्रतिशत के दुख–तकलीफों और आंसुओं के लिए जिम्मेदार शोषक शासक वर्गों द्वारा जनता के खिलाफ जारी अन्यायपूर्ण युद्ध आपरेशन ग्रीनहंट के चलते आज क्रांतिकारी आंदोलन वाले इलाकों में जनता को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना भी दुष्कर हो गया। ऐसे में क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को समय पर इलाज की सुविधाएं मुहैया करवाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। लुटेरे शासक वर्गों द्वारा अपने हितों के मद्देनजर चलाए जा रहे इस फासीवादी हमले से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के चलते ही कामरेड महिता की मृत्यु हुई। अब महिता हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन महिता और महिता जैसे हजारों शहीदों द्वारा स्थापित क्रांतिकारी आशय के प्रति समर्पित हजारों कार्यकर्ता और लाखों जन समुदाय मौजूद हैं। सामंतवाद, दलाल नौकराशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को दफनाकर भारत की नई जनवादी क्रांति को सफल बनाने, उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद हासिल करने के लिए दृढ़तापूर्वक लड़ना ही उन तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दण्डकारण्य का क्रांतिकारी आंदोलन कामरेड महिता की सेवाओं को सदा याद रखेगा। वह आधार इलाके का अपना लक्ष्य हासिल करके रहेगा जो कामरेड महिता का भी सपना था। जोहार कामरेड महिता!

जनता की लाडली कामरेड सुक्कई अमर रहे! कामरेड सुक्कई के सपनों को पूरा करने पीएलजीए में भर्ती हो!!

कामरेड सुक्कई ओड़िशा राज्य के रायगढ़ जिला के क्लयाणसिंग ब्लॉक के गांव पंचुकूड़ी के निकट 11 सितंबर 2013 को हुए पुलिस हमले में बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपनी शहादत दी।

कामरेड सुक्कई का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिला, ब्लॉक भैरमगढ़ के जांगला गांव में हुआ था। उसके माता–पिता गरीब आदिवासी किसान हैं। कामरेड सुक्कई का गांव उसके जन्म से भी पहले से माओवादी क्रांतिकारी राजनीति से परिचत था। वह बचपन से ही बाल संगठन में शामिल होकर पार्टी के कार्य करने लगी थी। जब वह किशोर अवस्था में पहुंची तो वह चेतना नाट्य मंच की सदस्य बनी। वह एक अच्छी कलाकार कामरेड थी जिसने अपने नाच व गानों के जरिये जनता को माओवादी राजनीति से लैस किया। नाच व गाने के साथ–साथ कामरेड सुक्कई अच्छा भाषण व नाटक भी करती थी। जब 2005 में फासीवादी दमन अभियान सलवा जुडूम शुरू हुआ तो इनके गांव पर भयंकर संकट आ गया। पुलिस, एसपीओ व जुडूम के गुंडो ने इनके गांव पर हमला किया, पूरे गांव को जुडूम शिविर में तब्दील कर दिया था। कुछ महीनों के बाद जब सुक्कई का स्थानीय पार्टी से संपर्क हुआ तो वह तुरंत पार्टी में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की। पुलिस शिविर की जेल को तोड़ कर वह फिर क्रांतिकारी शिविर में आ गयी। सितंबर 2010 में वह पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनी थी। अपने एरिया के दस्ते में उसने 2 महीने ही काम किया। पार्टी ने जब उनके सामने विस्तार के महत्वपूर्ण काम में जाने का प्रस्ताव रखा तो उसने तहेदिल से उसे स्वीकार किया।

छत्तीसगढ़ से क्रांति का परचम उठाये वह ओड़िशा राज्य के नियमगिरी में आयी। यहां आने के बाद स्थानीय कामरेडों की मदत से उसने जल्द ही कूवी भाषा सीख ली थी। वह आसानी के साथ स्थानीय जनता व कामरेडों के साथ घुलमिल जाती थी। वह जनता की अच्छी सेविका थी, जब भी गांव में कोई

मरीज दिख जाता तो वह उसकी सेवा में लग जाती थी, गाव वालों को दवाईयां देती थी।

छोटी सी उम्र में जनता की प्यारी व सेविका कामरेड की शहादत हम सब के लिए बेहद दुखद है। हमें अवश्य ही उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ प्रयास करने चाहिए. कामरेड सुक्कई का सपना था कि उसकी आदिवासी जनता की जल–जंगल–जमीन पर आदिवासी जनता का अधिकार रहे, देश की खनिज संपदा को लूटने वाले बड़े पूंजीपतियो, विदेशी कंपनियों को मार भगाया जाये। देश को आजाद करवा कर जनता की नव जनवादी सत्ता का निर्माण किया जाये। यही सपना लेकर उसने छत्तीसगढ़ से नियमगिरी इलाके में कदम रखा। आज नियमगिरी की जनता को उजाड़ने के लिए वेदांता व उसके दलाल भारत के शासक वर्ग जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। उसके बाप–दादाओं की जमीन का जबरन अधिग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज युवक–युवतियों का कर्तव्य बन जाता है कि कामरेड सुक्कई की तरह अपनी जनता के लिए पीएलजीए में भर्ती हो जायें और अपनी आदिवासी जनता के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ें। 'जनसंग्राम' कामरेड सुक्कई की शहादत को मुठीबांध कर लाल सलाम पेश करती है, और उसके शोकसंतप्त परिजनों, दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है।

कामरेड संतोष को लाल सलाम!

कामरेड आयतु का जन्म दंडकारण्य की दक्षिण बस्तर डिवीजन के बासागुडा एरिया के एक आदिवासी परिवार में हुआ था. 2005 से सलवा जुडूम फासीवादी अभियान ने बस्तर की जनता से जल-जंगल-जमीन पर से अधिकार छीन कर उसे तबाह करने के लिए बेहद दमन ढाहया था. इस दमन के खिलाफ अपने गांव की, फसलों की रक्षा करने के लिए हजारों की संख्या में नौजवान युवक-युवतियां जन मिलिशिया में भर्ती हुए थे. उनमें से कामरेड संतोष भी एक थे. जन मिलिशिया में बहादुरी पूर्वक काम करते हुए उसने पीएलजीए में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा तो उसे भर्ती कर लिया गया. तीन साल दंडकारण्य में उन्होंने काम किया, उसके बाद 2010 में उन्हें विस्तार कार्य के लिए ओड़िशा राज्य भेजा गया.

उसने तहेदिन से इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला और विस्तार कार्य के लिए दृढतापूर्वक कार्य किया.

उसने जल्दी ही यहां आकर ओड़िशा जनता की भाषा को सीख लिया था. गांव में कुछ भी काम होने से वह खुशी के साथ जाते थे और जनता से प्यार से बात करते थे. कामरेड संतोष उभरते हुए नेतृत्व कारी कामरेड थे, उनके काम व योग्यताओं को देख कर जल्द ही वह एरिया स्तर के नेतृत्व में शामिल होने वाले थे.

छत्तीसगढ जन्म लिए कामरेड संतोष ने देश की जनता की मुक्ति के लिए ओड़िशा राज्य के बलांगिर जिले में शहादत का जाम पीया. 25 अगस्त 2013 को पुलिस मुखबिर की सुचना पर आई एसओजी पुलिस के हमले में कामरेड संतोष शहीद हो गए. 'जनसंग्राम' उनकी शहादत को लाल सलाम पेश करती है और उनके सपनों को पूरा करने की शपथ लेती है.

कामरेड धनंजय सदा अमर रहेंगे!

कामरेड रोंडा कोवाची का जन्म छत्तीसगढ राज्य, कोंडा गांव जिला के गांव कोटमेट्टा के एक आदिवासी परिवार में हुए था. माता-पिता की 8 संतानों में से वह 7वें थे. यह गांव दंडकारण्य के पूर्व बस्तर डिवीजन में आता है. 2006 में आंदोलन का विस्तार उनके गांव की तरफ हुआ था. इस प्रकार बचपन से ही कामरेड रोंडा क्रांतिकारी राजनीति से परिचत हो गए थे. उन्होंने बचपन में बाल संगठन में काम किया और बाद में बडे होने के बाद अपने गांव की जनताना सरकार के जन मिलिशिया दल में काम किया. जन मिलिशिया में काम करते हुए वह 2012 जुलाई महीने में पीएलजीए में भर्ती हो गए और पूर्णकाल के लिए जनता के लिए लडने का संकल्प लिया. 2013 में

कुछ समय के लिए उन्होंने पूर्व बस्तर में जिला स्तर के नेतृत्वकारी कामरेड के सुरक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई. उसके बाद उनके सामने जब क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार के लिए बदली का प्रस्ताव रखा तो वह खुशी के साथ ओड़िशा राज्य में आने के लिए तैयार हो गए. उनके लिए पूरे देश की शोषित पीडित जनता अपनी जनता थी. यहां आने के बाद ज्यादा समय नहीं बिता था कि कामरेड रोंडा पुलिस की गस्त के दौरान एक मुठभेड में शहीद हो गए.

कामरेड रोंडा को 'जनसंग्राम' विनम्रतापूर्वक श्रध्दांजली पेश करती है और उसके गांव, परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना प्रकाट करती है.

लोयर सुकतेल बांध निर्माण से विकास नहीं विनाश होगा
जनता का विस्थापन होगा - पर्यावरण का नाश होगा

लोयर सुकतेल को जानने से पहले हमे पश्चिम ओड़िशा में स्थित बलांगीर और बरगढ़ जिलाओं में विस्थापन की समस्याओं को जानना जरुरी है। इन दो जिलों की सीमा में गंदमर्धन पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में स्थित 200 मिलियनटन बाक्साइट खनिज भण्डार को निकालने के इरादे से इस पहाड़ के बलांगीर की तरफ लोयर सुकतेल, लोयर इंदिरा और बरगढ़ की तरफ पुजारीपाली के निकट बांध के निर्माण करने की ओड़िशा सरकार ने योजना बनाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक 1980 के दशक में इनका शिलान्यास भी किया था। तब से ही इन पहाड़ों से बाक्साइट खनिज खुदाई की कोशिश जारी हैं. लेकिन इस अंचल के लोगों के जबर्दस्त प्रतिरोध के चलते तत्काल काम बंद हो गया था। इस नजरिये से ही लोयार सुकतेल को समझना है। उधर पुजारीपाली बांध के निर्माण का काम भी चालू करने की कोशिश जारी हैं। यह तीनों बांधों के साथ बाक्साइट खनिज दोहन का प्रयास भी तेज हो रही हैं। इन तीन बांधों और खदानों से लाखों लोग विस्थापित होने का बड़ा खतरा बनी हुई हैं।

लोयर सुकतेल की जानकारी

गंदमर्धन पहाड़ों से निकले झरनों से मिलकर बनी लोयर सुकतेल नदी पटनागढ़ से होते हुए, बलांगीर शहर के बगल से बहती है। इसी लोयर सुकतेल नदी पर बलांगीर, पटनागढ़ के बीच में बांध के निर्माण की योजना बनाई गई थी। लोगों का प्रतिरोध जब से शिलान्यास हुआ तब से जारी है। इस बांध से 3,981 हेक्टेयर निजी जमीन और 583 हेक्टार जंगल कुल 4,564 हेक्टेयर जमीन डूब जाएगी, प्रभावित कुल 29 गांवों में से 12 गांव पूरी तरह जलमग्न हो जायेंगे। 2009 की एक गणना के अनुसार 9,212 परिवार के 27,636 लोग प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होंगे। अब यह संख्या और बढ़ जायेगी। 1980 में जब इसका शिलान्यास हुआ बांध निर्माण कार्य का जनता की कड़ा विरोध किया जिसके चलते निर्माण कार्य रुक गया था। साम्राज्यवादी, बड़े दलाल पूंजीपतियों की सेवा में समर्पित नवीन पटनायक सरकार ने किसी भी हालात में इस बांध के निर्माण पूरा करने के लिए कमर कसकर 2013 अप्रैल की पहली सप्ताह से फिर से निर्माण कार्य शुरू करवाये। बांध निर्माण कार्य शिघ्र पूरा करने की मांग से बलांगीर शहर के सभी संसदीय पार्टियों के नेताओं, व्यापारी, ठेकेदारों और जमिंदारों जैसे उच्च वर्ग के लोगों मिलाकर बांध के समर्थन में एक एक्शन कमेटी खड़ा करवाई गयी. इस कमेटी की नेतृत्व में अनशन आंदोलन, जिला बंद का भी आयोजन करवाया गया। इस बांध को बलांगीर जिला की जीवन रेखा के रूप में मीडिया के जरिये बढ़ाचढ़ा कर जनता के सामने पेश कर शहरवासियों को गुमराह कर भड़काया जा रहा है।

बांध विरोधी संघर्ष

लोयर सुकतेल बांध से विस्थापित होने वाले परिवारों ने इसके विरोध में संघर्ष समिति का गठन कर अब तक लगातार कई तरीकों से शांतिपूर्वक संघर्ष करते आ रहे हैं। और अभी भी संघर्ष जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधान सभा में बांध निर्माण काम फिर से शुरू करने की घोषणा की और 10 प्लाटूनों की संख्या में पुलिस को तैनात करके अप्रैल की पहली सप्ताह में जबरन काम शुरू करवाया। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने मारपीट कर भागा दियाा इस के बाद पिछे से बुलडोजारों से काम आरम्भ किया गया। कड़ी धूप से धरने पर बैठे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी से लू लगकर एक युवाक शहीद भी हुआ। फिर भी जनता पीछे नहीं हटी। इस बार बांध के विरोध में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी बड़ा संख्या में शामिल हुईं। पुलिस के लाठीचार्ज में कई जन घायल और अरेस्ट हुए उसके बाद जेल से रिहा होते ही फिर से संघर्ष में उतरे। इस इलाका के लोगों को कई वर्षों से सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा हौ यानि शीलान्यास करते ही ही सरकार का सौतेला व्यवहार शुरू हो गया था।

पिछले दो साल से बलांगिर-बरगढ-महासमुंद डिवीजनल कमेटी की ओर से गंदमर्धन बचाओ, पुजारीपाली और लोयर सुकतेल बांध का विरोध करो, इनसे जनता को और पर्यावरण को होनेवाले हानि को पर्चे, बेनरों, पोस्टोरों से प्रचार करते आ रही है। 2013 अप्रैल 23 को लोयर सुकतेल निर्माण कार्य शुरू होने के विरोध में व विस्थापन के विरोध में एक दिन का बलांगीर-बरगढ़-महासमुंद डिवीजन बंद का आव्हान दिया गया। अभी पूरे ओड़िशा राज्य में बलांगीर जिला में सबसे ज्यादा गर्मी यानि 47 डिग्री से ऊपर तक चली जाती है। लाखों लोगों का विस्थापन, जमीन अधिग्रहण, जल, जंगल की दूरपयोग इसी तरह जारी रहने से आनेवाले दिनों में स्थिती और भयानक हो जायेगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है की पश्चिम ओड़िशा का यह अंचल आनेवाले दस-पंद्रह सालों में मरुभूमि में बदल जाएगा। बताया जा रहा है की यह प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। जल-जंगल-जमीन, प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण को बचाने के लिए जनसंघर्ष और तेज करने की जरुरत हैं।

विस्थापन के खिलाफ जन आंदोलन मे कूद पड़ो!

लोकतंत्र की न रमन की - जीत हुई दमन की
चुनावों का बहिष्कार करने वाली बस्तर की जनता को लाल सलाम!

जनता के खून–पसीने की गाढ़ी कमाई के सैकड़ों करोड़ रूपये पानी की तरह बहकर 11 नवंबर और 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का ड्रामा रचा गया। बस्तर तो पहले से ही सैनिक छावनी में बदली किया जा चुका है, पहले से मौजूद 70 हजार से ज्यादा पुलिस–अर्ध सैनिक बलों के अलावा और 650 कंपनियों को चुनाव में उतारा गया। कुल मिलाकर मात्र 19 लाख बस्तरीया वोटरों के लिए डेढ़ लाख के करीब 'सुरक्षा' बलों को उतारा गया यानि 12 वोटरों पर 1 पुलिस वाला। क्या यही लोकतंत्र है, क्या यही जनता की स्वेच्छीक भागीदारी है, कि गर्दन पकड़ कहा जाये लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हो कर मत का दान करो!

10 सालों से बस्तरीया आदिवासी जनता पर कहर बरपा रहे रमन सिंग ने चुनाव जीतते ही इसे विकास की जीत बताया है, चुनाव आयोग ने अपने मुंह मिया मिट्ठू बनते हुए खुद अपनी पीठ थपथपाई कि यह उसके प्रचार और प्रयासों का नतीजा था कि जनता को बड़े पैमाने पर वोट डालने के लिए निकाल पाये और नक्सल प्रभावित इलाके में 77 प्रतिशत तक मतदान करवा पाये। छत्तीसगढ़ पुलिस मुखिया राम निवास ने इसे सुरक्षा बलों की जीत बताया और सभी पुलिस बलों, अर्ध सैनिक बलों को धन्यवाद दिया। दरअसल रामनिवास ही सही कह रहे हैं कि यह पुलिस प्रशासन की जीत है, क्योंकि पूरा चुनाव सरकारी आतंक फैलाकर संगीनों के साये में संपन्न हुआ है। यह पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तानाशाही की ही जीत है। कुछ पत्रकारों और खासकर आकशवाणी ने इसे लोकतंत्र की जीत, बुलेट पर बैलेट की जीत आदि का राग अलापा।

अगर सही मायनों में इन चुनावों को समझा जाये और विश्लेषण किया जाये तो एक ही बात निकाल कर सामने आती है कि जनता ने किसी को भी सरकार बनाने के लिए नहीं चुना, किसी को बहुमत नहीं दिया और यह सारा चुनावी तमाशा अर्ध सैनिक बलों, पुलिस बलों की संगीनों के साये में हुआ है।

छत्तीसगढ़ में कुल मतदान 77 प्रतिशत के करीब हुआ है, बस्तर में केवल 67 प्रतिशत वोट पड़े, और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के लगभग 36 मतदान केंद्रों पर 0 प्रतिशत मतदान हुआ। एक भी मतदाता चुनाव के नाटक में शामिल नहीं हुआ। बीजापुर में मतदान केवल 29 प्रतिशत, कोंटा में 40 प्रतिशत और नारायणपुर के ओर्चा में मात्र 20 प्रतिशत मतदान हुआ। जिन लोगों ने मतदान किया उनमें से भी तकरीबन 10 प्रतिशत लोगों ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया। पूरे छत्तीसगढ़ में नोटा के 4 लाख से ज्यादा वोट पड़े। छत्तीसगढ़ में विधान सभा की कुल सीट 90 हैं, इनमें से 49 सीटों पर भाजपा और 39 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करवाई है। इसके अलावा एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी और एक सीट पर भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े उम्मीद्वार को जीत हासिल हुई

सुर्पीम कोर्ट के आदेश पर देश में पहली बार वोटिंग मशीनों में एनओटीए (नोटा) यानि किसी भी उम्मीद्वार को वोट नहीं का बटन चुनाव आयोग को लगाना पड़ा। दरअसल यह बटन इसलिए लगाया गया ताकि इस लोकतंत्र के नाटक में ऐसे मतदाताओं को भी रिझाने की कोशिश की जाये जो इस लुटेरी व्यवस्था और संसदीय चुनाव से तंग आ चुके हैं और उनका भरोसा उठ चुका है। ऐसे लोगों को मतदान केंद्रों तक लाकार वह इस झूठे लोकतंत्र को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। नोटा बटन केवल एक दिखावा है, यह बिना दांतों का कुत्ता है जो काट ही नहीं सकता, क्योकि नोटा बटन को अगर पचास प्रतिशत भी वोट मिले तो न तो कोई उम्मीद्वार हारता है और न ही चुनाव रद्द होते हैं। यह शक्तिहीन बटन है, जिसका का लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने इस बटन के जरिये भी राजनेताओं व दलाल बुर्जुआ–सामंती पार्टियों को उनकी औकात दिखा दी है। हमारे आंदोलन से प्रभावित विधानसभा सीटों में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। 16 सीटों पर तो स्थिति यह थी कि जितने वोट जीतने वाले उम्मीद्वार को मिले उससे ज्यादा वोट नोटा बटन को मिले और 34 स्थानों पर नोटा तीसरे व 33 स्थानों पर व तीसरे नंबर पर रहा। इस प्रकार देखा जाये तो जो सरकार बनी है वह कहीं से भी बहुमत की सरकार नहीं है। क्योंकि 23 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले ही नहीं, 3 प्रतिशत वोट गए नोटा को, कांग्रेस से बीजेपी को मात्र 1 प्रतिशत वोट ज्यादा मिले हैं, जिससे वह सरकार बनाने में कामयाब हो गयी। कुल मिलाकर देखा जाये तो 26 प्रतिशत सीधे और कांग्रेस, बीएसपी और अन्य उम्मीद्वारों को मिले वोटों का प्रतिशत इसमें जोड़ दिया जाये तो लगभग 70 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं, वह रमन सिंग की सरकार को नहीं चाहते। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र में

किसी बहुमत की सरकार नहीं बनती वह केवल आंकड़ों की बाजीगरी होती है।

इस चुनाव में झूठे प्रचार के लिए ही सही लेकिन किसी भी दल ने जनता के मुद्दों को छुआ तक नहीं। किसानों के चावल को सस्ते दामों पर खरीद कर वापस किसानों को सड़ा–गला कर दे रमन सिंग चाउर बाबा के रूप में प्रसिद्ध होने के चक्कर में रहे तो वहीं कांग्रेस ने जनता के दुश्मन महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल आदि के मारे जाने पर लाशों पर राजनीति कर और जनता को रिझाने की कोशिश की। रमन सिंग ने पिछला चुनाव भी पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के फर्जी वोटों से जीता था तो इस बार भी यही स्थिति रही। वहीं कांग्रेस जनता के मुद्दों को न उठाने से हार का समाना करना पड़ा। वहीं जहां महेंद्र कर्मा की पत्नि हारते हुए बची तो जीरमघाटी में मारे गए उदय मुदलियार की पत्नि अलका मुदलियार व योगेंद्र शर्मा की पत्नि अनिता शर्मा को भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। रमन सिंग के विकास के दावों की पोल तो इससे ही खुल जाता है कि उसके पांच मंत्रियों की जमानत जब्त हो गयी। गृहमंत्री ननकी राम कंवर, बाल–महिला विकास क्लयाण मंत्री लता उसेंडी सहित रामविचार नेताम, हेमचंद यादव व विधानसभा अध्यक्ष व उपअध्यक्ष दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है की सभी मंत्री केवल अपने कोठी–बंगले बनाने पर ही लगे रहे। लगभग आधे पुराने विधायकों को भी हार का सामना करना पड़ा।

बस्तर में दस सालों से हजारों आदिवासियों का कत्ल कर दिया जा चुका है, हजारों घरों को जला कर रख कर दिया गया, सारकेनगुड़ा, एड़समेट्ठा जैसे नरसंहार ने हिटलर की याद दिलाई, सैकड़ों महिलाओं से बलात्कार अर्ध सैनिक बलों, व एसपीओ, पुलिस वालों द्वारा किये गए लेकिन इन लोकतंत्र के ठेकेदारों व तथाकथित जन नेताओं, 'कर्मठ' नेताओं के लिए यह कोई चुनावी मुद्दे नहीं थे। जगह–जगह पुलिस कैंप खोल कर गांवों की संस्कृति का तहस–नहस किया जा रहा है, बड़ी–बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू कर के जनता को उजाड़ा जा रहा है या उजाड़ने की साजिश रची जा रही है, करोड़ों रूपये सरकारी अधिकारियों, सहित रमन सिंग व उसके मंत्रियों ने कई घोटालों में खाए यह भी किसी के लिए चुनावी मुद्दे नहीं थे। कुल मिलाकर देखा जाये तो बस्तर की जनता के मुद्दे इन राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई मुद्दे ही नहीं थे।

'जन संग्राम' बस्तर की बहादुर जनता का चुनाव बहिष्कार कर अपनी खुद की जनताना सरकारों पर भरोसा जताने को क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है। उसने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि झूठे चुनावों से लोकतांत्रिक सरकार नहीं चुनी जाती बल्कि असली सरकार तो उसकी 'भूमकाल–सभाओं' में जनताना सरकार चुनी जाती है जिसमें न केवल वोट डालने का अधिकार है बल्कि गलती करने वालों नेताओं को वापस बुलाने का अधिकार भी इन जनता के पास है।

पीएलजीए के लाल योध्दाओं ने जब्त किये तीन हथियार : दो पुलिस आतंकी खत्म

नुआपाडा जिला में माओवादी पार्टी का समूल नाश करने के लिए ओड़िशा के पुलिस बल सैनिक हमलों के साथ-साथ सीविक एक्शन जैसे कार्यक्रम चला कर कुप्रयास कर रहे हैं. उनके इन कार्यक्रमों को करारा जवाब देने के लिए पीएलजीए के लाल योध्दा कई दिनों से प्रयास कर रहे थे. 29 नवंबर 2013 को पुलिस बल नुआपाडा जिला, ब्लॉक कुमना के गांव डेकुनपानी में सिवीक एक्शन प्रोग्राम के बाद वापस जा रहे थे तब लाल योध्दाओं ने गातीबेडा और डेकुनपानी गांव के बीच तुरंत घात लगाकर हमला किया. 8 मोटर साइकिलों से वापस जा रहे आतंकी बलों के पहले ही मोटरसाईकिल को निशाना बनाया गया. इस हमलें तुरंत ही दो पुलिस आतंकी मिट्टी में मिल गए. वहीं बाकि दुम दबाकार जंगल में छीप गए. पीएलजीए योध्दाओं ने मौका देख एक एके-47, एक इंसास और एक रिव्लवर साहित 4 एके मेगजिन, 95 कारतुस, 4 इंसास मेगजिन व 80 कारतुसों पर कब्जा कर लिया. रिव्लवर के भी 24 कारतुस हाथ लगे. इस हमले के बाद पुलिस वालों में जहां हडकंप मचा है वहीं जनता ने कुछ समय के लिए राहत की सांस ली है. 'जनसंग्राम' जनता के रक्षक पीएलजीए योध्दाओं की ऐसे हमलों के लिए हौंसला अफजाई करती है और आशा करती है की जनता को राहत पहुंचाने व पीएलजीए को मजबूत करने के लिए ऐसे और हमलों को अंजाम देंगे.

जन मुक्ति छापामार सेना द्वारा 2013 में किए गए कुछ मुख्य हमले

- जनवरी 2013 - 9 सीआरपीएफ समेत 1झरखंड जगुआर के आतंकी सुरक्षा बलों के 10 जवानों का एक एंबुश में पीएलजीए ने सफाया कर दिया. यह एंबुश लातेहार जिले के करमातियां के जंगलों में अंजाम दिया गया.
- 22 फरवरी 2013 - पीएलजीए लाल योध्दाओं ने बिहार के गया जिले गांव माझउलिया में एक माईन का विस्फोट किया जिसमें 7 पुलिस वाले मारे गए, जिसमें एक एसपीओ भी शामिल है.
- 4 अप्रैल 2013 - झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के 5 पुलिस वालों का सफाया कर दिया गया. यह घटना गुमला जिले के चैनपुर गांव के बाजार में हुई.
- 12 मई को छत्तीसग्ढ़ के बस्तर में 3 पुलिस वालों को खत्म किया गया.
- 13 जून को बिहार के जमूही जिले में इंटर सीटी एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी में जा रहे पुलिस वालों पर हमला किया गया. इस हमले में तीन जन मारे गए और पीएलजीए ने 1 एके-47 और 2 इंसास राइफलों पर कब्जा कर लिया.
- 2 जुलाई 2013 - जब दुमका जिला का एसपी अमरजीत बलिहार डीआईजी प्रिया दूबे के साथ मीटिंग करके वापस आ रहा था तो काथिकूंड के जंगलों के पास पीएलजीए ने एंबुश लगाकर उसके वाहन को निशाना बनाया. इस एंबुश में एसपी सहित 5 जवान मौके पर ही मारे गए. इसके साथ तीन अन्य घायल भी हुए.
- 17 जुलाई 2013 - 3 स्पेशल आक्जिलिरी पुलिस व रोड़ निर्माण कंपनी के तीन गाडर्स साहित कुल 6 जन को पीएलजीए ने बिहार के औरंगाबा जिले में खतम कर डाला.
- 13 अगस्त 2013 बस्तर के कौशलनगर नगर में पीएलजीए द्वारा किये गए हमले में तीन छत्तीसगढ तीन सशस्त्र पुलिस बल के जवान मारे गए.
- 27 अगस्त 2013 - कोरापुट जिला के हाईवे नं. 26 पर सकिराई व कौगुनथा गांव के बीच किये गए एक बारुदी सुरंग विस्फोट में सिमा सुरक्षा बल के 4 जवानों का खात्मा हुआ.
- 17 अक्तुबर 2013 को महाराष्ट्र के गडचिरोली जिला के बड़े झलिया गांव में पीएलजीए द्वारा लगाये गए बम के विस्फोट होने से 3 सी-60 कमांडो मारे गए व पांच घायल हुए.
- 28 अक्तुबर गडचिरोली जिला एटापल्ली तहसील के गांव हिंदूर में हुई फायरिंग में 1 सी-60 जवान मारा गया, समाचारों में बताया गया है कि दो माओवादी भी मारे गए.
- 11 नवंबर - पहले चरण के विधानसभा चुनावों के दौरान सुकमा जिला के कटेकल्याण ब्लाक केरपाल में किये गए बारुदी सुरंग विस्फोट में 2 सिमा सुरक्षा बलों के जवानों सहित उनका एक वहान चालक भी मारा गया. साथ बीएसएफ का एक डॉक्टर भी घायल हो गया.

छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा चुनाव का बहिष्कार करो।
नवजनवादी क्रांति की सफलता के लिए संगठित हो जाओ।।

प्रिय जनता!

राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी हैं। अगले पांच साल हमे कोन ज्याद लूटे सिर्फ इसी को तय करना है. हमे इस चुनाव के जरिए इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए हमे गुमराह करने आ रहे हैं। भाजपा 'विकास यात्रा' निकाल रही है तो कांग्रेस 'परिवर्तन यात्रा'. इस पर जीरम घाटी हमले के बाद 'बलिदान माटी कल्श यात्रा' के नाम से घूम रहे हैं। आइए इन लोगों से सवाल करें की विकास किसका? जनता का या साम्राज्यवादी बड़े पूंजिपतियों और नेताओं का? बलिदान का मतलब क्या है? गांवों पर हमला करके संपत्ति को लूटना-घरों को जलाना-1000 से ज्यादा लोगों की हत्या करना, दिन दहाड़े घर परिवार के सदस्यों के सामने सैकड़ों महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार, कईयों की हत्या करना ही बलिदान हैं? कर्मा और शोषक वर्गों ने अब तक जनता की ली बलियों के कर्ज चुकाया हैं।

राज्य में पिछले दस सालों से भाजपा के रमनसिंह राज चला रहे हैं। इसके शासन काल में राज्य में तबाही मची हुई है. देश में ही धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य में आज कृषि क्षेत्र के प्रति सरकारों का सौतेले रवैय्ये के चलते सिंचाई व्यवस्था ठप हुई है, प्रकृति का प्रकोप दूसरी तरफ हायब्रीड बीजों, कीटनाशक दवाई और खाद के दामों के वृध्दी से लागत कई गुणा बढ़ गयी है, लेकिन इसको महत्व दिये बगैर ही सरकार तानाशाही तरीके से न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने की जिम्मेदारी से भी पला झाड़ रही है इस से किसान मार्केट के हाथों में फंस कर कर्ज की दलदल में धस गए हैं बैंकों, सहुकारों व्दारा की जाने वाली बेइज्जती के सदमें से खुदकुशियों में राज्य देश में अव्वल नम्बर पर आ गया है। दूसरी तरफ टाटा, रिलायंस, जिंदल, एस्सार जैसे दलाल पूंजिपतियों और बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं, सेजों को, रियल एस्टेटों को, चार-लाइन एक्सप्रेस हाईवे आदि के लिए गरीब किसानों, आदिवासियों से जबरन जमीन हथिया रहे हैं। पिछले दो दशकों से रावघाट परियोजना को वहां की जनता एक आवाज से नकारने के बाद भी हजारों अर्धसैनिक बलों को तैनात करके तेजी से रेल लाइन बिछा रहे हैं ताकि लोह आयस्क आसानी से दोहन कर सकें। इसी तरह लोहंडीगुडा-नगरनार स्टील कारखानों के लिए सरकार जनता के विरोध को दरकिनार करते हुए जबरन जमीन अधिग्रहण पूरा कर रही है। आमदाय मेट्टा, पल्लेमाड़ खदानों के लिए, रायगढ़ के स्टील एवं बिजली संयंत्रों के लिए, भिलाई (दुर्ग) के पास जे.के. सिमेंट कारखाना योजना के खिलाफ जनता संघर्ष की तो इस आंदोलन में नक्सली शामिल होने के नाम से कईयों को गिरफ्तार कर के जेल में डाल दिया गया। साम्राज्यवादियों, दलाल पूंजिपतियों का हित ही देश का हित जैसा प्रचार कर रही है। इन दस सालों में दलाल पूंजिपतियों और राजनीतिक नेताओं की आमदनी में कई गुणा वृध्दि हुई तो गरीब और गरीब बन गये हैं. खदानों, कारखानों के लिए लाखों परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित लोग देशभर में मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। विस्थापन का एक और कारण है सेंचुरियां यानि नेशनलपार्क। बहुराष्ट्रीय व निजी कारखानों, बड़े-बड़े बांधों से हो रही विध्वंस से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के नाम से बड़े जंगल इलाकों को सेंचुरी या रिजर्व फारेस्ट के नाम से घोषणा कर रहे हैं । जहां सीतानदी, उदंती जंगल में टाइगर ही नहीं है सरकार उसे टाइगर सेंचुरी क्यों घोषित किया गया? इतना ही नहीं अब इसे आममोरा तक विस्तार किया जा रहा है। और ओड़िशा के सुनाबेड़ा से जोड़ के इस विशाल इलाके से जनता को विस्थापन करने का केंद्र और राज्य सरकारों का षड़यंत्र है। इस षड़यंत्र के विरोध में जनता आंदोलन कर रही है तो सरकार दमन और घेराव नीति अमल करते हुए कईयों को गिरफतार कर के जेल में डाल रही है। इस जनांदोलन को नेतृत्व कर रही हमारी पार्टी का सफाया करने के लिए ही जोलाराव जंगल में हमारे तीन महिला कामरेडो को 2012 मई माह में हत्या की गयी और इस साल हमारे दस्ते पर तीन बार हमला किया गया। पीढी दर पीढी जंगल में जनता और वन्य प्राणी मिलकर रहते आ रहे हैं अब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जबसे शसक वर्ग का दोहन/ लूट शुरू हुई तबसे ही पर्यावरण का विनाश हो रहा है। राज्य का हर नदी नाले का पानी पूंजिपतियों को मुफ्त में दिया जा रहा है। इन कारखानों से नदी-नालों में छोड़े जानेवाले प्रदूषित पानी से आस-पास के गांवों की सैंकडों जनता जानलेवा बीमारियों का शिकार हो कर अकाल मृत्यू का शिकार हो रहे हैं। इस साल बैलाडिला खदानों से निकलने वाले गंदे पानी के कारण लगभग तीन हजार गाय और बैल मर गये हैं। इससे पता चलता है की सरकारें जनता की जानमाल के नुकसान के प्रति कितना संवेदनशील है।

1990 के दशक से देश में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण को संप्रग सरकार ने 2005 से और तेजी से अमल करना शुरू किया। देश की हर तरह की संपदाओं को खासकर खनिज संपदाओं कोड़ी के मोल साम्राज्यवदियों को बेचने के लिए कई सैकड़ों गुप्त करार कर चुकी है. अब बचेखुचे खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी विदेशी पूंजी घुसपेठ करके गल्ली-मोहल्ले के दुकानदारों को भी बेरोजगार बना कर लगभग पांच करोड़ परिवारों को संकट में धकेल दी है। देश के छोटे-मझोले कारखानों को खनिज, बिजली और दूसरी आपूर्ती में सरकार साम्राज्यवादियों से कई गुना ज्यादा दाम वसूल कर रही है। साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों का 9 सालों तक सभी टैक्स

माफ करने वाली केन्द्र व राज्य सरकारें ज्यादा लोगों को नौकरी प्रदान करने वाले देशी कारखनों से जबरन टैक्स वसूल कर उन्हें बंद होने के कगार पर खड़ा कर दी हौ न सिर्फ देशी पूंजिपतियों को दिवालिया कर रही है, बल्कि उस पर अधारित लगभग आठ करोड़ कामगारों को भी बेरोजगार बना रही है।

आज राज्य में इन जनविरोधी, विस्थापन नीतियों का बस्तर की जनता विरोध किया तो 2005 में फासीवादी सलवा जूडूम नामक हमला का शिकार हुई। अब तरह-तरह अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है अभी माओवादियों का सफाया का नाम से सेना ही सीधा उतरा है क्योंकी यहां की एक-एक इंच जगह अनमोल संपदा से भरी हुई है। जनता का प्रतिरोध को खत्म करके शोषित वर्ग झटपट इसे लूटकर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए ही 2011 मार्च में ताडमेटला गांव पर हमला कर 300 घरों को जला कर पूरे गांव को राख कर दिया। 2012 जून में सरकेनगुड़ा गांव पर हमला कर नन्हें बच्चों और तीन छात्रों, महिलाओं सहित 18 लोगों का जनसंहार कर दर्जनों महिलाओं का सामूहिक बलत्कार किया गया था। 2013 मई महीने में एडसमेट्टा गांव पर हमला करके तीन मासूम बच्चों सहित नौ लोगों की हत्या की गयी ताकि जनता में दहशत फैले कि सरकार का विरोध करने से कितना बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। यह सिर्फ बस्तरवासियों का ही नहीं राज्य में हर वर्ग की यही हालत है। बच्चों को शिक्षा देकर संस्कारवान बनानेवाले गुरुजीयों को भूखे पेट सोने को मजबूर कर रही है! न्याय पूर्ण मांगों के लिए आमराण अनशान पर बैठे शिक्षाकर्मिओं और उनके परिजनो के मर पर भी सरकार उनकी मांग नहीं मानी उल्टा बदले की भावना से कई शिक्षाकर्मियों को निलंबित किया गया। हमारे गांव में शराब दुकान, शराब भट्टी नहीं चाहिए का नारा लागते हुए हजारों महिलाएं प्रशासन से शिकायत करने पर भी भट्टी मालिकों से हाथ मिलाए सरकार खुद माफिया बनकर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। दलित एवं आदिवासी लोगों ने अपने हकों के लिए रायपुर में रैली निकालने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पिटा गया, कईयों पर झूठे केस लगाकर जेल में डाला दिया गया!

आज राज्य में फासीवादी शासन चल रहा है। इस फासीवादी दमन को छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून का जामा पहनाते हुए माओवादियों को ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याती प्राप्त समाजसेवक विनायक सेन को भी तीन साल सलाखों का पीछे धकेल दिया गया था. इतना ही नहीं एक तरफा सुनवाई में व्यापारी पियुष गुहा और वरिष्ठ माओवादी नेता नारायण सान्याल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। आदिवासियों का पक्षधर, गांधीवादी हिमांशु कुमार को दंतेवाड़ा से पुलिस ने जबरन भगा दिया, उसके अनुयाई-आदिवासी पत्रकार लिंगाराम कोडापे और सोना सोड़ी (जो सरकारी आश्रम शाला में वार्डन है) दोनों पर नक्सली सहयोगी की मोहर लगाकर दो साल पहले अरेस्ट किया. उनको हिरासत में कई यातनाएं देकर जेल में डालदिया गया। सोनी सोड़ी के उपर लैंगिक अत्याचार कर मानवता की सभी सीमाओं को पार करके वर्दीधारी पुलिस दरिंदों ने उसके गुप्त अंगो में पत्थर घुसाये थे। इस कांड को अंजाम देने वाले एस.पी अंकित गर्ग को राष्ट्रपति के हाथों से उत्तम पुलिस अधिकारी पदक से सन्मानित किया गया। समाजसेवी, पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटेकर, बंधुआ मजदूर विरोधी स्वामी अग्निवेश से सादावर्दीधारी पुलिस और सलवा जुडूम गुंडों ने मिलकर की बदसलूकी के बारे में तो कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ा है। रायगढ़ के रमेश अग्रवाल और पटेल जो विस्थापित और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाये उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। नामी लोगों के साथ ही इतना नइंसाफ हो रहा है तो अंदरुनी इलाकों के आदिवासियों पर क्या गुजर रही होगी इसका आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अंदरुनी इलाकों में जो कोई हाथ लगता हैं छग जनसुरक्षा कानून के तहत केस लगाकर बिना गवाह एकतरफा सुनवाइयों में न्यायधिश सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुना रहे हैं। इससे न्यायपालिका का जन विरोधी रवैया हम समझ सकते हैं।

हमारे देश में हो रहे संसदीय चुनाव एक ढकोसला हैं। जनवाद के नाम से जनता को गुमराह कर जनता द्वारा दलाल शोषकों के लिए होने वाली इस चुनाव प्रक्रिया से पिछले सात दशक से केंद्र-राज्यों में सत्ता में आई सभी पार्टी ने जनता के बुनियादि हकों व मैलिक अधिकारों जैसे रोटी-कपड़–मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई आदि समस्याओं का समाधान नहीं किया। चुनाव आते ही कोई एक मुद्दा उछालकर जनता को गुमराह करके चुने जाने के बाद जनता से मुंह मोड़ लेना आम बात हो गयी है। मुख्यमंत्री रमन सिंह पिछले दस सालों से राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों-पूंजीपतियों के लिए चार लाइन हाइवे बनया, उनके लिए बिजली उत्पादन, निजी शिक्षण संस्थाओं - हस्पतालों को बढ़ावा दिया. पूंजिपतियों के आनेजाने के लिए हजारो छोटे किसानों की जमीन छीन कर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कोशिश किया, नई विधान सभा भवन निर्माण करायाा रमन इसको विकास के नाम पर पुरे जोर शोर से प्रचार कर रहा है. जनसंहारों की ट्रेनिंग देने के लिए जंगल वारफेयर कालेज की स्थापना, भाई भतीजावाद, कोलब्लाक आवंटनो में महा घोटालों आदि जनविरोधी कारनामों को छुपाने के लिए गरीबो को चारे के रूप में दो रुपये किलो चावल, अटल आवस (इस में 80 हजार करोड़ का घोटाला किया है), नये-नये मतदाता बने कालेज के छात्र-छात्राओं को छोटी-मोठी टैबलेट-कंप्युटर की आशा दिखाकर वोट एंठने की कोशिश कर रहा है। यह कंप्यूटर न तो नौकरी दिलायेगा न तो पेट भरेगा फिर क्यों? राज्य में 60 फिसदी पढ़े-लिखे लोग (इंजनियर, डिप्लोमा होल्डर) मजदूरी कर रहे हैं। रमन सरकार एक रूपया किलो चावल देने का वादा कर रहे हैं जबकि राज्य में 40 फिसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज गांव में जनता को न पीनेका पानी है, न जमीन के लिए सिंचाई का, न ही कोई मजदूरी. मनरेगा काम तो गरीबों को काम दिलाने के लिए नहीं दलालों, राजनेताओं की जेब भरने के लिए बना गया है। शिक्षा और स्वस्थ तो व्यपार बना दिया गया है। सरकारी दवाखाना तो नाम के वास्ते रह

गया है। गर्मियों में अनशन पर बैठे कई शिक्षाकर्मि मर गये तो भी बदले की भावना से कार्रवाई करनेवाली सरकार चुनाव आते ही कुछ ही लोगों को फयदा होने वाली योजना बनाकर उन लोगों को मस्का लगा रही है। केंद्र में कांग्रेस की युपीए-2 सरकार कुपोशण से ग्रसित देश की दो तिहाई जनता को खाद्य सुरक्षा देने के नाम से एक बिल लायी। खाद्य सुरक्षा एक नाटक है, गरीबी की हंसी उड़ाना है, क्योकि इस योजना के लिए कम से कम 125 लाख करोड़ रुपये चाहिए मगर सिर्फ 10 हजार करोड़ ही बजट में दिए गए है। दूसरी ओर अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले साल सरकार एक लाख टन धान सड़ा कर अपना जनविरोधी चरित्र को जाहिर कर चुकी है। सरकारों को जनता सशक्त बनना रास नहीं आता, लाचार बने रहने से ही आसानी से वोट हासिल कर सकते है। अभी विस्थापित लोगों को ज्यादा रुपये मुआवजा देने का भूअधिग्रहण बिल लाये हैं. दलाल व्यापारी हर विषय को पैसों से ही तोलते हैं. जबकि विस्थापन से भाषा, संस्कृती विलुप्त होने के अलावा कई सामाजिक समस्यएं उत्पन्न होती हैं। शसक शोषक वर्ग को इसकी कोई परवाह नहीं है।

प्यारे किसानों, मजदूरों और जनवादा पसंद बुध्दिजीवियों, नौजवान छात्र-छात्राओं आज देश कठिन दौर से गुजर रहा है। विकास के नाम पर शासक देश और राज्य को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। विकास बहुराष्ट्रीय कंपनियों, दलालों का हो रहा है। साल-दर साल अमीर और गरीबों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले ढाई दशक से बोफोर्स से लेकर कोल ब्लाक आवंटन तक अनगिनत घोटालों को अंजाम देकर खुद की तरक्की के लिए देश को आज 43,81,040 लाख विदेशी कर्ज के दलदल में फसा दिया गया है। रुपये की कीमत डालर की तुलना में अब तक का न्युनतम दर 68.50 रु गिर गया है! क्या यही तरक्की है? मुश्किल से 27 रू रोज कमाने वाला इनसान देश का 3लाख 65 हजार कर्ज कैसा चुकाएगा। सरकारी आंकडों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 40 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे है। मुठ्ठीभर शोषको के लिए रची गयी संसदीय प्रणाली और चुनाव एक ढकोसला है। देश को इस कर्ज के दलदल से व मानसिक दासता से मुक्ती ही एकमात्र विकल्प नवजनवादि क्रंाति है, जो 95 प्रतिशत जनता को रोटी-कपड़ा-मकान के अलावा जोतनेवाले को जमीन, हर हाथ को काम, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी मानती है। अपने राज्य के कई हिस्सों में कई सालों से साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के खिलाफ चल रहे सशस्त्र संग्राम का सफाया करने के लिए चलाये जा रहे आपरेशन ग्रीन हण्ट अभियान का खंडन करके अपने वर्ग भाइयों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो। आओ सड़ी गली इस व्यवस्था को कायम रखने वाले इन चुनावों का बहिष्कार कर के शोषण विहीन समाज की स्थापन के लिए संगठित होकर संघर्ष करें!

- **सड़े गले समाज को सुधरा नहीं जा सकता - उसे नवजनवादी क्रांति के जरिए बदल डालो !**
- **वोटों के जरिए नहीं सशस्त्र संघर्ष के जरिए ही बुनियादी बदलाव संभव है!**
- **झूठे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो !**
- **भारत की नवजनवादी क्रांति जिन्दाबाद!**

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ
भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
ओड़ीशा राज्य कमेटी

माओवादी नेतृत्व और गुरिला दस्तों की हत्या करने की पुलिस साजिश फर्दाफाश

एसपीओ और मुखबिर मेहतर नेताम, रयमान धुर्वे, आशाराम नेताम और पुष्पा कश्यप की मौत के जिम्मेदार हैं

धमतरी जिला एसपी अकबर कोर्राम - गरियाबंद एसपी गोपाल गर्ग

प्रिय जनता !

गरियाबंद जिला मैनपुर ब्लाक जुंगाड़ पुलिस थाना के अतंर्गत बामनी झोला गाँव की पुष्पा कश्यप को जिला पुलिस अधिक्षक ने एसपीओ के रुप में तैयार किया है। गोपनिय तरीका से मुखबिरों को तैयार करने वाली पुष्पा को जुलाई महीने में हमारी पार्टी ने मृत्यु दण्ड दिया है। गारहडी पंचायत सरपंच के पति, नयापारा गांव के निवासी मेहतर नेताम (30-6-2012) को, झोलाराव गांव के गुरूजी रायमान धुर्व (14-8-2012) और धमतरी जिला चेमिंदा गांव के फायर वाचर आशाराम नेताम को (10-6-2012) को हमारी पीएलजीए ने क्यों मृत्यु दण्ड दिया है। इसके बोरे में सभी लोग जानकारी देना जरुरी है।

माओवादी पार्टी नेतृत्व में धमतरी, गरियाबंद जिलों में बढ़ रहे किसान व आदिवासी जन आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपना दमन के आधार को बनाने के लिए सामाजिक नेताओं की गुप्त रुप में मदत की और उनको मुखबिर बनाया है। इन लोगों को और युवकों को एसपीओ बनाने की योजना दी गयी। मेहतर नंदीपारा में पुलिस को खुद लाया और हमारे दस्ते पर फायरिंग करवाया। दिनांक 31 मई 2012 को ग्राम झोलाराव के आस-पास

हमारे दस्ते के ठीकाने का समाचार मुखबिरों ने पुलिस को दिया था। इतना ही पुलिस वालो के साथ खुद आकर हमारे दस्ते के उपर फायरिंग में भी शामिल रहे.

रायमन धुर्वे (गुरुजी) झोलाराव गांव ही का निवासी था. शिक्षाकर्मि के रूप में बच्चों को पढ़ाता था। एक बार मैनपुर में और एक बार गौरगांव में टीआई रमेश मरकाम के साथ बैठक किया। इसके बाद मरकाम ने गुरूजी को मितान बनाकर माओवादी दस्ते को खत्म करने की योजना भी बनाई गयी। इस प्रकार से शिक्षक रायमंन धुर्वे हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए टीआई रमेश मरकाम के मार्गदर्शन में काम किया और इस प्रकार मरकाम ने गुरुजी को बलि का बकरा बनाया ।

मेहतर नेताम को भी इसी प्रकार से मुखबिर बनाया और इलाके में पार्टी के विरोध में खड़े होने की जिम्मेदारी भी दिए। झोलाराव घाटना में मेहतर की भी सक्रिय भागीदारी थी। इन लोगों ने मेहनतकश जिंदगी का रास्ता छोडकर जनांदोलन और माओवादी पार्टी को कुचलने के लिए मुखबिरी के काम को महत्व दिया। मुखबिर बनकर इन लोग कई बार पार्टी का समाचार भेजा था. झोलाराव घाटना के पहले दो-तीन मुठभेड़ हो जानी थी लेकिन हमारे दस्ता की सतर्कता के कारण वे मुठभेड़ें टल गयीं।

आशाराम मुखबिर बनने से पहले पार्टी के साथ अच्छे से मिलजुलकर रहता था। मुखबिर होने के बाद आशाराम ने पार्टी से मिलना बंद करके पार्टी समाचार पुलिस को देना चालू किया। जंगल में पानी मिलने के स्थानों, हमारे डेरा डालने के स्थानों को पुलिस को दिखा चुका था. इस कारण से उसे जन आदलत में सजा भूगतनी पड़ी। जब से वे एसपी अखबर कोराम और नरेन्द्र पुजारी के पैसों के लालच में आकर मुखबिर बने तब से दस्ता कहां रहने कहां भोजन तैयार करेगा आदि समाचार तुरंत पहुंचा रहे थे.

पुष्पा कश्यप बामनी टोला की रहने वाली थी। उनके पिताजी और ताऊ (बड़े पिता) पहले से झुंगाड़ में पुलिस कैंप के लिए जमीन देने को तैयार हुये थे। पुलिस के सामने चलकर लोगों का पत्ता बताते थे। मुखबिर बनकर आस-पास गाँवो में भी मुखबिरों को बनाकर जनांदोलन के विरोधी बन गये थे. बाद में पुष्पा को पुलिस ट्रेनिगं में भेजकर एसपीओ बनाये थे। तब से पुष्पा एसपीओ बनकर अन्य एसपीओं के साथ मिलकर माओवादियों के समाचार जमा कर टीआई और एसपी जैसे अधिकारियों को भेज रही थी।

2011 अगस्त-सितंबर महिनों में जब हमारा दस्ता गाँव गया तो तुरंत फोनकर पुलिस को बुलाई थी। उस दिन पुलिस से मुठभेड़ भी हुआ थी। गोलीबारी में दस्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ. हमारा पार्टी ने जांच की तो पता चला पुष्पा एसपीओ बन गयी है, जिसने समाचार दिया था. इसके उसे गम्भीर चेतावनी देकर छोड दिया था। लेकिन वह बाज नहीं आयी. पुष्पा कश्यप ने मुखबिर तंत्र का विस्तार किया. और 6 गाँवों के मुखबिरों की इंचार्ज बनकर उनके साथ समन्वय के साथ रहती थी। नये मुखबिर तैयार कर उनको एसपीओ में भर्ती भी करवाई थी। पहले से आवारा वाली लड़की पुलिस से वेतन लेकर काम कर रही थी। पुष्पा को जनादालत में लाके विचार किये। पहले जन विरोध तत्व थी अब एसपीओ बनकर 2011 में पुलिस को बुलाकर फायरिंग करवाई, नेटवर्क को तेज कर बहुत गाँवो में मुखबिर नेटवर्क बना कर जनता को गिरफ्तार करवाई इन सब बातों को उसने जनता के सामने कबूल किया। पुलिस से सांठ-गांठ कर जन विरोधी काम करने वाली पुष्पा को जन अदालत ने मौत की सजा सुनाई

प्रिय जनता

जनता ने मेहतर, रायमन धुर्वे, पुष्पा कश्यप, आशाराम इन लोगों को मृत्य दण्ड दिया गया। इनकी मौत की पूरी-पूरी जिम्मेदारी गरियाबंद एसपी गोपाल गर्ग, धमतरी एसपी अकबर कोराम, टीआई नरेन्द्र पुजारी, रमेश मरकाम जैसे पुलसि अधिकारियों की है. जन आन्दोलन और पार्टी नेतृत्व को खत्म करने के लिए रचे षड़यंत्र में शामिल होने की सजा उन मुखबिरों, एसपीओं को मिली है। इसके लिए उपरोक्त अधिकारी ही असली दोषी हैं. आने-वाले समय में जन आन्दोलन और जनता इन पुलिस अधिकारियों को जरूर सजा देगी। पुलिस अधिकारी क्रांतिकारी जन आंदोलन को कुचलने के लिए ग्रीन-हंट सैनिक अभियान चलाने के लिए ग्रामीण इलाको में आवारा और जन विरोधी तत्वों को पैसा और नौकरी का लालच दिखाकर मुखबिर व एसपीओ बना रहे हैं। पुष्पा कश्यप, मेहतर नेताम, रायमन धुर्वे जैसे लोग पैसे और नौकरी का लालच में आकर जनविरोधी रास्ते में गये। एसपीओ बनकर एक हमला होने तक पुलिस ट्रेनिंग होकर गांव में रह कर पुलिस में काम करते रहे। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को जन आंदोलन के खिलाफ हथियार के रुप में इस्तेमाल कर रहा है। गांव-गांव में युवकों को गुरुजी, अंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सामाजिक मुखियाओं को एसपीओ, मुखबिर के रुप में क्रांतिकारी जनांदोलन को रोकने षड़यंत्र में फसा कर बलि का बकरा बना रहा है। जनवाद पंसद

जनता से हमारा अनुरोध है कि पुलिस और प्रशासन बेरोजगार युवाओं को नौकरी और पैसों का लालच दिखाकर जनविरोधी काम करवा रहे है आप पुलिस के इस जाल में नहीं फसना है। बेरोजगार युवाओं और सामाजिक मुखियाओं, कर्मचारी, अंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, गूरुजियों से भी अपील है कि मुखबिर और एसपीओ बनकर पुलिस के खातिर बलि का बकरा मत बनो। इस अवसर पर हमारी पार्टी मैनपुर डिवीजन के गरियाबंद, धमतरी, कांकेर और ओड़िशा के नवरंगपुर जिलों के सभी सामाजिक संगठनो, सदस्यों और कर्मचारी संगठनों से अनुरोध करती है कि आपके संगठनों के सदस्यों को जनविरोधी कर्यों से दूर रखे। पैसों के लालच में पुलिस का साथ दे रहे लोगों को समझा कर उससे बाहर लाने के प्रयास करो ।

आज देश में 90 प्रतिशत शोषित-पीड़ित जनता के हितों के लिए उन के साथ रह कर भाकपा (माओवादी) संघर्ष कर रही है। साम्राज्यवादी, दलाल नौकरशाह पूंजीपति, बड़े सामन्तवादी इन दुश्मनों के विरोध में तमाम मजदूर, किसान, निम्न पूंजापति, राष्ट्रीय पूंजीपति को साथ लेकर संघर्ष जारी है। इस वर्ग संघर्ष को कुचलने के लिए ही साम्राज्यवादियों के इशारों पर देश के दलाल शासक वर्गों ने अपनी ही जनता पर युद्ध चला रखा है। इस युद्ध में शोषक वर्ग कुछ लोगों को गलत राह में ले जा समाजविरोधी बना कर बलि बकरा बना रहे हैं। इस तरह की समाजविरोधी, जनविरोधी नीतियों का समाज के सभी जनवादी प्रेमियों और बुद्धिजीवियों से विरोध करने का हमारा अनुरोध है।

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ
मैनपूर डिवीजनल कमेटी -भाकपा (माओवादी)

सितंबर 2012

सुनाबेड़ा की जनता के मन में भय पैदा कर माओवादी पार्टी से अलग-थलग करने की पुलिस साजिश का पर्दाफाश करो!
माओवादी पार्टी हमेशा जनता की बेहतर जिंदगी के लिए काम करती है. जनता के हित ही हमारे लिए सर्वोपरी हैं!!

प्रिय जनता सुनाबेड़ा इलाके की जनता ने पार्टी को ५ साल पहले स्वागत कर पार्टी के नेतृत्व में संगठित हो कर ३० साल से चल रहे वन विभाग व्दारा जारी शोषण, उत्पीड़न दमन के खिलाफ लड़ कर यहां से उन्हें भगा दिया था। दोबारा फिर वन विभाग की तानाशाही को स्थापित करने के लिए पुलिस कैम्प लगाया गया लेकिन पार्टी के मार्गदर्शन में जनता ने पुलिस का सामाजिक बहिष्कार कर यहां से पुलिस को भागने पर मजबूर किया। इस तरह जनता और पार्टी ने मिलजुल कर कई समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया । इस तरह जनता और पार्टी के बीच संबन्ध दिन ब दिन सुदृढ़ बनने और जनता में शोषण के खिलाफ आई चेतना को देख कर घबरायी सरकार हमारे बीच में दरारे पैदा करने की साजिश कर रही है। इसके मुताबिक रीता दास, सुबल दास जैसे कुछ लोगों को पुलिस ने अपने जाल में फंसाकर उन से पार्टी की मदद करने वालो के ताजा समाचार जुटाना कुछ को अरेस्ट कर दबाव डालना, मुखबीर बनाना, कुछ को पैसा और लालच दिखकर एसपीओ बनाना तथा उन लोगों को पार्टी और जनता के खिलाफ खड़े करना आदि जनविरोधी काम कर रहे हैं। इसी योजना के तहत गुणमनी मेहर, वष्णु मेहर, ब्रीजलाल जैसें लोगों को विशेष पुलिस प्रशिक्षण और इनके हाथों में AK 47 जैसे स्वचालित हथियार दे कर किन को मारना है, किस नेता की हत्या पर कितने लाख रूपये और स्थाई पुलिस की नौकरी मिलेगी आदि समझाकर नुआपाड़ा जिला पुलिस अधिक्षक उमा शंकर दास खुद तैयार कर यहां भेज रहा है। इनके द्वारा पिछले दो सालों से गुप्त रूप से काम करवाते हुए पुलिस अपने मुखबिरी नेटवर्क को बढ़ा रही है।

माओवादी पार्टी की प्रति जनता में नफरत फैलाने और जनता में भय पैदा करने के लिए पुलिस द्वारा प्रतिक्षित ब्रीजलाल ने माओवादी पार्टी के पास लम्बी हिट लिस्ट (मार डालने वालों की लिस्ट) है, जिसमें आम जनता से लेकर सामाजिक प्रमुखों के नाम भी है का कोरा झुठ प्रचार कर रहा है। इसे बढ़ा-चढा कर एसपी दास ने मीडिया को बताया कि माओवादी भूंजीया जाती को मारने की योजना बनाई है इसलिए जनता ने उनके खिलाफ बगावत की है. साथ ही उसने जनता के अनुरोध पर सुनाबेड़ा में पुलिस कैंप लगाये जाने की घोषणा का भी ऐलान किया. लेकिन सच्चाई यह है कि उसके ऑफिस में मुखबिरों के अलावा गांव का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. पुलिस प्रशासन काफी दिनों से यहां कैंप लगाने की कोशिशों में था. जब उनका नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया और उसे अब खतरा हो गया तो ऐसी झूठी कहानी प्रचारित करना शुरू कर रहा है. इस इलाके को अपने कब्जे में कर पुलिस और वन विभाग इस इलाके को सैनिक छावनी में तब्दील कर देना चाहता है, यह एक साजिश के अलावा कुछ नहीं है. यह उनको स्पष्ट पता है कि न हमारे पास कोई हिट लिस्ट है न ही हम किसी जनता को मारना चाहते. ब्रीजलाल को हम सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेकर गए थे, न कि मार डालने के लिए. उनके जनविरोधी कामो का पर्दाफाश करने के लिए जन अदालत में पेश करने के लिए ले जाते समय भागकर वह इस तरह के गलत प्रचार कर रहा है. इस तर की झूठे प्रचार के प्रभाव में आकर कुछ किसानों ने अपनी फसल की रखवाली छोड़ देने के कारण जंगली जानवरों ने फसलों को नष्ट कर दिया. जनता की इस मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान के लिए एसपी उमाशंकर दास के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है.

सोनाबेड़ा के विकास के लिए माओवादी पार्टी आने के बाद ही करोड़ो रूपया मंजूर करने का निर्णय सिर्फ संघर्षरत जनता को गुमराह करने के लिए ही है यह सब को समझ लेना चाहिए. सिर्फ पुलिस के दमन से जन आंदोलन और माओवादी पार्टी का सफाया करना नामुकिन है यह समझकर दमन के साथ झूठे सुधार कार्यकर्मो को जोड़कर करोड़ो रूपयों का आवंटन करके जनता के मन में लालच पैदा करने की साजिश के तौर पर कुछ सामाजिक प्रमुख राजनीतिक नेताओं को पैसा और अधिकार का आशा दिखा रहा है. लंपट व आवारा तत्वों, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर रायगड़ा, गजपति जिलों में शांति सेना, कोरापुट शांति कमेटी आदि के नाम से हत्यारा गिरोहों को तैयार कर रहे हैं. जिस प्रकार दंडकारण्य के बस्तर में सलवा जुडूम के नाम से फासीवादी सैनिक हमला चला कर हजारों जनता को मौत के घाट उतारा गया और उनकी करोड़ों की संपत्ति को नष्ट किया गया, महिलाओं से बलात्कार किये गए वही आज वह सुनाबेड़ा में दोहराना चाहते हैं. मुखबिर नेटवर्क के जरिये माओवादी पार्टी के खिलाफ झूठा प्रचार करके जनता की रक्षा के नाम पर पुलिस कैंप बिठा रहे हैं.

प्रिय साथियो

केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर साम्राज्यवादियों की भूमंडलीकरण योजना के तहत आदिवासी जनता के जंगल, जमीन में मौजूद खनिज संपदा व वन संपदा को लूटने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को उनकी जमीनों से उजाड़ रही है. इस लुटखसोट को रोकने के लिए जनता का नेतृत्व कर रही माओवादी पार्टी को आतंकी व उग्रवादी पार्टी का नाम

देकर उसे खत्म करने के लिए दुष्पचार युध्द के साथ-साथ सैनिक अभियान में चलाया जा रहा है. सुनाबेड़ा में जो घट रहा है वह इसी का परिणाम है.

प्रिय जनता, बुध्दिजीवियो, शिक्षको व छात्र-छात्राओ

पिछले पांच सालों से यहां पार्टी पानी में मछली की तरह जनता के साथ मिलजुल कर जनता के हर का में, उसके हर सुख-दुख में शामिल होते हुए अटूट रिश्ता बनाये हुए है. इस रिश्ते को और सुदृढ और घनिष्ठ बनाने के लिएए हम काम कर रहे हैं. हम गलती या जल्दबाजी से भी जनता का कुछ नुकसान करने की सोच भी नहीं सकते. जन आंदोलन, पार्टी और पार्टी नेतृत्व पर पुलिस खुफिया तंत्र और सरकार मिलकर मीडिया के जरिये गलत, कुटिल व झूठा प्रचार कर रहा है कि माओवादी शिक्षकों को मारते हैं, स्कूल भवनों को बमो से उड़ाकर बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, जनता के साथ मारपीट करते हैं, विकास कामों को रोक रहे हैं, आदिवासी विरोधी हैं आदि अफवाहें फैला रहा है. ऐसे झूठे प्रचारों को आपने पहले भी ठुकराया है, इसी प्रकार आज भी पुलिस के इस झूठे प्रचार को ठुकरा दीजिये.

जनता जब विस्थापन के विरोध में जन आंदोलन में उतरी तो इस दौरान इन पुलिस दरींदों ने कई बार दिन-रात गस्त लगाते हुए लोगों से मारपीट, गिरफ्तारी, गाली-गलौज किया, यहां की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, लाल बंगलों में जूतों के साथ घुसने के कारण कई घरों को लाल बंगलों को छोड़ना पड़ा. जनता के साथ हमने भी इसका विरोध किया.

अपील

हम ग्रामवासियों से अपील करते हैं कि - आपके जो रिश्तेदार, परिजन पुलिस के साथ जनविरोधी कामों में शामिल हो गए हैं उनको समझकर वापस मेहनत व इज्जत की जिंदागी जीने के लिए समझाइये, उनको वापस आपने गांव लाइये. सामाजिक प्रमुखों से अपील है कि रीति-रिवाजों का अपमान करने वाले पुलिस वालों को मदद करने वालों को समझाइये कि सरकार हमारी उगंली से हमारी ही आंख फोड़ने की साजिश रच रही है. इस साजिश से बचकर रहें.

- **पार्टी और जनता के बीच संबंधों को घनिष्ठ बनाए रखें!**
- **अपनी ही उंगली से अपनी ही आंख फुड़वाने वाले सरकारी षड़यंत्र को ध्वस्त करें!**
- **पुलिस कैंप खोलने का विरोध करें!**
- **जनता में फूट डालने वाली सरकार व पुलिसिया साजिश का भांडाफोड़ करें!**
- **निजी स्वार्थ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाने वालों को चिन्हित करें व समझाएं!**
- **पार्टी और जनता एकजुटता व दृढता के साथ विस्थापन के खिलाफ संघर्ष तेज करें!**

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ
भाकपा (माओवादी)
नुआपाड़ा डिवीजनल कमेटी

15 नवंबर 2013

अभियान चलाकर पीएलजीए पर हमले तेज करना है. इसके पार्टी व पीएलजीए के कुछ कमजोर तत्वों को आत्मसर्मपण नीति के जरिये आत्मसर्मण करवाना, साथ ही मानसिक युद्ध को तीव्र कर बार-बार झूठा प्रचार करना आदि है। कुछ रणनीतिक इलके जैसे- सारण्डा, सुकमा, अभी-अभी नियमगिरी, सुनाबेड़ा इलाकों को विशेष पैकेज के नाम से (इस साल नियमगिरी को 300 और सुनाबेड़ा को 240) करोडों आवंटन किया गया हैं। इन पैकेजों को खुद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के प्रत्यक्ष निर्देशन में अमल किया जा रहा है। फिर भी जयराम रमेश ने इन योजनाओं का अमल धीमीगति से होने पर अपनी नाराजगी जताई है। क्योंकि साम्राज्यवादियों की लूट जितना तेजी से आगे बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ रही। इस परिप्रेक्ष में हम केंद्र-राज्य सरकरों की रणनीतिक हमला योजना बनाये जाने को आसानी से समझ सकते हैं।

आज केन्द्र, राज्य सरकारें देश की सार्वजनिक संपदा को वैश्वीकरण के नाम से साम्राज्यवादियों के हाथों सौंपने की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ रही हैं। इसी पॉलसी का नतीजा ही है कि आज देश के बड़े इलाके में जनता को खासकर आदिवासी जनता विस्थापन के लिए मजबूर हो रही है। आजीविका के सभी संसाधनों को छीन लेन वाली इन योजनाओं को माओवादी पार्टी की नेतृत्व में लालगढ़ से सुरजागढ़ तक और छत्तीसगढ़ से लेकर असम तक जनता विस्थापन विरोधी पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक विकास के नमुने को हाथों में ले कर आगे बढ़ रही है। साम्राज्यवाद की प्रतिक्रांतिकारी एलआईसी नीति के तहत जनांदोलन और माओवादी पार्टी को जनविरोधी, आतंकी, विकास विरोधी करार देकर इसे बार-बार दोहराकर झूठा को ही सच साबित करने का एक षड़यंत्रकारी प्रचार छेड़े हुए है। इस षड़यंत्र का ही रुप है आल आउट अभियान यानि माओवादियों पर सुनियोजित हमलों से नेतृत्व का सफाया कर जनांदोलन को दिशाहीन करना। शासक वर्गों की इस कोशिश का विरोध करते हुए जनांदोलन के पक्ष में मजबूती से खड़ा होने के लिए देश के सभी बुध्दिजीवियों, जनवादी एवं प्रगतिशील तत्वों से 'जनसंग्राम' अनुरोध करती हैं।

मुख्यमंत्रियों की बैठक में रची गयी ऑपरेशन आल आउट पुलिस योजना की भर्त्सना करें!

फासीवादी सलवा जुडूम नेता, हत्यारे, सामन्ती दलाल महेन्द्र कर्मा सहित कुछ कांग्रेसी आला नेताओं का 25 मई 2013 को सुकमा जिला दरभा ब्लॉक जीरम घाटी के पास हमारी पीएलजीए द्वारा एक बहादुराना हमला में सफाया कर देने के बाद कांग्रेस सहित वामपंथी कहलाने वाले सुधारवादी और दक्षिणपंथी बीजेपी तक सभी संसदवादी पार्टियों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ मिलजुल कर मुकाबला करने एकमत हो कर हो-हल्ला मचाना शूरु किया. जो इतने दिनों तक लोकतंत्र के नाम पर जनता को फौज के बूट तले दबा कर पर मुंह पर ताला डालके बैठे थे।

हमले की खबर सुनते ही यूपीए चेयरमेन सोनिया गांधी ने यह हमला कांग्रेस पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है, यह लोकतंत्र इतिहास में ही काला दिवस है कहकर अपने दिवालियेपन का परिचय दिया तो प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने वामपंथी उग्रवाद के सफाये के लिए राज्यों की मदद मांगी। 5जनवरी 2013 को दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा विषय पर सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर वामपंथी उग्रवाद को जड़ से सफाया करने के लिए सभी राज्य मिलकर काम करने की जरूरत पर और इसके लिए हर तरह की मदद देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने रखा। शोषक-शासक वर्ग यह अच्छी तरह जानते हैं कि जीरम घाटी हमला फासीवादी सलवा जुडूम और ग्रीनहण्ट सैनिक अभियान का अनिवार्य नतीजा है। अपने कारपोरेट मीडिया के माध्यम से जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। साम्राज्यवादियों द्वारा रची गयी एलआईसी युध्द नीति के तहत 2009 मध्य में आपरेशन ग्रीनहंट की शुरूआत की गयी. यह अभियान साम्राज्यवादियों, बड़े पूंजीपतियों की लूट में बाधा बनी माओवादी पार्टी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया। लोकतंत्र के नाम से जारी दमन, शोषण का जनता ने प्रतिरोध किया तो शोषक-शासक वर्गों और कारपोरेट घरानों के हाथों कैद मीडिया लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए जमीन आसमान को एक करके हाय तौबा मचाकर जनता और खासकर शहरी जनता को गुमराह कर रहा है. जीरम घाटी हमला लोकतंत्र के मूल्यों को बड़ा धक्का करार देकर सोनिया-मनमोहन- चिदम्बरम-शिंदे के तिकड़म गुट ने माओवादियों का सफाया करने का संकल्प दोहराया तो मीडिया ने कई दिनों तक मनगड़ंत कहानियों से क्रांतिकारी आंदोलन पर जहर उगलकर खुद को जनविरोधी धड़े में शामिल कर लिया। केन्द्रीय गृहमंत्री सुशिल कुमार शिंदे ने अपने रायपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृहमंत्री, राज्यपाल के अलावा पुलिस, अर्धसैनिक और मिलटरी आला अधिकारियों से गुप्त बैठक करके एक हमले योजना बनाई. जीरम घाटी हमले को आतंकी हमला करार देकर माओवादियों का सफाये के लिए ज्याईंट आपरेशन (केन्द्र और राज्य के बलों मिलकर सभी राज्यों में एक समय अभियान) योजना पत्रकार सम्मेलन में घोषित किया। विधि विधानों को गुप्त रखने का भी ऐलान_ किया। मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले ही योजना आयोग ने नौ राज्यों के 72 जिलों के लिए 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त बजट की घोषणा की गयी. इस में छत्तीसगढ़ के 10 जिले भी शामिल हैं। इसके साथ जून 3 तारीख तक माओवादी प्रभावित इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में रोड़, मोबाइल टावर, पुलिस थाना निर्माण और सुरक्षा संबंधित दस्तावेजों को तुरंत मंगवा कर तैयार रखने का कहा गया था ताकि सीएमों के बैठक में सुधार प्रोग्रामों पर मोहर लगायी जा सके।

जून 5 को सम्पन्न मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधान मंत्री के अलावा गृह मंत्री और भूतपुर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इनमें माओवादियों के खिलाफ सैनिक हेलिकाप्टरों के इस्तेमाल के लिए नागपुर हवाई अड्डे को तैयार करना, यहां आधुनिक तकनीक से लैस पांच हेलिकाप्टर हमेशा तैयार रखना ताकि हमले के समय बलों की रवानी व पादार्थिक सहयता को प्रभावी ढ़ंग से इस्तेमाल किया जा सके। आन्ध्र की तर्ज पर हर राज्य में खासकर छत्तीसगढ़, ओड़िशा, झारखण्ड, बिहार, बंगाल में विशेष पुलिस बल तैयार करने में होनेवाले खर्च में 80 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार अनुदान देगा तो बाकी 20% राज्य सरकार को उठाना है का प्रस्ताव किया गया तो राज्य सरकारों ने इस पर सहमति जताई है। यह सभी निर्णय अप्रैल महीने में हुई पुलिस अधिकारियों की बैठक में लिए गए। जीरमघाटी हमला के बाद पहले से ही अंदोलन इलाकों में तैनात 3.5 लाख अर्ध सैनिक बलों के अलावा और दस बटालियनों को जनांदोलन को कुचलने के लिए तैनात करने के लिए भी सहमति हुई।

भारत के दलाल शासक वर्ग की केन्द्र राज्य सरकारों ने मिलकर पिछले चार सालों से अपनी ही जनता पर युद्ध छेड़ रखा है। शासकों ने सोचा था कि जनांदोलन को आसानी से कुचल दिया जायेगा और उसके झूठे आर्थिक सुधार लागू हो जायेंगे. लेकिन ठीक इसके उलट हुआ. दमन से जनता में और गुस्सा पैदा हुआ और अभी मजबूरन उन्हें सैकड़ों करोड़ के झूठे सुधार प्रोग्रामों की घोषणा करनी पड़ी। इन आर्थिक सुधारों का लक्ष्य है जनता में से कुछ लोगों को अपने पक्ष में आकर्षित कर पिछड़ी जातियों में अपना सामाजिक आधार बनाना, न कि पूरी जनता का कोई उपकार करना। आवंटित हजारों करोंड़ों की योजनाओं से 75% रुपये रोड़, टावर, स्कूलों के नाम से खर्च कर पुलिस के लिए बड़े-बड़े भवन निर्माण कराना है। योजनाओं के अमल के लिए कार्पेट सेक्युरिटी के नाम से हजारों बलों के कैम्प लगाकर विशाल इलाकों में गश्त, सर्चिंग

बचा हुआ पेज 45 पर देखें...